चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

सुशासन का सच

पेज-3

देश में कितने सिंगुर और बनेंगे

पेज-4

मरती नदियां, उजड़ता बुंदेलखंड

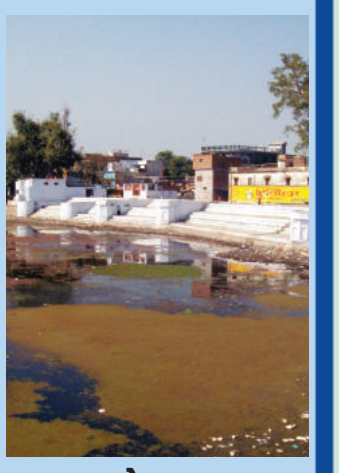

पेज-7

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 27 जून–3 जुलाई 2011 | मूल्य 5 रुपये

अब लोकपाल नहीं बनेगा

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

जिस बात का डर था, वही सच होने जा रहा है. देश में अब एक सशक्त और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने वाला लोकपाल नहीं बनेगा. इसके लिए सरकार, कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां और अन्ना हज़ारे ज़िम्मेदार हैं. इन सब से ग़लतियां हुई हैं. ऐसी ग़लतियां जिसे देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी. लोकपाल के नाम पर देश में जो राजनीतिक वातावरण बना है वह बॉक्सिंग से कम नहीं है. जिसे जहां मौक़ा मिलता है, पंच मार कर देता है. कांग्रेस अन्ना हज़ारे को कभी आरएसएस का एजेंट बताती है तो कभी तानाशाह. अन्ना हज़ारे और उनके सहयोगी सरकार को धोखेबाज़ और झूठा बताते हैं. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अलग तू-तू, मैं-मैं चल रही है. देश की जनता भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म होते देखना चाहती है. अफ़सोस इस बात का है कि यह मूल मुद्दा ही इन लोगों के एजेंडे में नहीं है. ये सब होशियार लोग हैं. ये कालीदास नहीं हैं कि जिस डाल पर बैठे हैं उसे ही काटने लग जाएं.

मनीष कुमार

हमारे देश में सरकारी तंत्र के साथ साथ भ्रष्टाचार का तंत्र भी मौजूद है. यह भ्रष्ट तंत्र देश की जनता को तो नज़र आता है, लेकिन सरकार अंधी हो चुकी है. इसलिए सरकारी तंत्र और भ्रष्ट तंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं. ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो सरकार के नियम क़ानून हैं, जिसके ज़रिए आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता. आप शुमाकर क्यों न हों, उस टेस्ट को पास ही नहीं कर सकते. लाइसेंस के लिए भ्रष्ट तंत्र मौजूद है. घूस खिलाइए, लाइसेंस आपके घर पर पहुंच जाएगा. रेलवे में आरक्षण करवाना हो तो लाइन में आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन सीट नहीं मिलेगी, तत्काल सेवा में भी नहीं. टिकट दलालों को पकड़िए, आपके नाम के साथ टिकट उपलब्ध हो जाएगा. आप सरकार के किसी भी विभाग में जाइए, वहां दो तरह से काम कराए जा सकते हैं. एक सरकार द्वारा बनाया गया क़ायदा क़ानून है और दूसरा रिश्वत देकर वहीं काम कराने का एक और तरीक़ा मौजूद है. देश की जनता का इससे रोज़ाना सामना होता है, इसलिए लोग नाराज़ हैं. सरकार के अधिकारी, नेता, उद्योगपति और वे सारे लोग जो आम आदमी नहीं हैं, इस भ्रष्ट तंत्र के पोषक, वाहक, ग्राहक और उस पर पोषित हैं. कोई भी राजनीतिक दल या सरकार इस भ्रष्ट तंत्र को ख़त्म नहीं करेगी, क्योंकि यही उनकी जीविका का आधार है, यही उनकी लाइफ लाइन है. यहीं से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसे मिलते हैं. सत्ता का हर हिस्सेदार व्यक्ति या संस्थान इस यथास्थिति को बरक़रार रखना चाहता है. हमारे देश का भ्रष्ट तंत्र इतना मज़बूत है कि प्रजातंत्र का ब्रह्मास्त्र भी इस पर कोई असर नहीं छोड़ पाता है. देश की जनता ने कई भ्रष्ट सरकारों को सत्ता से बाहर तो किया, लेकिन भ्रष्टाचार की सत्ता को ख़त्म नहीं कर सकी. मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं कि वे सरकार के समानांतर कोई ढांचा खड़ा नहीं कर सकते. समझने वाली बात यह है कि मंत्री जी को सिविल सोसायटी के लोग समानांतर ढांचा खड़ा करते नज़र आते हैं, लेकिन देश में पहले से ही भ्रष्टाचार का जो समानांतर ढांचा खड़ा है, वह उन्हें नज़र नहीं आता. इसे ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? देश के ढाई सौ से ज़्यादा ज़िलों में नक्सलियों की समानांतर सरकार चल रही है, उसके बारे में सरकार के पास क्या जवाब है?

लोकपाल का क़ानून बनाना सरकार की ज़िम्मेदारी है. सरकार का कहना है कि 30 जून तक सख्त लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार हो जाएगा. लेकिन सरकार और उनके मंत्रियों का जो रवैया है उससे यही लगता है कि वे लोकपाल तो बनाना चाहते हैं, मगर वह मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और महिला आयोग के अध्यक्ष की तरह दंतहीन, विषहीन लोकपाल बनाना चाहते हैं. जो प्रधानमंत्री, जजों, बड़े अधिकारियों और सांसदों को भ्रष्टाचार में लिप्त होते तो देख सकता है, लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. आज सरकार और कांग्रेस पार्टी कठघरे में खड़ी दिखाई पड़ती है. यही वजह है कि अन्ना हज़ारे ने फिर से अनशन का ऐलान किया है. यह बेहद अफ़सोसजनक स्थिति है कि जनता की नज़रों में सरकार और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की समर्थक बन गई है. वजह भी साफ़ है, पिछले एक साल से घोटालों के सामने आने का जो दौर शुरू हुआ है वह थमता दिख नहीं रहा है. सुप्रीम कोर्ट की वजह से यूपीए के दूरसंचार मंत्री ए राजा जेल में हैं. गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक के नेता करुणानिधि की बेटी कनीमोई जेल में है. कांग्रेस पार्टी के नेता और कॉमनवेल्थ महालूट के अधिनायक कलमाड़ी जेल में हैं. जो भी जांच रिपोर्ट आ रही है उसमें सरकार और कांग्रेस के लोगों का नाम आ रहा है. एक तरफ़ रामदेव और अन्ना हज़ारे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं. लोकपाल पर बहस हो रही है, इस बीच यूपीए के दूसरे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं. कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन पर तलवार लटक रही है. भारतीय जनता पार्टी अब होम मिनिस्टर पर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पैसे लेने का आरोप लगा रही है और पी. चिदंबरम का इस्तीफ़ा मांग रही है. इन सबके बीच सरकार और कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई सारी दलीलें बेमानी लगती हैं. जनता का विश्वास उठ गया है.

लोकपाल को लेकर सिविल सोसायटी और सरकार के बीच प्रधानमंत्री के नाम पर गुत्थम-गुत्थी हो रही है. सिविल सोसायटी प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाना चाहती है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि इसके ख़िलाफ़ हैं. इससे कई सवाल खड़े होते हैं. प्रणब मुखर्जी एनडीए सरकार के दौरान लोकपाल बिल बनाने वाली कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे. उन्होंने जो बिल तैयार किया, उसमें प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में रखा. उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. उन्होंने भी आपत्ति दर्ज नहीं की. अब ऐसी क्या बात हो गई कि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से अलग रखना चाहते हैं. इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को देश की जनता को देना चाहिए. पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे काम किए हैं, जिससे सरकार की दलीलें कमज़ोर हो गई हैं. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले का मामला जब सामने आया तो प्रधानमंत्री ने ए राजा को मंत्रिमंडल से बर्ख़ास्त करने के बजाए उनका बचाव किया था. फिर सीवीसी की नियुक्ति के मामले में भी मनमोहन सिंह का रुख़ कई सवालों को खड़ा करता है. सीवीसी को नियुक्त करने वाली कमेटी में तीन सदस्य होते हैं. प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष. पी जे थॉमस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे. सीवीसी के लिए तीन नाम थे. लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने पी जे थॉमस के नाम पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने यह कहा था कि पी जे थॉमस के अलावा किसी को भी चीफ़ विजिलेंस कमिश्नर बनाया जा सकता है. इस आपत्ति को दरकिनार करके मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम ने पी जे थॉमस को सीवीसी बना दिया. क्या इसमें प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है. फिर इसरो का केस सामने आया. इसरो ने एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियम क़ानून तोड़ डाले. प्रधानमंत्री पर एक नया सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि इसरो प्रधानमंत्री के पास है. इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, यह किसी को पता नहीं है. कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर मची लूट पर भी सरकार ने कुछ

(शेष पृष्ठ 2 पर)

लोकपाल का क़ानून बनाना सरकार की ज़िम्मेदारी है. सरकार के मुताबिक़ 30 जून तक सख्त लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार हो जाएगा. लेकिन उसके रवैये से यही लगता है कि वे लोकपाल तो बनाना चाहते हैं, मगर उसे मानवाधिकार और महिला आयोग के अध्यक्ष की तरह दंतहीन, विषहीन लोकपाल बनाना चाहते हैं. जो प्रधानमंत्री, जजों, बड़े अधिकारियों और सांसदों को भ्रष्टाचार में लिप्त होते तो देख सकता है, लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. आज सरकार और कांग्रेस पार्टी कठघरे में खड़ी दिखाई पड़ती है.

जिस देश में संसद सदस्य पैसे लेकर सवाल पूछते हों. समर्थन के लिए जहां विधायकों और सांसदों की ख़रीद-फ़रोख्त होती हो. जहां पैसे देकर लोकसभा में समर्थन ख़रीदा जाता हो, गठबंधन सरकार बनाने के नाम पर ब्लैकमेलिंग और सौदेबाज़ी होती हो, जहां नीरा राडिया जैसी मीडिया मैनेजर यह तय करती हो कि मंत्री कौन बनेगा तो उस देश के मंत्री को संसदीय लोकतंत्र की दुहाई देने का क्या अधिकार है?

अजीत सेठ को नया कैबिनेट सचिव और सुनील मित्रा को नया वित्त सचिव बनाए जाने के बाद बहुत से बाबू अब इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि आगे की नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर ही की जाएंगी.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बेदाग़ अधिकारी चाहिए

फ़िलहाल, सरकार अभी अपना ध्यान पूरी तरह से कैबिनेट में किए जाने वाले फेरबदल के अलावा अन्ना हज़ारे और रामदेव के आंदोलन से भड़की आग को बुझाने पर केंद्रित कर रही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से काम प्रतीक्षा सूची में हैं, जिन्हें जल्दी से जल्दी यानी कुछ ही हफ्तों के भीतर किया जाना है. बाबूशाही पर नज़र रखने वाले लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इन पदों पर किन लोगों को लाया जाएगा, क्योंकि इन नियुक्तियों से ही पता चलेगा कि अपने बाक़ी के कार्यकाल में सरकार की दशा और दिशा क्या रहने वाली है. अजीत सेठ को नया कैबिनेट सचिव और सुनील मित्रा को नया वित्त सचिव बनाए जाने के बाद बहुत से बाबू अब इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि आगे की नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर ही की जाएंगी. अभी गृह सचिव के पिल्लई, विदेश सचिव निरूपमा राव और रक्षा सचिव प्रदीप कुमार जल्द ही रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह नए लोगों के नामों पर क़यास लगने शुरू हो गए हैं. सूत्रों के मुताबिक़, प्रधानमंत्री साफ़ सुथरे और बेदाग़ छवि के अधिकारियों की नियुक्ति चाहते हैं. सीवीसी प्रकरण के बाद उच्च पदों पर होने वाली नियुक्तियों के लिए सबसे पहला आधार बेदाग़ रिकॉर्ड ही होगा.

ब्यूरोक्रेसी का बोझ

जब से नियामक संस्थाओं में शासन में भूमिका बढ़ी है तब से सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज़ पर एक विशेष नई सेवा के गठन के बारे में सोच रही है. सूत्रों के मुताबिक़ अब इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रयास तेज़ किए जा रहे हैं और क़ानून मंत्रालय जल्द ही एक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष पेश करने वाला है. सूत्र कहते हैं कि इस प्रस्ताव के पीछे क़ानून मंत्री वीरप्पा मोइली का दिमाग़ है. इसके पीछे विचार यह है कि सीसीआई, ट्राई, सेबी जैसी नियामक संस्थाओं के लिए बाबुओं की भर्ती सीधी की जाए. हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शिक्षा सेवा और लीगल सर्विस के गठन की योजना तो पहले ही फेल हो चुकी है और पहले से ही भारी–भरकम ब्यूरोक्रेसी के रहते एक और सेवा की भला क्या ज़रूरत है.

नैटग्रीड का गठन

घोषणा के दो साल बाद जाकर पी चिदंबरम की महत्वाकांक्षी योजना अब शुरू होने जा रही है. कुछ दिन पहले ही नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड (नैटग्रीड) को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ओर से हरी झंडी दे दी गई है. नैटग्रीड एक केंद्रीकृत डाटाबेस व्यवस्था होगी, जहां इंटेलीजेंस और क़ानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच साझा की जाने वाली सूचनाएं होंगी. नैटग्रीड के सीईओ पी रघु रमण को 6 महीने का सेवा विस्तार दिए जाने को अच्छा संकेत माना जा रहा है. हालांकि कुछ मंत्री इस बारे में सूचनाओं के इस्तेमाल की प्रक्रिया पर संदेह भी जता रहे हैं.

dilipcherian@gmail.com

अब लोकपाल नहीं बनेगा

पृष्ठ एक का शेष

नहीं किया. आख़िरकार सरकार को खेल समय पर कराने की पूरी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ी थी. कॉमनवेल्थ गेम्स में हुई गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने शुंगलु कमेटी का गठन किया था. उसकी रिपोर्ट भी आ गई. कई बड़े–बड़े राजनीतिक अधिकारियों पर सवाल खड़ा हुआ, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है. दयानिधि मारन का नाम अब सामने आया है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं. सवाल यह है कि सरकार और कांग्रेस पार्टी ने क्या मंत्रिमंडल की सामूहिक ज़िम्मेदारी के सिद्धांत को भुला दिया है. देश में कई योजनाएं चल रही हैं, जिसकी सीधी ज़िम्मेदारी कैबिनेट सचिवालय की है. इन योजनाओं में घोर भ्रष्टाचार चल रहा है, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? देश में रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय की ग़लतियों की वजह से देश के बैंकों से नक़ली नोट निकल रहे हैं. प्रधानमंत्री की नाक के नीचे से लाखों करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हो जाता है और कोई सुगबुगाहट भी नहीं होती है. शिबु सोरेन के जाने के बाद कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था. यह बात भी याद रखने की ज़रूरत है, ये सब घोटाले मीडिया की वजह से सामने आए. भ्रष्टाचार की कहानी सिर्फ़ चंद मंत्रालयों तक ही सीमित नहीं है. मीडिया देश के कई मंत्रालयों के कारनामों से वाक़िफ़ है, लेकिन ठोस सबूत की कमी के कारण मामले दबे पड़े हैं.

अन्ना हज़ारे फिर से अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि सरकार जिस तरह का लोकपाल बनाना चाहती है उससे वह संतुष्ट नहीं हैं. कांग्रेस इसे धमकी बता रही है. कांग्रेस अन्ना की टीम के रवैये को ग़ैर लोकतांत्रिक बताती है. कांग्रेस का मानना है कि यह निर्वाचित सरकार को धमकाने जैसा है, लेकिन आमरण अनशन या दबाव के ज़रिये संसद से उसका अधिकार नहीं छीना जा सकता. कपिल सिब्बल केंद्रीय मंत्री के साथ–साथ देश के जाने माने वकील हैं. क़ानून की समझ उनसे ज़्यादा किसे हो सकती है. यही वजह है कि वह सिविल सोसायटी के रुख़ पर सवाल उठाते हैं. वह कहते हैं कि उनकी अनेक मांगें ऐसी हैं जिन पर सरकार अकेले निर्णय नहीं कर सकती, क्योंकि देश में संसदीय लोकतंत्र है और हर क़ानून बनाने का हक़ संसद को है. सिविल सोसायटी सरकार का हिस्सा नहीं है और वह सरकार को निर्देशित भी नहीं कर सकती. क़ानून के नज़रिए से कांग्रेस पार्टी की दलील सही है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार को धमकाने की स्थिति आख़िर क्यों पैदा हुई? चुनी हुई सरकार से लोगों का विश्वास क्यों उठ गया? संसद से उसका अधिकार छीने जाने का सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ है? इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? जिस देश में संसद सदस्य पैसे लेकर सवाल पूछते हों. समर्थन के लिए जहां विधायकों और सांसदों की ख़रीद–फ़रोख्त होती हो. जहां पैसे देकर लोकसभा में समर्थन ख़रीदा जाता हो, गठबंधन सरकार बनाने के नाम पर ब्लैकमेलिंग और सौदेबाज़ी होती हो, जहां नीरा राडिया जैसी मीडिया मैनेजर यह तय करती हो कि मंत्री कौन बनेगा तो उस देश के मंत्री को संसदीय लोकतंत्र की दुहाई देने का क्या अधिकार है? जिस देश में उम्मीदवार बनने के लिए अपनी ही पार्टी को घूस देनी पड़े, वोट लेने के लिए पैसे बांटने पड़े, जेल में बंद लोग भी धनबल और बाहुबल के सहारे जनप्रतिनिधि चुन लिए जाते हों. जिस देश में अपराधियों को टिकट देने की राजनीतिक दलों में होड़ लगी हो, तो ऐसे सांसदों को प्रजातंत्र का ध्वजवाहक कैसे माना जाए? भारत पर कांग्रेस पार्टी का शासन पचास साल रहा. क्या इस दुर्दशा के लिए कांग्रेस ज़िम्मेदार नहीं है. क्या ऐसी संसद और ऐसे संसद सदस्य इस देश के प्रजातंत्र के लिए ख़तरा नहीं हैं? अन्ना हजारे और उनकी टीम को ग़ैर निर्वाचित तानाशाह बताने से पहले देश की जनता यह जानना चाहेगी कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो कौन सा तीर मार रहे हैं?

अन्ना हज़ारे और उनकी टीम केलोगों को ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी का सदस्य नहीं बनना चाहिए था. इससे अन्ना की साख भी बढ़ती और सरकार को संभलने का मौक़ा तक न मिलता. अन्ना को जो लोग गांधी बता रहे हैं, उन्हें यह भी पता करना चाहिए कि गांधी कभी किसी क़ानूनी कमेटी के सदस्य नहीं रहे. गांधी ने आंदोलन किया और समझौता वार्ता विशेषज्ञों पर छोड़ दी. अन्ना, गांधी के इस फ़लसफ़े को समझ नहीं पाए. जो ग़लती रामदेव ने की, वही ग़लती अन्ना हज़ारे ने की है. वह यह भी नहीं समझ सके कि राजनीतिक दलों से लड़ने के लिए राजनीति आनी चाहिए.

लोकपाल के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों का रुख़ भी सवालों के घेरे में है. भारतीय जनता पार्टी और वाममोर्चा ने शायद विपक्षी राजनीति के दर्शन को ही भुला दिया है. जो काम अन्ना हज़ारे और रामदेव कर रहे हैं वह असल में विपक्षी पार्टियों का काम है. वामदल चुनाव में बंगाल और केरल क्या हार गया, लगता है कोमा में चला गया है. उसने सारे राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप्पी साध ली है. देश की जनता आंदोलित है, लेकिन विपक्ष उसे नेतृत्व देने में नाकाम साबित हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से अपना हिसाब बराबर करने में लगी है. दोनों तरफ़ से ऐसे–ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जो राजनीति के गिरते स्तर को चिन्हित कर रहे हैं. इन पार्टियों को समझना चाहिए कि इससे लोगों का विश्वास और मनोबल टूटता है. लोकपाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है, इसे लेकर देश की जनता अंधेरे में है. यही वजह है कि अन्ना जैसे लोग जब भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन करते हैं तो समर्थन मिलता है. अन्ना और रामदेव लोगों में आशा जगाते हैं, वहीं राजनीतिक दल घनघोर निराशा के पर्याय बन चुके हैं. अगर सारी विपक्षी पार्टियां एक सशक्त और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने वाले लोकपाल का खुला समर्थन करतीं तो सरकार की हिम्मत नहीं होती कि वह इसे टाल सके.

अगर लोकपाल नहीं बनता है तो इसके लिए अन्ना हज़ारे और उनकी टीम भी ज़िम्मेदार होगी. अन्ना हज़ारे और उनके साथियों का लक्ष्य जन लोकपाल बिल को लागू कराना नहीं, बल्कि उसका श्रेय लेना है. उनके पास भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए लोकपाल के अलावा कोई दूसरा तरीक़ा नहीं है. उनके पास भविष्य की कोई योजना नहीं है. विचारधारा नहीं है. क्या एक ही परिवार से दो सदस्यों को ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी में शामिल करना ग़लत नहीं है? क्या इस देश में क़ानून के जानकारों की कमी है? यह कहना कि जन लोकपाल बिल हमने बनाया है और इसे कोई दूसरा समझ नहीं सकता, यह बात भी ग़लत है. अगर देश में लोकपाल बनेगा तो वह अन्ना हज़ारे नहीं बनाएंगे. संसद में बिल को पास किया जाएगा. अन्ना की टीम अगर जन लोकपाल बिल को ज्वाइंट कमेटी में पास भी करा लेती है, फिर भी इस पर संसद ही फ़ैसला करेगी. वहां अलग–अलग राजनीतिक दल हैं. जिस तरह से अन्ना की टीम ने सांसदों और नेताओं को आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया, राजनीतिक पार्टियों के ख़िलाफ़ बयान देने और सांसदों को भ्रष्ट साबित करने में जुट गई, उससे कांग्रेस के अलावा दूसरे राजनीतिक दल नाराज़ हो गए हैं. क्या अन्ना हज़ारे को यह पता नहीं है कि अगर क़ानून बनेगा तो उसे संसद में बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी. सांसदों ने वोटिंग के समय इस नाराज़गी का इज़हार कर दिया तो यह बिल कैसे पास होगा. इसकी रणनीति तो अन्ना हज़ारे को पहले ही बनानी चाहिए. अन्ना हज़ारे को चाहिए था कि आंदोलन की सफलता के बाद वह कमेटी के लिए ऐसे लोगों के नाम आगे करते, जिससे लोकपाल बिल न सिर्फ़ तैयार हो जाता, बल्कि संसद में इसे पारित होने की गारंटी भी मिल जाती. अगर इस कमेटी में अरुण जेटली, सीताराम येचुरी, सुब्रमण्यम स्वामी, फाली एस नरीमन और अरविंद केजरीवाल होते तो ये सरकारी प्रतिनिधियों पर न सिर्फ़ भारी पड़ते, बल्कि इस बिल को संसद में पास होने की गारंटी भी मिल जाती. यह बात सच साबित हुई है कि अन्ना की टीम सरकार के प्रतिनिधि के सामने टिक नहीं पाई. अगर जन लोकपाल बिल को लागू कराना मक़सद था तो अन्ना हज़ारे और उनकी टीम के लोगों को ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी का सदस्य नहीं बनना चाहिए था. इससे अन्ना की साख भी बढ़ती और सरकार को संभलने का मौक़ा तक न मिलता. अन्ना को जो लोग गांधी बता रहे हैं, उन्हें यह भी पता करना चाहिए कि गांधी कभी किसी क़ानूनी कमेटी के सदस्य नहीं रहे. गांधी ने आंदोलन किया और समझौता वार्ता विशेषज्ञों पर छोड़ दी. अन्ना, गांधी के इस फ़लसफ़े को समझ नहीं पाए. जो ग़लती रामदेव ने की, वही ग़लती अन्ना हज़ारे ने की है. वह यह भी नहीं समझ सके कि राजनीतिक दलों से लड़ने के लिए राजनीति आनी चाहिए. प्रजातंत्र के दो पहलू होते हैं–प्रणाली और सिद्धांत. प्रणाली प्रजातंत्र का शरीर है तो सिद्धांत प्रजातंत्र की आत्मा है. प्रजातांत्रिक प्रणाली का आधार है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, चुनाव आदि संस्थाएं हैं, लेकिन प्रजातंत्र की आत्मा तो जनमत है. अगर आत्मा ही मर जाए तो शरीर का क्या करेंगे. देश का जनमत भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने की किसी भी मुहिम के साथ है. इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली को ढाल बनाकर राजनीतिक वर्ग प्रजातंत्र की आत्मा को ही नष्ट करने में जुटा हुआ है.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 16
दिल्ली, 27 जून–3 जुलाई 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4+4+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

भारतीय राजनीति की विडंबना देखिए कि जिस हिमालयन अस्पताल में युवा संत ने दम तोड़ा, उसी अस्पताल में बाबा रामदेव को देखने के लिए मुख्यमंत्री गए, लेकिन निगमानंद की खोज ख़बर तक नहीं ली.

संत निगमानंद की मौत पर राजनीति

राजकुमार शर्मा

गंगा को बचाने के लिए जान देने वाले संत निगमानंद की मौत पर राजनीति शुरू हो गई है. इस मामले को लेकर जहां प्रदेश की निशंक सरकार पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, वहीं संत के परिवार वालों ने मातृ सदन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं. संत के परिवार वालों का कहना है कि निगमानंद पर अनशन का दबाव था. संत निगमानंद गंगा के रक्षार्थ चलाए गए अपने आंदोलन के तहत 19 फ़रवरी 2011 से अनशन पर थे. उनकी मांग थी कि गंगा के रक्षार्थ कुंभक्षेत्र को खनन मुक्त रखा जाए. 68 दिनों बाद अनशन के दौरान स्वामी निगमानंद को ज़िला प्रशासन द्वारा ज़िला चिकित्सालय में भर्ती कराकर उन्हें जबरन अन्नग्रहण कराया गया था. इस दौरान, ऐसा कहा जा रहा है कि खनन माफ़िया के इशारे पर इलाज के दौरान ही संत को किसी नर्स द्वारा ज़हर दे दिया गया. ज़हर देने के बाद संत निगमानंद की हालत चिंताजनक हो गई. आनन–फ़ानन में मातृ सदन के सदस्यों ने बेहतर इलाज के लिए संत को हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 40 दिनों तक कोमा में रहने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया. खनन माफ़िया से गंगा की रक्षा करने की मांग करने के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले निगमांद मातृ सदन के दूसरे संत बन गए, जबकि इससे पहले इसी संस्था के संत स्वामी गोकुलानंद की खनन माफ़िया द्वारा कालीढूंगी के जंगलों में निर्मम हत्या कर दी गई थी.

भारतीय राजनीति की विडंबना देखिए कि जिस हिमालयन अस्पताल में युवा संत ने दम तोड़ा, उसी अस्पताल में बाबा रामदेव को देखने के लिए मुख्यमंत्री गए, लेकिन निगमानंद की खोज ख़बर तक नहीं ली. स्पर्श गंगा के नाम पर काम करने की बात करने वाले मुख्यमंत्री द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए बाबा रामदेव के नौ दिन के अनशन पर हाय तौबा मचाना और गंगा के लिए बलिदान देने वाले संत निगमानंद के प्रति नकारात्मक रवैया आख़िर क्या दर्शाता है?

संत निगमानंद का आंदोलनों से गहरा नाता रहा है, इससे पहले भी वह दो बार अनशन कर चुके थे. 1995 में संत निगमानंद ने मातृ सदन के महंत संत शिवानंद सरस्वती से दीक्षा ली और शास्त्रों व वेदों का गहन अध्ययन के साथ ही गीता की ममर्ज्ञता प्राप्त की. उन्होंने वर्ष 2001 में देहरादून के गांधी पार्क में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ 73 दिन लगातार अनशन किया. इसके बाद उन्होंने वर्ष 2008 में मातृ सदन में लगातार 68 दिन का अनशन किया. युवा संत ने इस बार फिर जनहित के मुद्दे पर 115 दिन तक अनशन किया था. समाज एवं गंगा के लिए किए गए अनशन के कारण उनकी पहचान एक विद्वान तपस्वी संत की बन गई थी. निगमानंद खनन माफ़िया की कुदृष्टि की भेंट चढ़ गए. सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सूबे के नेता प्रतिपक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने सचिवालय में बुलाए गए पत्रकार सम्मेलन में स्वामी निगमानंद को अज्ञात नर्स द्वारा विष दिए जाने का मामला उठाते हुए सरकार से संत को उपचार हेतु दिल्ली ले जाने की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने अनसुना कर दिया था. उन्हें इस बात का मलाल है कि सरकार की संवेदनहीनता के कारण युवा संत को बचाया नहीं जा सका.

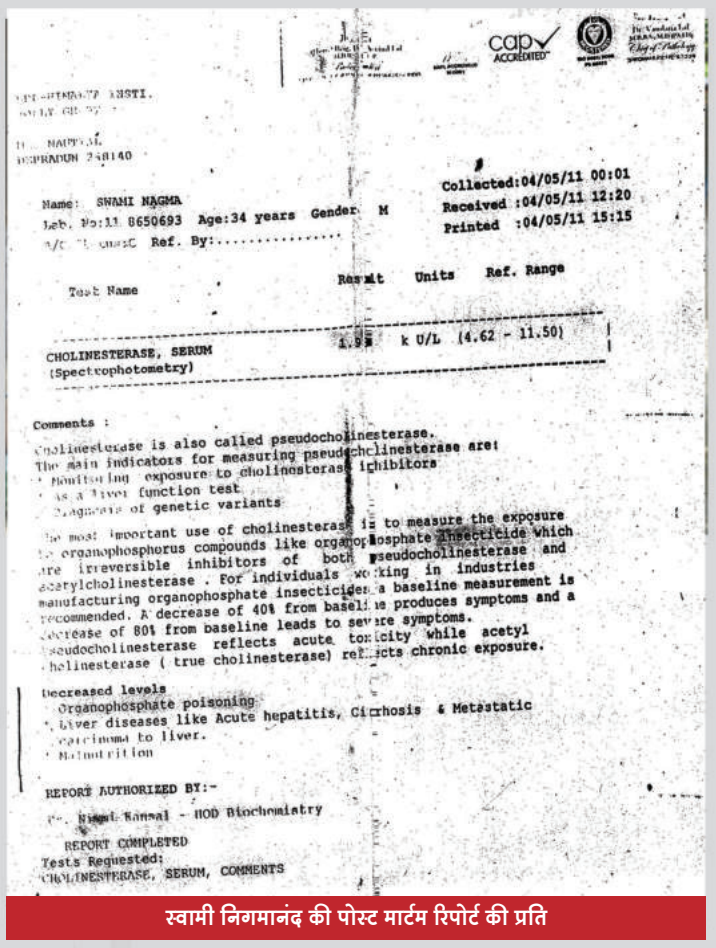

Name: SWAMI NAGMA
Lab. No:11 0650693 Age:34 years Gender M
Ref. By:.....
Collected:04/05/11 00:01
Received :04/05/11 12:20
Printed :04/05/11 15:15

Test Name	Result	Units	Ref. Range
CHOLINESTERASE, SERUM (Spectrophotometry)	1.9	k U/L	(4.62 - 11.50)

Comments :
Cholinesterase is also called pseudocholinesterase.
The main indicators for measuring pseudocholinesterase are:
- Monitoring exposure to cholinesterase inhibitors
- As a liver function test
- Diagnosis of genetic variants

The most important use of cholinesterase is to measure the exposure to organophosphorus compounds like organophosphate insecticide which are irreversible inhibitors of both pseudocholinesterase and acetylcholinesterase. For individuals working in industries manufacturing organophosphate insecticides a baseline measurement is recommended. A decrease of 40% from baseline produces symptoms and a decrease of 80% from baseline leads to severe symptoms.
Pseudocholinesterase reflects acute toxicity while acetyl cholinesterase (true cholinesterase) reflects chronic exposure.

Decreased levels
- Organophosphate poisoning
- Liver diseases like Acute hepatitis, Cirrhosis & Metastatic carcinoma to liver.
- Malnutrition

REPORT AUTHORIZED BY:-
Dr. Nimal Kansal - HOD Biochemistry
REPORT COMPLETED
Tests Requested:
CHOLINESTERASE, SERUM, COMMENTS

स्वामी निगमानंद की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रति

अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता एवं अखिल भारतीय संत एकता परिषद के अध्यक्ष कैलाशनाथ हठ योगी संत की मौत के लिए सरकार को ज़िम्मेदार मानते हुए कहते हैं कि सरकार अपनी इस जवाबदेही से बच नहीं सकती है. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह राज्यमंत्री रहे हरिद्वार परमार्थ निकेतन के महंत संत चिन्मयानंद ने कहा कि निगमानंद के अनशन को गंभीरता से न लेकर प्रशासन एवं सरकार ने संज्ञेय अपराध किया है, जिसके चलते ही युवा संत की मौत हुई. उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार से निगमानंद की मौत के लिए ज़िम्मेदार सरकारी स्वास्थ्यकर्मी को खोज कर दंडित करने की मांग की. हरिद्वार जयराम संस्थाओं के संस्थाध्यक्ष व संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने निगमानंद की मौत के लिए सूबे की निशंक सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझ कर युवा संत को नहीं बचाया. इससे यह बात भी साफ़ हो गई कि सरकार का जुड़ाव खनन माफ़िया के साथ है.

गंगा के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार अपने मनोरंजन एवं नाच गाने में ख़र्च कर रही है. युवा संत की जान की रक्षा के लिए एक कौड़ी भी सरकार ने ख़र्च नहीं की. धर्मनगरी में सभी संतों की आंखें नम हैं, लेकिन युवा संत के गंगा के लिए दिए गए बलिदान से वे गर्व महसूस कर रहे हैं. बलिदानी युवा संत को मिल रहा समर्थन साबित करता है कि
शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

सुशासन का सच

डॉ. अनिल सुलभ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नित नई घोषणाओं–योजनाओं की चर्चा और सूचना माध्यमों का इस्तेमाल करके मजबूरी से ज़ार–ज़ार हो रहे लोगों से पटे राज्य और सरकार की कमज़ोरियों से जनता का ध्यान बांटने में फ़िलवक़्त सफल दिखते हैं. इस सोची–समझी योजना में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने का शिगूफ़ा भी शामिल है. नीतीश जानते हैं कि अंदर चाहे जैसा हो, बाहर लोकरंजक छवि दिखनी चाहिए. कूटनीति की इस कसौटी पर भी नीतीश खरे दिखते हैं. वह इस बात से पूरी तरह वाक़िफ़ हैं कि प्रदेश की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं है. बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं कृषि आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विगत दो दशकों में स्थितियां लगातार बिगड़ी हैं. लालू प्रसाद एवं राबड़ी देवी की सरकारों का कार्यकाल प्रदेश को रसातल में ले जाने का काल था. पिछले 5 सालों में भी कुछ दिखावटी रंगरोगन के अलावा राज्य को विकास की पटरी पर लाने के लिए ज़रूरी आधारभूत संरचना विकसित नहीं हो पाई. ऐसे में नीतीश कुमार की यह राजनीतिक विवशता है कि वह अपनी कमज़ोरियों से जनता का ध्यान बंटाने के लिए प्रचार माध्यमों का सहारा लेकर प्रशंसा–स्तुति गान कराएं, हर असफलता के पीछे केंद्र के असहयोग का आरोप लगाए और उसमें जनता को भी भागीदार बनाएं.

दरअसल, नीतीश कुमार स्वयं को छोड़कर किसी भी राजनेता या राजनीतिक कार्यकर्ता को ईमानदार नहीं मानते. शासन में उनका हस्तक्षेप न हो, इसलिए नीतीश कुमार ने उच्चाधिकारियों को अपने ढंग से कार्य करने की पूरी छूट दे रखी है. पदाधिकारी अपने हिसाब से नाप–तौल करने के बाद जो मन बनाते हैं, वही काम प्रदेश में होता है. राजनेताओं की हालत यह है कि कोई ज़रूरी और सही काम भी यदि नहीं हो रहा है तो वे पदाधिकारियों से पूछ नहीं सकते. यह प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता प्रेसिडेंट रूल की याद दिलाती है. नीतीश कुमार को कौन बताए कि जनता का काम हो न हो, उससे इन पदाधिकारियों को क्या फ़र्क़ पड़ता है! कोई सरकार लोकप्रिय हो या अलोकप्रिय हो जाए, उससे उन्हें क्या मतलब, लेकिन राजनीतिक व्यक्तियों को फ़र्क़ पड़ता है. काम न होने पर जनता अपने प्रतिनिधियों को ही घेरती है. बड़े अफ़सरों से तो जनता को मिलने का अवसर ही नहीं मिलता. मौजूदा स्थिति तो यह है कि सत्तारूढ़ दल के विधायक भी अपनी इच्छा से डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी से नहीं मिल सकते. जमालपुर के जदयू विधायक शैलेष कुमार इसके उदाहरण हैं, जिन्हें बिना अनुमति के कक्ष में प्रवेश कर जाने से नाराज़ अधिकारी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और मिलने से मना कर दिया. पदाधिकारी का कहना था कि समय लेकर आएं.

इससे साफ़ है कि प्रदेश में पदाधिकारियों के अहं की स्थिति और राजनीतिज्ञों की हैसियत क्या है. मुमकिन है कि नीतीश कुमार प्रशासनिक कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप को उचित न मानते हों. यह ठीक भी है, किंतु जब स्थिति निरंकुशता की बन आए तो क्या वहां भी जनप्रतिनिधि मूकदर्शक और असहाय बने रहेंगे? हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि आज कोई राजनीतिक कार्यकर्ता तो क्या, विधायक और मंत्री भी ब्लॉक और थानों में कुछ नहीं बोल सकते. यदि कोई सिपाही किसी निर्दोष युवक को पकड़ कर थाने ले आए तो भी वे थानेदार से यह नहीं कह सकते कि लड़का बेक़सूर है, भला है, उसे छोड़ दीजिए. वहां वही होगा, जो पुलिस चाहेगी. यह दूसरी बात है कि वर्तमान स्थिति कुछ अच्छे और ईमानदार अधिकारियों के लिए आदर्श है, जो वास्तव में निष्ठापूर्वक जनहित में कार्य कर रहे हैं. नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के बीच प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में हुई धांधली को कोई क्यों नहीं रोक पाया? ऐसे–ऐसे शिक्षक बहाल हुए, जिनकी ककहरे से भेंट भी है या नहीं, बताना मुश्किल है. वे कक्षा में अंग्रेजी के दिन और महीनों के नाम तक बोर्ड पर नहीं लिख सकते. एक न्यूज़ चैनल ने ऐसे अनेक प्रमाण प्रसारित करके इन नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफ़ाश किया. क्या नीतीश कुमार को इस बात की ख़बर नहीं थी? जो नीतीश कुमार अपने छोटे–छोटे राजनीतिक विरोधियों की भी गतिविधियों की ख़बर लेते रहते है, उन्हें इस संगठित भ्रष्टाचार की भनक नहीं लगी, यह कैसे माना जा सकता है. क्या इसे प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा पर कुठाराघात नहीं कहा जाएगा? जिस प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा ही ध्वस्त हो जाएगी, उसका भविष्य कैसा होगा?

क़ानून और व्यवस्था की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है. गंभीर अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. अपहरण, बलात्कार एवं हत्या की घटनाओं में भी इज़ाफ़ा हुआ है. एक दम से स्वतंत्र पुलिस तंत्र को अब क्या कहना है, किस बात का रोना है? नीतीश बराबर यह कहते हैं कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, राज्य को उसका हक़ नहीं मिल रहा है. जब कांग्रेस ने इस आरोप के जवाब में बताया कि बिहार को उसके सभी हक़ मिल रहे हैं और वे पहले के मुक़ाबले अधिक हैं. इस पर नीतीश ने यह कहना शुरू किया कि केंद्र सरकार जो दे रही है तो क्या कोई एहसान कर रही है, यह तो बिहार का हक़ है. दरअसल केंद्र–राज्य के बीच संबंधों के संवैधानिक दृष्टिकोण से जो राज्य की हिस्सेदारी बनती है, वह मुख्यत: केंद्रीय करों के अंतरण की राशि के रूप में है. इसके अतिरिक्त जो प्रदेश का बजट होता है, उसमें योजना और ग़ैर योजना मद में केंद्र सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसे केंद्रीय सहायता कहते हैं. यदि विगत वितीय वर्षों में केंद्र की ओर से दी गई सहायता राशि पर ग़ौर किया जाए (इसमें राजग गठबंधन वाली वाजपेयी सरकार भी शामिल है, जिसमें नीतीश भी मंत्री थे) तो स्पष्ट होगा कि पूर्ववर्ती राजग सरकार के मुक़ाबले वर्तमान डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने लगातार सहायता राशि बढ़ाकर दी है. बिहार का बजट बढ़ाकर 25 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया, उसे भी केंद्र ने स्वीकृति प्रदान की. फिर भी नीतीश कुमार को शिकायत है कि केंद्र सहयोग नहीं करता. उन्हें तब यह शिकायत नहीं थी, जब वह केंद्र में मंत्री थे. विगत 5 वर्षों में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत केंद्र ने बिहार को 3 लाख 71 हज़ार 609 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की, जो केंद्रीय करों के अंतरण और बजट में केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त थी. सच्चाई यह है कि इस बड़ी धनराशि का सदुपयोग प्रदेश में हो नहीं सका. प्रत्येक योजना राशि बंदरबांट के बावजूद ख़र्च नहीं हो सकी, वापस लौटाई गई. ख़र्च की गई धनराशि का भी एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया. यदि इस राशि का सदुपयोग हुआ होता तो आज बिहार की तस्वीर अलग होती थी और यह सब कुछ हुआ सुशासन के नाम से बहुप्रचारित सरकार में. ऐसी तमाम बातों–समस्याओं की तरफ़ आम जनता और ख़ास तौर से प्रबुद्धजनों का ध्यान न जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने प्रचार माध्यमों और धन का खुलकर उपयोग (जिसे दुरुपयोग कहना अधिक मुनासिब होगा) किया. राशि के आवंटन में भी स्वेच्छाचारिता और अदूरदर्शिता का परिचय दिया जा रहा है. इसका प्रमाण उस आर्थिक प्रतिवेदन के ख़ुलासे से मिला है, जो स्वयं राज्य सरकार द्वारा कराया गया आर्थिक सर्वेक्षण है. उसके मुताबिक़, वित्तीय वर्ष 2009–10 में ग़ैर योजना मद, केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं के अंतर्गत ख़र्च की गई कुल धनराशि लगभग 4 खरब (3 खरब, 99 अरब, 66 करोड़) रुपये में से लगभग आधी राशि (एक खरब, 56 अरब, 714 करोड़ रुपये) केवल पटना ज़िले में ख़र्च कर दी गई. क्या प्रदेश का आधे हिस्से का अधिकारी केवल एक पटना ज़िला है? डेढ़ खरब रुपये एक वर्ष में ख़र्च करके पटना में क्या उपलब्धि हासिल हुई? क्या यह इतनी छोटी रक़म थी, जो केवल पार्कों के निर्माण में ख़र्च हो गई? आख़िर कहां–कहां, क्या–क्या हुआ? नीतीश कुमार चाहे जितना पर्दा डालने का प्रयत्न करें, संचार माध्यमों में जय बोल–हरि बोल का कीर्तन कराए, लेकिन वह दिन दूर नहीं, जब यह पाखंड जनता की नज़रों में आएगा. जनता अब जाग रही है, लुभावनी बातें अब उसे नहीं बहला सकतीं.

(लेखक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं)

feedback@chauthiduniya.com

हरियाणा सरकार ने आईएमटी रोजका मेव के लिए जिन किसानों से 1600 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की थी उन्हें छह महीने पहले ही मुआवज़ा दे दिया गया था.

मेवात किसान आंदोलन

जज़्बा वही रास्ता नया

हसन ख़ान मेवाती, मेवात के राजा थे. 1527 में बाबर के ख़िलाफ़ लड़ते हुए एक ही दिन में 12 हज़ार मेवाती योद्धा शहीद हो गए थे. शहीद इसलिए हुए क्योंकि अपनी ज़मीन को विदेशी आक्रांताओं से बचाना था. वह ज़माना और था. अब देश में लोकतंत्र है. कहने को अपनी सरकार है, लेकिन इस बार अपनी ज़मीन बचाने के लिए मेवात के लोगों के पास अपना गौरवपूर्ण इतिहास दोहराने का भी विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि लोकतंत्र में सशस्त्र संघर्ष की अनुमति नहीं है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की गूंज सरकारी दरवाज़ों को भेद नहीं पाती.

दरअसल, इस वक़्त देश के विभिन्न हिस्सों में ज़मीन बचाने को लेकर जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसी की कड़ी में एक और नाम मेवात के किसानों का भी जुड़ गया है. हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (रोजका) बनाने के नाम पर मेवात के किसानों से 1600 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया है, लेकिन किसानों का मानना है कि उन्हें अपेक्षाकृत बहुत ही कम मुआवज़ा दिया जा रहा है. ये किसान इसी मुद्दे को लेकर पिछले कई महीने से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. बहरहाल, यह लड़ाई हरियाणा से चल कर दिल्ली तक पहुंच गई है. 16 जून को हज़ारों मेवाती किसान, महिलाएं जंतर–मंतर पहुंचे. इस उम्मीद में कि वो राहुल गांधी उनकी बात को सुनेंगे, जो भट्टा पारसौल में जाकर किसानों के दर्द पर मरहम लगाते हैं.

दरअसल यह पूरा मामला अभी तक मुआवज़े की रक़म पर केंद्रित रहा है. हरियाणा सरकार ने आईएमटी रोजका मेव के लिए जिन किसानों से 1600 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की थी उन्हें छह महीने पहले ही मुआवज़ा दे दिया गया था. मुआवज़े के तौर पर इन किसानों को 16 लाख रुपए प्रति एकड़ दिए गए, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब कुछ ही दिनों बाद सरकार ने नई भूमि अधिग्रहण नीति बना दी. नई नीति के मुताबिक़ मेवात के किसानों को प्रति एकड़ 35 लाख रुपए मुआवज़ा देने की बात थी. ज़ाहिर है जिन किसानों की ज़मीन 16 लाख रुपए प्रति एकड़ ली गई थी, उनके लिए यह नई नीति किसी अन्याय से कम नहीं थी. ऐसे में विरोध होना स्वाभाविक भी था. सो, विरोध के स्वर भी उठे और अब धीरे–धीरे ये स्वर तेज़ भी होते जा रहे हैं. दिल्ली पहुंचे इन हज़ारों किसानों में महिलाओं की संख्या भी अच्छी–ख़ासी थी. ऐसा माना जाता है कि मेवात क्षेत्र के अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं अमूनन घर से बाहर नहीं निकलतीं, लेकिन दिल्ली के जंतर–मंतर पर उनकी संख्या देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता था कि मामला सचमुच गंभीर है.

> “अब सवाल ज़्यादा मुआवज़े का नहीं है. सवाल ज़मीन का है. अगर सरकार को ज़मीन लेनी ही है तो किसानों से बातचीत कर के और किसानों की शर्त पर ही मिलेगी. इस प्रदर्शन में जितनी संख्या में महिलाएं आई हैं उससे साबित होता है कि अब मेवात के लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे. हमलोग दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि अगर मेवात के इन लोगों को छेड़ा गया और इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो दिल्ली थम जाएगी.”
>
> अली अनवर अंसारी, *सांसद, जद(यू)*

इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में मेवात के कई संगठनों ने हिस्सा लिया और इसकी अगुवाई की जद(यू) सांसद अली अनवर अंसारी ने. अली अनवर जद(यू) नेता होने के साथ ही ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ के भी अध्यक्ष हैं और इस मंच के माध्यम से पिछड़े मुसलमानों की समस्याओं को उठाते रहे हैं. मेवात के किसानों के भूमि अधिग्रहण और असमान मुआवज़े का विरोध जताते हुए अली अनवर कहते हैं कि अब हम लोग सिर्फ़ ज़्यादा मुआवज़े की ही नहीं, बल्कि इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार ग़रीब किसानों की ज़मीन मनमाने ढंग से न ले सके. अगर सरकार को ज़मीन चाहिए तो वह किसानों की शर्त पर ले. असल में, 1600 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण से मेवात के 9 गांव प्रभावित हो रहे हैं. किसान मुख्यमंत्री और राज्यपाल को 7 अप्रैल और 24 मई को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर अब तक देखने को नहीं मिला है. इसके अलावा जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया है वह कुंडली–मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ़ स्थित है. इस हिसाब से देखें तो इस ज़मीन की बाज़ार क़ीमत करोड़ों में है, लेकिन सरकार ने चतुराई से यह ज़मीन महज़ कुछ लाख रुपए प्रति एकड़ के मुआवज़े पर किसानों से ले ली. दूसरी ओर, फ़रीदाबाद के किसानों से जब ज़मीन अधिग्रहित की गई थी तब वहां के किसानों को 45 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवज़ा दिया था. ज़ाहिर है, ऐसी स्थिति में मेवात के 9 गांवों के किसान ख़ुद को ठगा महसूस कर रहे हैं.

बहरहाल, योद्धाओं के वंशजों यानी मेवात के किसानों के इस आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या होगा, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता. लेकिन, देश भर में ज़मीन बचाने को लेकर जिस तेज़ी से आंदोलनों की जो आंधी चल रही है वह वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए तो क़तई शुभ संकेत नहीं मानी जा सकती.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

मध्य प्रदेश

वेलस्पन कंपनी का कारनामा

देश में कितने और सिंगुर बनेंगे

विकास के नाम पर आख़िर कब तक किसानों और मज़दूरों को उनके हक़ से वंचित किया जाएगा? सेज, नंदीग्राम, सिंगुर, जैतापुर, फ़ेहरिस्त लंबी है और लगातार लंबी होती जा रही है. इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है वेलस्पन का. मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में वेलस्पन कंपनी के प्रस्तावित पावर प्लांट की स्थापना हेतु ज़िले की बरही एवं विजयराघवगढ़ तहसीलों के गांव बुजबुजा व डोकरिया के किसानों की लगभग 237.22 हेक्टेयर भूमि का शासन द्वारा अधिग्रहण किए जाने की ख़बर है. इससे दोनों ही गांवों के किसानों में हड़कंप मचा है. नतीजन विरोध में आवाज़ भी बुलंद होनी शुरू हो गई है. किसानों ने ज़िला कलेक्टर को इस कार्यवाही के विरुद्ध सामूहिक रूप से आपत्ति व्यक्त करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है.

वेलस्पन एनर्जी नामक औद्योगिक कंपनी द्वारा ज़िले की विजयराघवगढ़ एवं बरही तहसीलों के ग्राम बुजबुजा व डोकरिया के क्षेत्रीय किसानों की कृषि भूमि का उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अधिग्रहण किया गया है. इसके लिए कंपनी ने शासकीय अमले की ज़ोर ज़बरदस्ती का भय दिखाया. डोकरिया एवं बुजबुजा ग्रामों की तस्वीर बदलने, क्षेत्रीय बेरोज़गारों को हज़ारों की तादाद में रोज़गार देने जैसे लालच दिए गए. यहां तक कि कई स्थानीय व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों समेत दलालों से लेकर मीडिया तक का एक बड़ा तबक़ा इस दिशा में कंपनी का भरसक सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. इतना ही नहीं कंपनी के संरक्षण में पिछले दिनों बाक़ायदा एक सामाजिक संस्था तक पंजीकृत कराई गई.

प्रस्तावित उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक ज़मीनें देने से ग्रामीणों द्वारा साफ़–साफ़ इंकार किए जाने व हज़ारों आपत्तियां दर्ज कराए जाने के बाद वेलस्पन कंपनी द्वारा बाक़ायदा एक संस्था वेलस्पन ताप विद्युत परियोजना प्रभावित वेलफेयर संघ–डोकरिया, बुजबुजा तहसील विजयराघवगढ़, ज़िला कटनी मध्य प्रदेश रजि.नं.04/15/05/13331/11 हाल ही में पंजीकृत कराई गई है. इस संस्था की ओर से गत दिनों एक पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित कराया गया है. साथ ही कई संदिग्ध हस्ताक्षर युक्त एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है. इसके माध्यम से ग्राम डोकरिया व बुजबुजा में प्रस्तावित वेलस्पन एनर्जी के प्लांट से जहां एक ओर क्षेत्रीय विकास, बड़ी संख्या में स्थानीय युवा बेरोज़गारों को रोज़गार मिलने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर उद्योग स्थापना का विरोध करने वालों को असामाजिक तत्व बताया जा रहा है और ऐसे लोगों को विकास का दुश्मन कहा जा रहा है. इस संस्था के माध्यम से कंपनी और उसके धोखे की पोलपट्टी खोलने तथा ज़िले के प्रबुद्ध नागरिकों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, विभिन्न राष्ट्रीय जनांदोलनों के प्रतिनिधियों को विकास विरोधी व असामाजिक तत्व ठहराने की कोशिश की जा रही है.

कंपनी की ओर से ज़िले में अराजकता का वातावरण निर्मित किए जाने के प्रयास भी तेज़ी से जारी हैं. इस सबके बावजूद बुजबुजा एवं डोकरिया ग्रामों के बहुसंख्यक ग्रामीण इस उद्योग के लिए किसी भी क़ीमत पर अपनी ज़मीनें देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी आपत्तियां तथा विरोध को पर्याप्त महत्व न दिए जाने और उसकी पूरी तरह अनदेखी करते हुए उनकी ज़मीनें हथियाने की प्रक्रिया पर अभी भी रोक न लगने से नाराज़ ग्रामीणों, किसानों आदि ने अब एक बार फिर आर–पार आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने का मन बना लिया है. इन ग्रामीणों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन में हर तरह का साथ दे रहे देवीदीन गुप्ता, अजय सरावगी, चैतू पटैल, राजेश नायक कहते हैं कि कटनी ज़िले के बरही तहसील अंतर्गत ग्राम बुजबुजा, डोकरिया, खन्ना, बनगंवा में भूमि अधिग्रहण अधिनियम का दुरुपयोग करते हुए ज़बरदस्ती छीनी जा रही कृषि भूमि के ख़िलाफ़ किसानों व स्थानीय निवासियों ने तय किया है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पांच स्थानीय लोगों का जत्था प्रतिदिन अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठेगा और यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि वेलस्पन कंपनी पावर लिमिटेड के पक्ष में जारी की गई भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द नहीं की जाती.

वेलस्पन कंपनी के पावर प्लांट का विरोध करने के लिए कई बार किसान कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी मंशा ज़ाहिर कर चुके हैं, लेकिन लंबे अरसे से चली आ रही इस जंग में प्रशासन ने किसानों को हताश ही किया है. किसानों की आशंकाओं का समाधान तथा उनकी ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों का निराकरण किए बग़ैर ही उन्हें उनकी भूमि से वंचित किया जाना, साफ़ तौर पर किसानों के जीवन को ख़तरे में डालने जैसा ही है. किसानों के साथ प्रशासन का यह रवैया किसानों में रोष का सबब भी बना हुआ है. वेलस्पन कंपनी का हितैषी ज़िला प्रशासन आख़िर सभी किसानों को भुखमरी की कगार पर खड़ा करने पर आतुर क्यों है? क्या सरकार और प्रशासन इस देश में एक और सिंगुर का इंतज़ार कर रहे हैं?

अरविंद वर्मा
feedback@chauthiduniya.com

उमा लखनऊ में रहकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार एवं प्रभार का काम देखेंगी. उनकी वापसी से उत्तर प्रदेश में भाजपा को ताक़त मिलेगी.

उत्तर प्रदेश

सपा अधिवेशन

न दिशा मिली न दशा संभली

अजय कुमार

आगरा में समाजवादी पार्टी का आठवां राष्ट्रीय अधिवेशन ऊहापोह और नसीहतों के बीच समाप्त हो गया. ताज नगरी के तारघर मैदान में बने लोहिया नगर में सपा नेताओं ने पहले दिन बसपा पर तो दूसरे दिन कांग्रेस पर निशाना साधा. कई मुद्दों पर भटकाव साफ़ दिखाई दिया. शुरू से लेकर अंत तक पार्टी तय नहीं कर पाई कि उसका दुश्मन नंबर वन कौन है? पार्टी के भीतर जारी गुटबाज़ी से कैसे निपटा जाए? चुनावी समर में उसके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम का तोड़ कैसे निकाला जाए? केंद्र की मनमोहन सरकार को समर्थन देने के पीछे की मजबूरी क्या है? आज़म ख़ां अधिवेशन के पहले दिन कहां ग़ायब रहे? किस तरह भाजपा और कांग्रेस को पीछे धकेल कर सपा को बसपा के विकल्प के रूप में पेश किया जाए, पार्टी कुछ भी तय नहीं कर पाई.

प्रदेश और देश के कई ऐसे तमाम मुद्दे थे, जिसे लेकर मंच से बयानबाज़ी तो ख़ूब हुई, लेकिन कोई ठोस कार्य-योजना नहीं बन पाई. जनता से जुड़े तमाम मुद्दे गरमाने के बाद भी सपा के शीर्ष नेताओं ने किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा नहीं बनाई, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा देखी गई. माना यह जा रहा था कि अधिवेशन के अंत में किसी बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन सिंह ने इतना ज़रूर कहा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर एक बड़ा आंदोलन चलना चाहिए, लेकिन उनकी बात को समर्थन नहीं मिला. सपा विधानमंडल दल के नेता शिवपाल यादव, मोहम्मद आज़म ख़ां, रेवती रमण सिंह, अखिलेश सिंह आदि सभी वक्ता कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों और बसपा सरकार के भ्रष्टाचार को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश ही देते रहे. अधिवेशन में कई राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित करने के अलावा कार्यकर्ताओं को यह भी संदेश दिया गया कि सूबे के चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं. उन्हें चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अलख जगाए मुलायम ने अपने भाषण के दौरान एक बार भी बाबा रामदेव का नाम नहीं लिया, लेकिन आज़म ख़ां की जब बारी आई तो उन्होंने मायावती सरकार के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बाबा रामदेव और अन्ना हज़ारे को लखनऊ में अनशन करने का न्योता दिया. भाजपा ने उमा को आगे लाकर भी सपा की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया. पिछड़े वोट बैंक के सहारे कई बार अपनी मंज़िल हासिल कर चुकी सपा को डर इस बात का भी है कि पिछड़ी जाति (लोध) की उमा भारती उन वोटरों को अपने पाले में फिर से न खींच लें, जो कल्याण के भाजपा से जाने के बाद उससे दूर चला गया था. एक मौक़ा ऐसा भी आया जब धरती पुत्र मुलायम को अपने ही कार्यकर्ताओं को आईना दिखाना पड़ा. अधिवेशन में सपा प्रमुख को अपनी पार्टी की गुटबाज़ी से भी रूबरू होना पड़ा. यही वजह थी कि मुलायम को समापन भाषण में मंच से ही कहना पड़ा कि पार्टी में गुटबाज़ी की जड़ें काफ़ी गहरी हो चुकी हैं और पार्टी नेतृत्व इसे लेकर फ़िक्रमंद है. शीर्ष नेतृत्व का मानना था कि अधिवेशन में ज़िलों से आए अधिकांश नेताओं की कोशिश एक-दूसरे को नीचा दिखाने और शिकायतें करने की रही. आलाकमान ने यहां तक कहा कि अगर आप अपने ही झगड़ों में उलझे रहेंगे तो दुश्मन से कैसे निपटेंगे. आज़म ख़ां जैसे क़द्दावर नेता भी ख़ुद को इस गुटबाज़ी से बचा नहीं पाए. सपा अधिवेशन के पहले दिन आज़म ख़ां की ग़ैर-मौजूदगी पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही. अधिवेशन के पहले दिन देर शाम आगरा पहुंचे आज़म ख़ां ने मुलायम सिंह से शिष्टाचारवश भी मुलाक़ात नहीं की. वह कुछ देर तक मंच से दूर पंडाल में ही बैठे रहे. अधिवेशन की कार्यवाही ख़त्म होने के बाद जब आज़म ख़ां से होटल चलने को कहा गया तो उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया. वह ईदगाह के निकट स्थित एक मध्यम श्रेणी के होटल में जाकर ठहर गए. आज़म ख़ां की नाराज़गी का कारण पार्टी के एक और मुस्लिम नेता रशीद मसूद बताए जाते हैं. हुआ यूं कि आज़म ख़ां ने पार्टी के दिग्गज नेता रशीद मसूद के वर्चस्व वाले सहारनपुर में अपने प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिला दिया. इसी को लेकर आज़म ख़ां और रशीद मसूद के बीच मन-मुटाव पैदा हो गया. रसीद के क़रीबियों का कहना था कि आज़म ख़ां अपने प्रत्याशी को यहां से टिकट तो दिला सकते हैं, लेकिन रसीद मसूद की मर्ज़ी के बिना उसे जिता नहीं सकते. यही बात आज़म ख़ां को बुरी लग गई.

सपा अधिवेशन के पहले दिन आज़म ख़ां की ग़ैर-मौजूदगी पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही. अधिवेशन के पहले दिन देर शाम आगरा पहुंचे आज़म ख़ां ने मुलायम सिंह से शिष्टाचारवश भी मुलाक़ात नहीं की. वह कुछ देर तक मंच से दूर पंडाल में ही बैठे रहे.

सपा के अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव को आठवीं बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना, कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं रही, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए मुलायम का नाम ही पेश किया गया था. दो वर्ष पूर्व आगरा में हुए अधिवेशन से इस बार मंच का नज़ारा काफ़ी बदला हुआ था. दो साल पहले कल्याण आगरा के मंच पर विराजमान थे तो अबकी बार आज़म ख़ां दिखाई दिए. अमर सिंह भी मौजूद नहीं थे. यह और बात थी कि कल्याण मुद्दे पर मुलायम के माफ़ी मांगने के बाद भी सपा के प्रति मुसलामानों का भटकाव जारी है. मुलायम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि 2012 में प्रदेश में सपा की सरकार बने और 2014 के आम चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिति यह हो कि केंद्र में कोई भी पार्टी सपा के समर्थन के बिना सरकार न बना सके. मुलायम सहित पार्टी के अधिकांश नेता कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम से काफ़ी चिंतित दिखे. आरोप लगाया गया कि छोटे-छोटे दल जो अल्पसंख्यकों के बीच बिरादरीवाद का ज़हर घोलते हैं उनसे गठबंधन करके कांग्रेस मुसलमानों का वोट बांटना चाहती है जिससे भाजपा को फ़ायदा होगा. हमेशा प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देने वाले मुलायम ने इस बार उन्हें भी नहीं छोड़ा. उन्होंने प्रधानमंत्री मनामोहन सिंह पर आरोप लगाया कि बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के जन्म स्थान पर विवाद खड़ा करके कुछ कांग्रेसी भारत-नेपाल के बीच संबंध ख़राब करने की साज़िश कर रहे हैं और प्रधामनंत्री चुप्पी साधे हुए हैं. अधिवेशन में सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशें लागू न किए जाने के ख़िलाफ़ कांग्रेस को घेरने का काम भी किया गया. संकल्प के साथ मुलायम ने उत्तर प्रदेश की सत्ता मिलने पर मुस्लिमों का पिछड़ापन दूर करने की बात कही. मुलायम ने कांग्रेस पर दबाव बनाते हुए कहा कि जब तक केंद्र मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं देता, तब तक इस क़ौम का भला होने वाला नहीं है. बात अंतरराष्ट्रीय मुद्दे की आई तो अधिवेशन में मुलायम चीन की चुनौती पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत महसूस करते भी दिखे. पार्टी ने महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन के मुद्दे को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए.

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा की सारथी उमा भारती

लंबे समय से वापसी की चर्चा और विरोधी स्वरों के बीच आख़िरकार उमा भारती की वापसी हो ही गई. उनकी वापसी तो दिल्ली में हुई, लेकिन आहट यूपी में सबसे पहले सुनने को मिली. उमा की वापसी के साथ ही यह भी तय हो गया कि भाजपा आलाकमान को यूपी के किसी भी नेता पर इतना विश्वास नहीं था कि वह अपने बूते पर भाजपा का बेड़ा पार लगा सकता है. आलाकमान की इसी सोच ने उमा की वापसी का मार्ग प्रशस्त कर दिया. उनकी वापसी लखनऊ में ही हो जाती, लेकिन कुछ गतिरोध के कारण ऐसा हो नहीं पाया. तब बैठक के बीच में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का रातों रात नागपुर जाना भी चर्चा का विषय बना था. पार्टी इस रणनीति पर भी काम कर रही थी कि बैठक के आख़िरी दिन उमा भारती की वापसी की घोषणा कर दी जाए, लेकिन अंदरूनी विरोध के चलते यह एक बार फिर टल गया. इसके बाद संघ ने दबाव बनाया और उमा की लखनऊ की बजाए दिल्ली में वापसी को कोई रोक नहीं पाया.

छह साल पहले अनुशासनहीनता के लिए पार्टी से निष्कासित उमा भारती की वापसी के मौक़े पर पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने दो टूक कह दिया कि उत्तर प्रदेश के अभियान में उमा जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. उन्होंने दावा किया कि उमा की वापसी का निर्णय पार्टी के भीतर आम सहमति से किया गया है और उमा के आने से भाजपा को उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा मिलेगी. उमा की वापसी के साथ ही तेज़-तर्रार संन्यासिनी ने भाजपा में वापसी की हैट्रिक पूरी कर ली. इसी के साथ ही भाजपा पर संघ की पकड़ एक बार फिर साबित हो गई, क्योंकि भाजपा में उमा की वापसी के विरोध में कई स्वर थे जिन्हें नागपुर से आए आदेश ने चुप करा दिया. पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनकी वापसी की ज़रूरत समझी, क्योंकि इस चुनाव पर भाजपा का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है. 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी का उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना ज़रूरी है. उमा की वापसी तो हो गई है, लेकिन उनके लिए उत्तर प्रदेश में काम करना आसान होगा ऐसा नहीं लगता है. उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता उमा की वापसी को लेकर तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि सबको अनदेखा करके उमा को आगे किया गया. ज़रूरत की बात की जाए तो उमा को भी भाजपा की उतनी ही ज़रूरत थी जितनी भाजपा को उनकी. छह वर्षों तक भाजपा से बाहर रही उमा भारती भी अकेले दम कुछ हासिल नहीं कर पाई थीं. उन्होंने पार्टी तो बना ली, लेकिन न तो पार्टी ही खड़ी कर पाईं और न ही ख़ुद का विधानसभा चुनाव ही जीत पाईं. भाजपा को पिछली बार मध्य प्रदेश में जो दो तिहाई बहुमत हासिल हुआ था उसे उमा ने सिर्फ़ अपने बलबूते मान लिया था. अब उमा का कार्यक्षेत्र लखनऊ होगा, यह बात तय करके भाजपा ने एक तो मध्य प्रदेश के नेताओं को ख़ुश करने का प्रयास किया है जो भोपाल से उनकी दूरी चाहते थे, साथ ही दिल्ली के उन नेताओं को भी राहत प्रदान की है, जो उमा की वापसी के विरोधी थे. अब देखना यह है कि उमा के कंधों पर पार्टी ने जो ज़िम्मेदारी डाली है उस पर वह कितना खरा उतर पाती हैं. उमा ने घर वापसी पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि वह जहाज़ के ऐसे पक्षी की तरह महसूस कर रही हैं जो उस पर वापस आने के लिए उड़ान भरता है. उन्होंने कहा कि पार्टी से पांच-छह साल बाहर रहने पर मैंने महसूस किया कि सिर्फ़ भाजपा ही मेरा किनारा और मेरी मंज़िल है. इन छह वर्षों में मैंने सबसे बड़ा सबक़ यह सीखा कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद के लिए भाजपा का कोई विकल्प नहीं है. भाजपा से पिछले पांच साल बाहर रहने के दिनों को मैं भुला देना चाहती हूं.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी उमा भारती को लेकर कुछ ज़्यादा ही चेतन्य दिखाई दे रहे हैं. उनका तो यहां तक मानना है कि उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह की वापसी को रोकने के लिए उमा महत्व-पूर्ण विकल्प साबित होंगी. उमा लखनऊ में रहकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार एवं प्रभार का काम देखेंगी. उनकी वापसी से उत्तर प्रदेश में भाजपा को ताक़त मिलेगी. उमा को सबसे पहले प्रदेश भाजपा नेताओं की टीम बनाना होगी जो उनके हिसाब से काम कर सके. उनके पास कलराज मिश्र, लालजी टंडन, केसरी नाथ त्रिपाठी जैसे नेताओं के साथ काम करने का अनुभव है, तो दूसरी तरफ़ राजनाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही जैसे दिग्गजों को साथ लेकर चलने की चुनौती भी होगी.

उमा की वापसी के साथ ही कल्याण सिंह को लेकर भी अटकलें शुरू हो गई हैं. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उमा अपना भाई मानती हैं. ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक तो उमा के ख़िलाफ़ कल्याण सिंह ज़्यादा ज़हर नहीं उगलेंगे, दूसरे उनके हटने से भाजपा का जो लोध वोट बैंक छिटक गया था, उसका बड़ा हिस्सा उमा वापस लाने में सफल हो सकती हैं. प्रदेश में 7 प्रतिशत लोध वोटर क़रीब 25-27 विधानसभा सीटों पर जीत-हार का फ़ैसला करते हैं.उमा भारती वापसी का स्वागत करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने कहा कि वह मन और विचारों से पहले ही पार्टी से जुड़ी थीं, केवल उनका तन पार्टी में दोबारा लौटा है. उमा की वापसी से पार्टी को एक नई दिशा और मज़बूती मिलेगी. उनसे जब पूछा गया कि उमा भारती को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने की बात सामने आ रही है तो क्या पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं मिला था जिसे पार्टी का प्रभारी बनाया जा सके, इस पर कटियार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के पास बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन उमा भारती को इसलिए पार्टी का प्रभारी बनाया जा रहा है कि वह यहां से मध्य प्रदेश को भी संभाल सकेंगी. भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी उमा की वापसी पर ख़ुशी ज़ाहिर की. उन्होंने कहा कि दो अंकों में पहुंच चुकी भाजपा विधायकों की संख्या अगर उमा भारती तीन अंकों तक पहुंचा देती हैं तो यह उनके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा.

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

संस्थान की चहारदीवारी करवाने का काम शुरू किया, लेकिन जानवरों पर लगाम लगाने के नाम पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई.

आईजीआईएमएस पटना

रिटायरमेंट, पुनर्नियुक्ति, इस्तीफ़ा

निदेशक की मनमानी सब पर भारी

पटना का इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, अपनी तमाम विशेषताओं के बावजूद आजकल विवादों से घिरा हुआ है और इसके केंद्र में हैं संस्थान के निदेशक. संस्थान के वर्तमान निदेशक डॉ. अरुण कुमार का कार्यकाल और क्रियाकलाप विवादों से भरा हुआ है. अपनी मनमर्ज़ी चलाते हुए उन्होंने तमाम नियम क़ानून को ताक़ पर रख दिया है. वह जो चाहते हैं वही होता है. नतीजतन एक अधिकारी जिस दिन रिटायर होता है उसी दिन उसे फिर से बहाल भी कर देते हैं. चौथी दुनिया की ख़ास रिपोर्ट :

शशि शेखर

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. अरुण कुमार के कार्यकाल और क्रियाकलाप विवादों से भरा हुआ है. संस्थान के चिकित्सक पद पर सेवारत डॉ. अरुण कुमार को पदोन्नत करके निदेशक बनाया गया था. इस पद पर आते ही डॉ. कुमार ने अपनी मनमानी चलानी शुरू कर दी. पहले संस्थान परिसर को जानवरों से मुक्त कराने के नाम पर संस्थान की चहारदीवारी करवाने का काम शुरू किया, लेकिन जानवरों पर लगाम लगाने के नाम पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई. राजीव नगर, केसरी नगर, महेश नगर आदि मोहल्ले के लोग संस्थान के किनारे से निकले मार्ग से होकर बेलीरोड की ओर आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन एक दिन नवनिर्मित चहारदीवारी गिर गई. इस दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जिसका नाम भोला सहनी (35 वर्ष) था. उसकी मौत के बाद से उसका परिवार सड़क पर आ गया. इस मौत और घटिया तरीक़े से बनाई गई दीवार की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है.

लेकिन यह घटना तो डॉ. अरुण कुमार की मनमानी का एक उदाहरण भर है. असली खेल और असली कहानी तो और भी गंभीर है. मामला संस्थान के प्रशासनिक पदाधिकारी डॉ. बेनी माधव और आशुलिपिक के पद पर बहाल संतोष चार्ली से जुड़ा है. वर्ष 1984 में डॉ. बेनी माधव प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर बहाल हुए. डॉ. बेनी माधव 30/11/2010 को सेवानिवृत हो गए, लेकिन यहीं पर संस्थान के निदेशक डॉ. अरुण कुमार ने अपनी मनमानी चलाते हुए और नियम क़ानून की बखिया उधेड़ते हुए डॉ. बेनी माधव को 30/11/2010 को ही फिर से प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति का आदेश दे दिया. इतना ही नहीं, डॉ. बेनी माधव को मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ-साथ उप निदेशक (प्रशासन) भी बना दिया. ग़ौरतलब है कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी का पद स्वीकृत ही नहीं है फिर भी डॉ. बेनी माधव को मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी बनाया गया और ग़लत ढंग से संस्थान से अधिक वेतन दिया गया.

डॉ. बेनी माधव को दिनांक 30/11/2010 से ही सेवानिवृत करने का कार्यालय आदेश संख्या 5393/प्रशा. दिनांक 30/11/2010 को निर्गत किया गया. इस आदेश में भी ग़लत तरीक़े से उन्हें मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत दिखाया गया है. उक्त कार्यालय के आदेश के तुरंत बाद ही आदेश संख्या 5394/प्रशा. दिनांक 30/11/2010 द्वारा डॉ. बेनी माधव को अध्यक्ष शासी निकाय के अनुमोदन के आलोक में दिनांक 1/12/2010 के प्रभाव से ग़ैर-स्वीकृत पद मुख्य प्रशासी पदाधिकारी के पद पर दोबारा नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया. नियम के मुताबिक़ सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना किसी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है. इसके अलावा, आशुलिपिक के पद पर की गई नियुक्ति भी विवादों में घिर गई. इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र देने के लिए सिर्फ़ पांच दिन का समय दिया गया, वो भी इस संबंध में सूचना सिर्फ़ नोटिस बोर्ड पर दी गई थी. नियमत: पांच रिक्ति तक के लिए नियोजनालय से नाम मांगा जाना चाहिए था या समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करना था.

> **डॉ. बेनी माधव को दिनांक 30/11/2010 से ही सेवानिवृत करने का कार्यालय आदेश संख्या 5393/प्रशा. दिनांक 30/11/2010 को निर्गत किया गया. इस आदेश में भी ग़लत तरीक़े से उन्हें मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत दिखाया गया है. उक्त कार्यालय के आदेश के तुरंत बाद ही आदेश संख्या 5394/प्रशा. दिनांक 30/11/2010 द्वारा डॉ. बेनी माधव को अध्यक्ष शासी निकाय के अनुमोदन के आलोक में दिनांक 1/12/2010 के प्रभाव से ग़ैर-स्वीकृत पद मुख्य प्रशासी पदाधिकारी के पद पर दोबारा नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया.**

INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES : SHEIKHPURA : PATNA-14

Office order

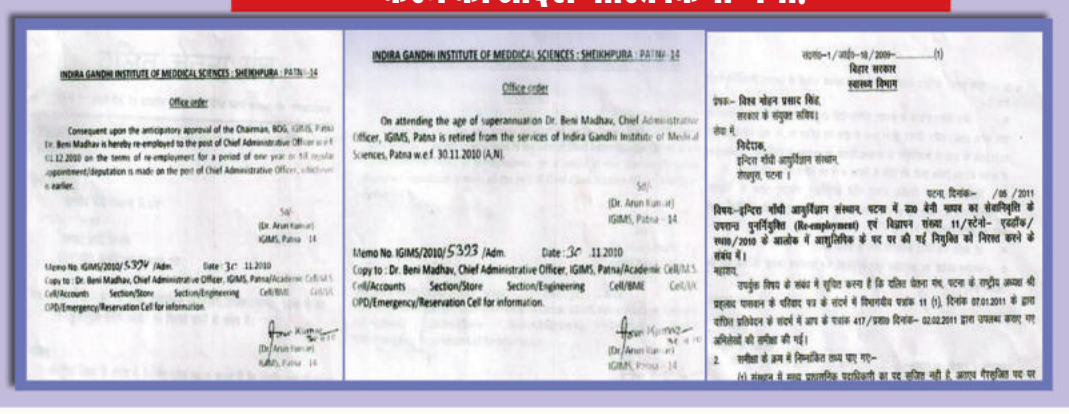

Consequent upon the anticipatory approval of the Chairman, BOG, IGIMS, Patna Dr. Beni Madhav is hereby re-employed to the post of Chief Administrative Officer w.e.f. 01.12.2010 on the terms of re-employment for a period of one year or till regular appointment/deputation is made on the post of Chief Administrative Officer, whichever is earlier.

Sd/-
(Dr. Arun Kumar)
IGIMS, Patna - 14

Memo No. IGIMS/2010/5394 /Adm. Date: 30 .11.2010
Copy to : Dr. Beni Madhav, Chief Administrative Officer, IGIMS, Patna/Academic Cell/M.S. Cell/Accounts Section/Store Section/Engineering Cell/BME Cell/UC OPD/Emergency/Reservation Cell for information.

(Dr. Arun Kumar)
IGIMS, Patna - 14

INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES : SHEIKHPURA : PATNA-14

Office order

On attending the age of superannuation Dr. Beni Madhav, Chief Administrative Officer, IGIMS, Patna is retired from the services of Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna w.e.f. 30.11.2010 (A.N).

Sd/-
(Dr. Arun Kumar)
IGIMS, Patna - 14

Memo No. IGIMS/2010/5393 /Adm. Date: 30 .11.2010
Copy to : Dr. Beni Madhav, Chief Administrative Officer, IGIMS, Patna/Academic Cell/M.S. Cell/Accounts Section/Store Section/Engineering Cell/BME Cell/UC OPD/Emergency/Reservation Cell for information.

(Dr. Arun Kumar)
IGIMS, Patna - 14

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक- विश्व मोहन प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,
निदेशक,
इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना।

पटना, दिनांक- /06 /2011

विषय- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में डा० बेनी माधव का सेवानिवृति के उपरान्त पुनर्नियुक्ति (Re-employment) एवं विज्ञापन संख्या 11/स्टेनो- एडहॉक/स्था0/2010 के आलोक में आशुलिपिक के पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त करने के संबंध में।

महाशय,

बहरहाल, राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की समीक्षा के उपरांत निर्णय लिया है कि बिना विहित प्रक्रिया के अपनाए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के कार्यालय के आदेश संख्या 5394/प्रशा. दिनांक 30/11/2010 के द्वारा ग़ैर सृजित पद पर डॉ. बेनी माधव का दिनांक 30/11/10 के अपराह्न से सेवानिवृत के उपरांत पुनर्नियुक्ति के आदेश को निरस्त किया जाए. साथ ही, आशुलिपिक के पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है. सरकार ने यह आदेश चेतना मंच, पटना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रह्लाद पासवान के शिकायत पत्र के आलोक में दिया है. इस संबंध में विस्तृत पड़ताल करने के बाद स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव विश्व मोहन प्रसाद सिंह ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के निदेशक को जारी ज्ञापांक 1/आई018/2009. 341(1)स्वास्थ्य पटना, दिनांक 24/05/2011 को कहा है कि डॉ. बेनी माधव का सेवानिवृति के उपरांत पुनर्नियुक्ति एवं विज्ञापन संख्या 11 /स्टेनो- एडहॉक/ स्था0/2010 के आलोक में आशुलिपिक के पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त करने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है.

साथ ही सरकार ने निदेशक डॉ. अरुण कुमार से भी पूछा है कि डॉ. बेनी माधव की सेवानिवृति के उपरांत पुनर्नियुक्ति के लिए क्या ऐसी कोई हड़बड़ी या आकस्मिकता आ गई थी कि आदेश संख्या 5393/प्रशा. दिनांक 30/11/2010 द्वारा सेवानिवृति और उसी दिन अनुक्रमित आदेश संख्या 5394/प्रशा. दिनांक 30/11/2010 के द्वारा पुनर्नियुक्ति का आदेश पारित कर किया गया. आख़िर क्यों इसके लिए ज़रूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जबकि यह आवश्यक था. पत्र में सरकार की ओर से लिखा गया है कि पुनर्नियुक्ति के बाद संविदा पर नियत वेतन पर या किसी भी प्रकार से नियुक्ति वैसे व्यक्ति की ही होनी चाहिए जिनकी छवि बेदाग़ हो, लेकिन डॉ. बेनी माधव को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने प्रशासनिक पद से हटाने का आदेश दिया था. उच्चस्तरीय समिति में लिए गए निर्णय पर दोबारा उन्हें प्रशासनिक पद से हटाया गया, फिर भी वैसे व्यक्ति को प्रशासनिक पदाधिकारी के ग़ैर सृजित पद पर पुनर्नियुक्त कर दिया गया है. इस बीच, डॉ. बेनी माधव को यह एहसास हो गया था कि उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई हो सकती है. नतीजतन, उन्होंने 3 मई 2011 को ही इस्तीफ़ा दे दिया. जब डॉ. माधव को जानकारी मिली कि स्वास्थ्य विभाग से पुनर्नियुक्ति को निरस्त कर दिया है तो आनन-फ़ानन में 25 मई 2011 से ही संस्थान की नौकरी से फ़रार हो गए.

बहरहाल, संस्थान के निदेशक की इस मनमानी से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और सरकार की साख को बट्टा तो लग ही चुका है. ग़लत तरीक़े से नियुक्त डॉ. बेनी माधव तो पद से हटा दिए गए, लेकिन क्या उन्हें ग़लत ढंग से नियुक्त करने वाले डॉ. अरुण कुमार के ख़िलाफ़ सरकार कोई कार्रवाई करेगी?

shashishekhar@chauthiduniya.com

नदियों को कल-कल बहने दो, लोगों को ज़िंदा रहने दो. बेतवा और चंबल क्षेत्र में मछुआरों पर संकट भारी साबित हो रहा है.

मरती नदियां, उजड़ता बुंदेलखंड

सुरेंद्र अग्निहोत्री

चंबल, नर्मदा, यमुना और टोंस आदि नदियों की सीमाओं में बसने वाला क्षेत्र बुंदेलखंड तेज़ी से रेगिस्तान बनने की दिशा में अग्रसर है. केन और बेतवा को जोड़कर इस क्षेत्र में पानी लाने की योजना मुश्किलों में फंस गई है. जो चंदेलकालीन हज़ारों तालाब बुंदेलखंड के भूगर्भ जल स्रोतों को मज़बूती प्रदान करते थे, वे पिछले दो दशकों के दौरान भू-माफ़िया की भेंट चढ़ गए हैं. अकाल की विभीषिका से जूझ रहे बुंदेलखंड में सरकारी पैकेज की खुली लूट का भयानक मंज़र देखने को मिल रहा है. बुंदेलखंड की धड़कन मानी जाने वाली बेतवा नदी के साथ हो रही छेड़छाड़ से जल संकट बढ़ गया है. रायसेन के पास शराब फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण से नदी का जल ज़हरीला हो रहा है. जालौन और झांसी में बालू माफ़िया के कारण सबसे बड़ा संकट बेतवा नदी पर है. झांसी में बजरी की बढ़ती मांग और चढ़ते दामों के चलते अवैध खनन बढ़ गया है. खनिज व राजस्व विभाग और पुलिस की मिलीभगत से आसपास की नदियों से दर्जनों ट्रैक्टर बजरी अवैध रूप से शहरों में पहुंच रही है. पहूज एवं बेतवा नदी के घाटों से तो बजरी कानपुर और उरई तक पहुंच रही है. सबसे नज़दीक पहूज नदी है, जो अवैध खनन करने वालों के निशाने पर है. इस नदी के घाट अवैध खनन के मुख्य क्षेत्र हैं. इसके साथ ही बेतवा नदी के विभिन्न घाटों पर भी अवैध खनन किया जा रहा है. रामनगर घाट से तो डंपरों बजरी शहर में आती है. महोबा में सूखे के चलते तालाबों में धूल उड़ रही है. मवेशी प्यास बुझाने के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं. एक दर्जन से अधिक जानवर मर चुके हैं. लोग अपने पालतू पशुओं को कौड़ियों के दाम बेचने को मजबूर हैं. प्रशासन नदी और निजी नलकूपों से जहां-तहां तालाब भराकर काम चला रहा है.

यह हाल किसी एक गांव का नहीं है, बल्कि दर्जनों ऐसे गांव हैं, जो पानी की कमी से बेहाल हैं. मवेशियों की प्यास का अंदाज़ा शायद किसी को नहीं होता, तभी तो बिना कोई शिकवा-शिकायत प्यास से तड़प-तड़प कर उन्होंने अपनी जान दे दी. पनवाड़ी ब्लॉक के गांव धवार में प्यास से 10 मवेशियों की मौत हो गई. एसडीएम विंध्यवासिनी राय एवं बीडीओ दीनदयाल अनुरागी ने भी इन मवेशियों की मौत का कारण प्यास माना. खैरोकलां में भी क़रीब आधा दर्जन मवेशी प्यास से दम तोड़ चुके हैं. मवेशियों की मौत से लोग इस क़दर सहमे हुए हैं कि वे अपने जानवर औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं. कई स्थानों पर नदी की जलधारा गड्ढों में सिमट गई है. बीच धारा में मशीन के सहारे बालू निकाल कर जलस्रोत ख़त्म कर दिए गए हैं. बालू के धंधे के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है. अभी तक इस मामले में हमीरपुर बदनाम था, लेकिन पिछले कई वर्षों से जालौन भी उसी ढर्रे पर चल रहा है. यहां बालू खनन के दर्जन भर से अधिक घाट हैं, जिन पर बसपा समर्थक लोगों का क़ब्ज़ा है. खनन के नाम पर नियम-क़ानूनों की अवहेलना देखनी हो तो वह बुंदेलखंड में देखी जा सकती है. उच्च न्यायालय की बार-बार चेतावनी के बावजूद यहां नदी की शेष धारा तक खनन कार्य खुलेआम हो रहा है. बेतवा नदी के अस्तित्व पर सबसे अधिक संकट जालौन और हमीरपुर में देखने को मिल रहा है. यहां नदी की जल धारा के बीच ही खनन कार्य कराया जा रहा है, जबकि इस पर रोक के निर्देश ज़िलाधिकारी ने दे रखे हैं.

पिछले दिनों नवरात्र के दौरान भेड़ी घाट में एक नाव डूबने से श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी. जांच के बाद यह बात सामने आई कि ज़रूरत से ज़्यादा बालू निकालने के चलते नदी में काफ़ी गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जो ऐसी दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं. सिर्फ़ बेतवा ही नहीं, केन, पहूज, सिंध, घसान, सुखनई, शहजाद, सजनाम, जामनी, सतार, बंडई, बबेड़ी, यमड़ार, खैड्डुर, मंदाकिनी और बागेन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. ललितपुर के मड़ावरा वन प्रभाग क्षेत्र की बंडई नदी जीव-जंतुओं और आदिवासियों के जीवन का एकमात्र सहारा थी. यह सहारा छिन जाने से सिर्फ़ आदिवासियों को ही नहीं, अपितु वन्य जीवों को भी गहरा धक्का लगा. इस प्रभाग में रहने वाले जंगली जानवर सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन करने के लिए विवश हो गए. बंडई नदी की यात्रा भले ही लंबी नहीं थी, लेकिन उसने मड़ावरा ब्लॉक के इस क्षेत्र में, जहां लोग जाने से डरते हैं, जंगली जानवरों को हमेशा जीवन दिया. मंदाकिनी चित्रकूट का जीवन स्रोत है. आज स्थिति यह है कि मंदाकिनी नदी का पानी राजापुर की ओर नहीं जा रहा. धवैन, चंदार्गाहना और बनकट आदि गांवों से नदी का सूखना प्रारंभ हो जाता है. पास में केवटों का पुरवा बड़ी तरिया है. वहां की कंचन कहती हैं कि हमारे गांव का जीवन कैसे चलेगा. नदी सूखते ही कुएं भी सूख गए. नदी में भरा पानी सड़ने लगा है. भोले-भाले बुंदेलखंडी लोग कहते हैं कि मास्टर साहब लिखा-पढ़ी नहीं करत, का करी? नारायणपुर हार में पशुओं को चराने आए दया राम ने कहा कि हमारे पूरे इलाक़े का पानी सूख गया है. यहां पानी के आस में आए तो देख रहे हैं कि नदी सूख गई. पिछले कई वर्षों से हम आ रहे हैं, लेकिन कभी सोचा न था कि मंदाकिनी भी सूख जाएगी. नारायणपुर के श्याम सुंदर और चंद्र प्रकाश ने कहा कि हम लोगों को अहंकार था कि नदी कभी नहीं सूखेगी. अब पूरा गांव भयभीत है कि खेती कैसे होगी. सबसे बड़ी समस्या है पशुओं के पानी की. नदी में जमा पानी सड़ने लगा है, ज़हरीला हो रहा है. गोदा घाट के सुंदर केवट नदी का पानी पीकर बीमार हो गए थे. चंदार्गाहना से लेकर सूरज कुंड तक कुल 7 दहार हैं. केवल दहारों में पानी है. सबसे ज़हरीला पानी सूरज कुंड में है, जहां शव डाले जाते हैं. सूरज कुंड आश्रम के महंत रामचंद्र दास ने कहा कि यह काम सरकार और पंचायत का है कि वे इसे रोकें, यह प्रथा ग़लत है. बरवारा के धर्मराज ने कहा कि नदी को जो ऊपर बांधा गया है, वह बहुत बड़ा अपराध है. नदी को यदि प्राकृतिक तरीक़े से बहने दिया जाए तो वह अपने आप बरसात में गंदगी को बहा ले जाती है. आज नदियों के सूखने का सबसे बड़ा कारण बांध हैं. सूरज कुंड में नया चेकडैम क्यों बनाया रहा है? सरकार हमारी राय क्यों नहीं लेती?

यह हाल किसी एक गांव का नहीं है, बल्कि दर्जनों ऐसे गांव हैं, जो पानी की कमी से बेहाल हैं. मवेशियों की प्यास का अंदाज़ा शायद किसी को नहीं होता, तभी तो बिना कोई शिकवा-शिकायत प्यास से तड़प-तड़प कर उन्होंने अपनी जान दे दी. पनवाड़ी ब्लॉक के गांव धवार में प्यास से 10 मवेशियों की मौत हो गई.

वैसली नदी काली पहाड़ी क्षेत्र के पश्चिम से निकलती है और सुपावली तक यह उत्तर दिशा में बहती है. इसमें कई बरसाती नदियां और नाले मिलते हैं. सुपावली से आगे यह मुरार नदी में संगम करती है. इन दोनों नदियों का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है. वैसली सिंध नदी की सहायक नदी हुआ करती थी. सिंध नदी ग्वालियर में आर-पार बहने वाली नदी है. यह विदिशा ज़िले में सिरोंज के मालवा पठार से निकल कर दक्षिण में ग्वालियर में प्रवेश करती है. मार्ग में पार्वती, नून, जोर एवं छछूंद आदि नदियां और कई बरसाती नाले इसमें मिलते हैं. उत्तर पूर्व में क़रीब दो सौ मील बहने के बाद यह यमुना में संगम करती है. पार्वती नदी शिवपुरी ज़िले से निकल कर नरवर के पास ग्वालियर में प्रवेश करती है. यहां इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, जो हरसी बांध के नाम से प्रसिद्ध है. शिवपुरी से जिस स्थान पर यह ग्वालियर ज़िले में प्रवेश करती है, वहां भी इसका पानी बांधा गया है, जो ककेटो बांध के नाम से प्रसिद्ध है. पार्वती डबरा के पास पवाया गांव में सिंध नदी से संगम करती है. नून पनिहार गांव के पास से निकल कर दक्षिण में बहने के बाद पूर्व की ओर मुड़ जाती है और सिंध में मिल जाती है. छछूंद नदी आंतरी के पास पूर्व में पहाड़ी से निकल कर दक्षिण की ओर बहती है और आगे सिंध में संगम करती है. कई सामाजिक संगठन केन-बेतवा गठजोड़ के ख़िलाफ़ सत्याग्रह कर रहे हैं. उनका कहना है कि प्राकृतिक नदियों का ऐसा अनर्गल गठजोड़ बुंदेलखंड को विनाश की ओर ले जाएगा. वे कहते हैं कि केन-बेतवा नदी गठजोड़ परियोजना पर विराम लगाया जाए. बीते 16 अप्रैल को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री जयराम रमेश ने पन्ना टाइगर रिज़र्व पार्क को इस गठजोड़ से हानि पहुंचने के चलते अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से मना कर दिया है. बुंदेलखंड में चल रही बड़ी बांध परियोजनाओं जैसे केन-बेतवा लिंक, अर्जुन सहायक बांध परियोजना महोबा, बांदा एवं हमीरपुर प्रस्तावित क्षेत्र से विस्थापित किसानों को उचित मुआवज़े और पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए. स्थायी रोज़गार हेतु शजर उद्योग, बांदा कताई मिल, बुनकर एवं शिल्प कला, बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री चित्रकूट और महोबा-छतरपुर पान उद्योग को पुनर्स्थापित करते हुए पलायन की मार से टूट चुके बुंदेलखंड को बचाने की ज़रूरत है.

नदियों को कल-कल बहने दो, लोगों को ज़िंदा रहने दो. बेतवा और चंबल क्षेत्र में मछुआरों पर संकट भारी साबित हो रहा है. यह बात झांसी में जंतु विज्ञानियों एवं विशेषज्ञों ने एक संगोष्ठी में कही है. उनका मानना है कि बुंदेलखंड में मछलियों एवं अन्य जल जीवों पर मंडरा रहे ख़तरे पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है. बेतवा और चंबल की सहायक नदियों का प्रवाह सिकुड़ने से उत्पन्न समस्या पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह क्षेत्र रेगिस्तानी टीले में बदल सकता है. झांसी के उमेश शुक्ल ने बुंदेलखंड स्तर पर जल-जैव विविधता में हो रहे बदलाव को ख़तरनाक बताया. भोपाल के प्रो. डी के बेलसारे ने नदियों में पानी की कमी से मछुआरों को हो रही दिक्क़तों पर चर्चा करते हुए कहा कि पर्याप्त मात्रा में मछलियां न होने से मछुआरों के अलावा जल में रहने वाले अन्य जीवों के भी सामने समस्या पैदा हो गई है. सदा नीरा नदियां लापरवाही के कारण मर गई हैं. इसका असर कृषि के साथ-साथ नागरिक जीवन पर भी पड़ा है. बुंदेलखंड के पहाड़ नंगे हो गए हैं और ज़मीन बंजर. इसके चलते बीहड़ों का विस्तार हो रहा है. खेत-खलिहानों के साथ गांव भी उजड़ रहे हैं. मूल रूप से नदी और कुंआ कभी नहीं मरते, आदमी ही इसे मरा समझ लेता है. प्रयास किए जाएं तो इन नदियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है. ऐतिहासिक कुओं और बावड़ियों को भी रीचार्ज करके इनका पानी लौटाया जा सकता है, लेकिन भागीरथ बनने के लिए कोई तैयार नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

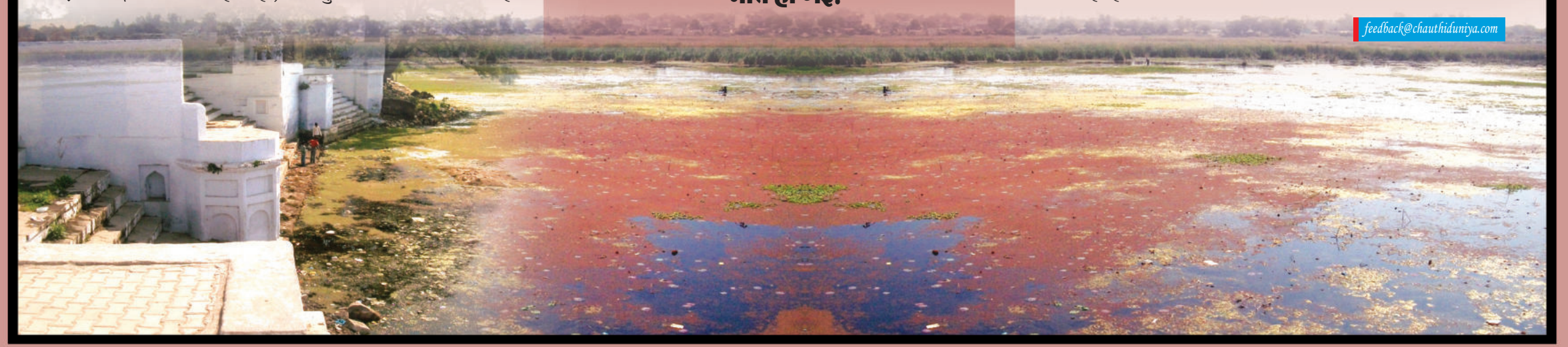

जहां कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती, वहीं कांग्रेस इस तूफ़ान से बड़ी आसानी से निकल आई. लगातार विपक्ष कांग्रेस के जाल में फंस कर कांग्रेस का ही तारणहार बन जाता है.

चीन में एक मिलावटी नेटवर्क द्वारा अक्टूबर 2007 से अक्टूबर 2008 के मध्य लगभग 600 टन नक़ली सूखा दूध बनाकर बेचा गया था. इस दूध के सेवन से 6 बच्चों की मौत हो गई थी.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

संपत्ति के वितरण की विभिन्न प्रणालियां

एक योजना जो आमतौर पर बतलाई जाती है और जो काम करने वाले मज़दूरों को मान्य और प्रिय है वह यह है कि जो आदमी अपने परिश्रम से जितना द्रव्य कमाए या पैदा करे वह उसके पास रहने दिया जाए. दूसरे कई व्यक्ति कहते हैं जो जितने का पात्र है उतना उसे मिले, जिससे कि आलसी, बेकार, कमज़ोर, शिथिल आदमियों को कुछ न मिले और वे नष्ट हो जाएं. अच्छे मेहनती और तंदुरुस्त आदमियों को सब कुछ मिले और वे ही जीवित रहें. कुछ का वही प्राचीन रूढ़िवादी अभिप्राय है कि जिसके पास ताक़त हो वह ले ले और जो संभाल कर रख सकते हों वे ही रखें, इस अभिप्राय वाले खुलेआम ऐसे विचार आधुनिक युग में प्रगट नहीं करते. कुछ का कहना है कि साधारण मानवों को जीवित रहने के लिए जितना आवश्यक है उतना उन्हें देना चाहिए, जिससे भगवान ने उन्हें जिस स्थिति में पैदा किया है उसमें फेरफार न हो. बाक़ी सारा समृद्ध समाज ले ले. यह अभिप्राय रखने वाले भी आज खुलकर नहीं बोल पाते, जबकि 50 वर्ष पहले तक ये खुलेआम घोषणा करते थे. कुछ लोगों का कहना है कि हम सबको वर्गों में विभाजित होना चाहिए और प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को उस वर्ग के हिसाब से बराबर-बराबर बांट देना चाहिए, तात्पर्य यह हुआ कि मज़दूर वर्ग को 50 रुपए माहवार, दक्ष कारीगर को 200 रुपए माहवार, प्रोफेसर या धर्मोपदेशक को 1000 रुपए माहवार मिले. उनकी पत्नियां और बच्चे उनसे जो भी ले सकें लें. कुछ यह भी कहते हैं कि जिस तरह से चलता है चलने दो. पर समाजवादी कहता है कि हर व्यक्ति को बराबर-बराबर बांट दो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे वृद्ध हो या युवा, कुछ भी काम करता हो, किसी भी ख़ानदान का हो.

यह आख़िरी योजना या ऊपर लिखी कोई भी योजना आपको अप्रिय हो तो कृपया क्षमा करें. आप ही बतलाइए कैसी स्कीम रखी जाए? मैं तो आपके सामने वे ही योजनाएं पेश कर रहा हूं, जो विश्व में कार्यरूप में लाई गई हैं, आज़माई जा चुकी हैं. इनमें से एक भी मानने के लिए आपको बाध्य नहीं होना है, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, कोई इससे अच्छा सुंदर तरीक़ा सुझाइए?

पर यह बेकार की माथापच्ची कौन करे, कहकर दूर मत हट जाइए, क्योंकि यह बेकार की माथापच्ची नहीं है. यह बड़ा महत्व का विषय है. अगर आप स्वयं कोई अच्छा मार्ग नहीं दिखाएंगे तो दूसरे लोग मार्ग बताएंगे. हो सकता है वे अपने हित की बात बतलाएं—आपके फ़ायदे की नहीं. संभव है वे अपने हिस्से को ख़ूब सुरक्षित रखें, शायद उनके बतलाए हुए बंटवारे के हिसाब से आपको सर्वथा वंचित रह जाना पड़े. अतएव अत्यंत आवश्यक है कि आप यथाशीघ्र निर्णय कीजिए कि किस तरह का सामाजिक बंटवारा होना उपादेय है. विश्व बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी तेज़ी से बदल रही है. अब यदि ऐसे समय में सोच-समझ कर समस्या नहीं सुलझाएंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा. इसलिए जो आज़माई हुई प्रणालियां हैं वे आपके सामने एक-एक करके प्रस्तुत हैं. आगे के प्रकरणों में ऊपर लिखी सारी योजनाओं की पूरी छानबीन करेंगे, जिनको पढ़कर आप स्वयं निर्णय करें कि उनके पक्ष या विपक्ष में क्या-क्या कहा जा सकता है?

अच्छे मेहनती और तंदरुस्त आदमियों को सब कुछ मिले और वे ही जीवित रहें. कुछ का वही प्राचीन रूढ़िवादी अभिप्राय है कि जिसके पास ताक़त हो वह ले ले और जो संभाल कर रख सकते हों वे ही रखें, इस अभिप्राय वाले खुलेआम ऐसे विचार आधुनिक युग में प्रगट नहीं करते.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

राजनीति का पाखंडी और बनावटी चेहरा

कहते हैं, युद्ध के समय सबसे अधिक क्षति सत्य की ही होती है. भारतीय राजनीति में सत्य का समावेश नहीं रहा है. इसलिए हम इसे लेकर ज़्यादा चिंतित भी नहीं रहते, लेकिन पिछले दिनों हमें ज़बरदस्त रूप से छल कपट, बनावटीपन, आरोप-प्रत्यारोप और अतिश्योक्तिपूर्ण बातें देखने-सुनने को मिलीं. पहला मौक़ा था रामदेव मुद्दे पर सरकार द्वारा पलटी मारने का. पहले मंत्री ख़ुशामद करने और बाबा रामदेव का दर्शन करने एयरपोर्ट पहुंचे. फिर अचानक शनिवार की रात और रविवार की सुबह के बीच मंत्रियों का रवैया ही बदल गया. जिस किसी ने भी बाबा रामदेव के कार्यकलापों को नज़दीक से देखा उसे महसूस हो गया था कि बाबा यह लड़ाई हार रहे हैं. ऐसे में, सरकारी कार्रवाई करके उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि सफ़ाई से काम करना यूपीए सरकार की फ़ितरत में है ही नहीं. और इसलिए देर रात इस फिल्म के नायक के ऊपर ही नहीं, बल्कि वहां पर सोते हुए हज़ारों सहनायकों पर भी पुलिसिया डंडा बरसा.

यहां बल प्रयोग की ज़रूरत ही नहीं थी. और इसके बाद अतिश्योक्तिपूर्ण शब्द जैसे आपातकाल और जलियांवाला बाग़ कांड से इस घटना की तुलना करके विपक्ष ने अपने हाथ से एक अच्छा मौक़ा खो दिया. विपक्ष ने इस घटना से जुड़ी वैधानिक ज़िम्मेदारी पर सवाल ही नहीं उठाया. यह सवाल नहीं उठाया कि इस कार्रवाई के लिए कौन ज़िम्मेदार है और यह कार्रवाई किस आधार पर की गई और किसके आदेश पर यह सब हुआ. आख़िरकार, स्वतंत्र विचार और सभा करने के मूल अधिकार का हनन क्यों हुआ? आख़िर कब से अनशन करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ने लगी है? यह कौन तय करेगा कि एक योग शिविर ग़ैर राजनीतिक है, लेकिन एक अनशन राजनीतिक घटना है?

अगर इस घटना की जलियांवाला बाग़ कांड से तुलना की जाए तो इसे बचपना ही कहा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे सुषमा स्वराज के राजघाट पर नाचने पर उंगली उठाना. यह कांग्रेस के पाखंड की पराकाष्ठा थी. सुषमा, आख़िर 1950 के दशक में आई फिल्म नया दौर के गाने पर ही थिरक रही थीं न कि मुन्नी बदनाम हुई जैसे आइटम गीत पर नाच रही थीं. सूफ़ी-संतों से लेकर मीरा तक धार्मिक गानों पर नाचते थे, लेकिन औरंगज़ेब की तरह कांग्रेस ने भी मानो किसी भी जगह ऐसे कार्यक्रमों पर निषेध लगाना शुरू कर दिया है. आख़िर क्यों न हो? राष्ट्रपिता की समाधि (राजघाट) को तो कांग्रेस ने अपनी बपौती समझ लिया है.

बहरहाल, कांग्रेस का पाखंड यहीं नहीं थमा. उसके प्रवक्ताओं ने रामदेव को आरएसएस का जन्मजात एजेंट तक बता डाला और बाबा से मिलने एयरपोर्ट पहुंचे मंत्रियों ने उन्हें ठग भी घोषित कर दिया. निश्चित ही बाबा रामदेव के विरुद्ध सरकार बहुत मोटी फाइल बनाएगी. आख़िर ऐसा क्यों न हो? बाबा रामदेव ने तो एक ऐसा नैतिक अपराध किया है जो अक्षम्य है. रामदेव ने कांग्रेस के हाथों बिकने से मना जो कर दिया था, जैसे ए राजा और कनिमोड़ी के संदर्भ में हुआ. कांग्रेस अपने मित्रों को लेकर भाग्यशाली नहीं रही है और वहीं बाबा अपने शत्रु के मामले में भाग्यशाली रहे हैं. स्वत: ही बाबा ख़लनायक की भूमिका में आ गए, जब उन्होंने 11 हज़ार सशस्त्र सैनिकों की सेना बनाने की ग़ैर ज़िम्मेदाराना घोषणा की. क्या बाबा सचमुच इसे लेकर गंभीर हैं? बाबा को ममता बनर्जी से अनुरोध करना चाहिए कि वह उन्हें नक्सलियों से मिलवाएं, ताकि बाबा पता कर सकें कि सरकार को तंग करने के लिए कितने सीधे-सादे लोगों को गुमराह करना पड़ता है.

जहां कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती, वहीं कांग्रेस इस तूफ़ान से बड़ी आसानी से निकल आई. लगातार विपक्ष कांग्रेस के जाल में फंस कर कांग्रेस का ही तारणहार बन जाता है. सिर्फ़ एक ख़तरा है कि दिग्विजय सिंह आरएसएस को एक बहुत ही ख़तरनाक संगठन बताने में जुटे हुए हैं, जबकि यह महज़ निकर पहने चंद ऐसे लोग हैं, जो 1750 के मराठा साम्राज्य को पुन:स्थापित करने का दिवा-स्वपन देख रहे हैं. आरएसएस को एक-एक ख़तरे के रूप में देखने या बताने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं. यदि सचमुच ऐसा है तो यूपीए ने पिछले सात साल में इस ख़तरे से निपटने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? क्या वह इस बात का इंतज़ार कर रही है कि तहव्वुर राणा और हेडली के मामले की तरह ही सीआईए आकर आरएसएस के ख़िलाफ़ केस दर्ज करेगा? कांग्रेस सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों को लागू कर पाने में असमर्थ रही है. वह मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाने में असफल रही है. इसलिए सांप्रदायिकता के मुद्दे को ज़िंदा रखना कांग्रेस की मजबूरी है, ताकि वह मुस्लिम वोट को अपने पाले में ला सके. इस बीच, देश से बाहर निर्वासित ज़िंदगी बिताते हुए आज़ाद भारत के सबसे बड़े चित्रकार मक़बूल फ़िदा हुसैन की मृत्यु हो गई. उन्हें इस देश में न तो बजरंग दल और न ही धर्मनिरपेक्ष यूपीए-1 और यूपीए-2 के ठगों से सुरक्षा मिली. ज़ाहिर है, उनके लिए किसी एक मुस्लिम वोट का कोई महत्व नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

मलियाना और हाशिमपुरा शर्मनाक घटनाएं हैं

वास्तव में मलियाना और हाशिमपुरा की घटनाएं तत्कालीन उत्तर प्रदेश और केंद्रीय सरकारों के लिए शर्मनाक हैं. तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने इस मामले में जो किया वह गुजरात की घटनाओं से किसी प्रकार भी कम नहीं है, लेकिन मीडिया को केवल गुजरात याद है. चौथी दुनिया ने इस मामले को उठाकर अच्छा किया है. इस कांड के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार भी वीर बहादुर सिंह की न तो भर्त्सना की और न ही कोई कार्यवाही की. बेगुनाह मुसलमानों की जान की क़ीमत केवल बीस हज़ार रुपए दी गई. वह भी केवल बहुत थोड़े से लोगों को. सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की शीघ्र प्रकाश्य डायरी में यह स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और उन्हें जान बूझकर पिछड़ा व अशिक्षित बनाए रखा. मुसलमानों के पढ़े लिखे तबक़े द्वारा इस बात को समझते हुए अपनी क़ौम को जागरूक करना चाहिए.

अनिल गुप्ता, *मेरठ, उत्तर प्रदेश*

■ संतोष भारतीय जी, जब धुरंधर पत्रकार और संपादक मौन धारण कर गए थे, तब आप ही इस मामले को सामने लाए थे. आप ही के कारण इसकी जांच बिठाई गई थी, मगर इस व्यवस्था को क्या कहें कि आप और हम तथा मेरठ के लोग आज तक इंसाफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं. इस बारे में श्री वीएन राय भी हाशिमपुरा 22 मई के नाम से एक किताब लिख रहे हैं. मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों की बदौलत ही इस मामले में कुछ हो सकेगा.

डॉ. मेहरउद्दीन ख़ान, *ईमेल से*

जल, ज़मीन, जंगल बचाओ

चौथी दुनिया पढ़ा. सिर्फ़ नोएडा नहीं, पूरे देश के किसान हिंसक हो सकते हैं, पसंद आया. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक है. क़ानूनन हम एक पेड़ भी नहीं काट सकते. इसके बावजूद सारे जंगल कट गए, कुएं, तालाब पट गए. गौशाला, कृष्ण लीला संस्कृत पाठशाला, भैरोनाथ, रामलीला और मज़ारों आदि पर अवैध क़ब्ज़े हो गए. भू माफ़िया आतंकवादियों ने भी बड़े देशद्रोही हैं. देश में नेता, नौकरशाह, अपराधी और पूंजीपतियों का गठजोड़ जनता को मूर्ख बना रहा है.

राजकुमार, *बरेली, उत्तर प्रदेश*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

भारत सचेत रहे

चीन भारत के लिए नई मुश्किलें पैदा कर रहा है. चीन में ज़बरदस्त सूखे और अकाल के हालात हैं और इसी के मद्देनज़र वह ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव फिर मोड़ने की योजना बना रहा है. चीन ने हालांकि अभी तक दावा किया है कि उसका नदी का बहाव मोड़ने का कोई इरादा नहीं है. भारत के विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को चीन द्वारा रोकने के मामले में उन्होंने बीजिंग में भारतीय राजनयिक से रिपोर्ट मांगी है. उनका कहना है कि वे स्थितियों का आंकलन कर, उपयुक्त क़दम उठाएंगे. चीन ने पिछले साल अधिकृत रूप से माना था कि वह ब्रह्मपुत्र नदी (चीन में राकलोंग सांगपो के नाम से विख्यात) पर 1.2 बिलियन डॉलर (54 अरब रुपए) की लागत से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन बना रहा है, लेकिन इससे डाउन स्ट्रीम में बसे भारत और बांग्लादेश में नदी के बहाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. चीन पिछले पांच दशक का सबसे भीषण सूखा झेल रहा है. यांगट्ज नदी में पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है और बिजली की पैदावार न्यूनतम स्तर पर है. दक्षिण और मध्य चीन के क़रीब दस प्रांतों में भीषण समस्या पैदा हो गई है, सरकार पर दबाव है कि वह ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने का काम फिर शुरू करे. डैम बनाने का काम पहले रोक दिया गया था. सरकार को चीन से सचेत रहने की ज़रूरत है.

मो. मख़सूद इनामदार, *नांदेड़, महाराष्ट्र*

सरकार की वादा ख़िलाफ़ी

मैं एक सीमांत किसान हूं. क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा से आशान्वित था कि इसी जीवन में क़र्ज़ मुक्त हो जाऊं गा, लेकिन भविष्य अंधकारमय ही रह गया. सरकार ने लघु व सीमांत किसानों को क़र्ज़ मुक्त करने का ऐलान तो किया, किंतु दिशा-निर्देश बनाने वाली समिति ने किसानों को धोखा दिया. किसान आज भी आस लगाए बैठा है कि वह क़र्ज़ मुक्त हो जाएगा. आपसे अनुरोध है कि अपने अख़बार के माध्यम से क़र्ज़ माफ़ी के नाम पर की गई सरकार की वादा ख़िलाफ़ी को सबके सामने लाकर देश के 70 फ़ीसदी किसानों की आवाज़ उठाएं.

अतुल कुमार, *मिल्कीपुर, उत्तर प्रदेश*

■ कृषि प्रधान देश का किसान अपनी दयनीय दशा के चलते इससे दूर भाग रहा है. यह निश्चित है कि लागत के आधार पर कृषि घाटे की हो गई है. ऐसी स्थिति में वह क़र्ज़ अदा नहीं कर सकता. सरकार ने छोटे-मझौले किसानों को क़र्ज़ माफ़ी के नाम पर अच्छा झुनझुना पकड़ा दिया जो न बज रहा है और न ही टूट रहा है. चौथी दुनिया में किसानों की इस समस्या को उठाया गया है, जिस पर खोज करने की और ज़्यादा ज़रूरत है. रोज़-रोज़ बैंकों द्वारा धमकी दी जा रही है.

हीरहर प्रसाद, *मिल्कीपुर, उत्तर प्रदेश*

राजकमल प्रकाशन समूह
1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फ़ोन 011-23274463, 23288769, फ़ैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email: info@rajkamalprakashan.com
लेखन विधा सम्मान 2011
'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जाने वाली 700 रुपए की किताबें

पाठक पूरा नाम, पता व फ़ोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:
चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

पत्रकारिता की क़ीमत जान हो सकती है

पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है, जिसकी क़ीमत क्या है, अभी यह तय नहीं हुआ है. पत्रकारिता में जो लोग आते हैं उन्हें कम से कम यह ध्यान में रखकर आना चाहिए कि पत्रकारिता के पेशे की क़ीमत उनकी अपनी जान हो सकती है. मुंबई में मिड डे के पत्रकार जेडे की हत्या इस सत्य को एक बार फिर रेखांकित कर रही है. जेडे निर्भीकता से अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाह कर रहे थे. बुनियादी तौर पर वह क्राइम रिपोर्टर थे और मुंबई के अंडरवर्ल्ड और मुंबई पुलिस के गठजोड़ तथा कौन सफ़ेदपोश ऐसे हैं, जो अपराध को प्रश्रय देते हैं, इसके बारे में वह लगातार लिखते रहते थे. उनके पास जानकारियां भी थीं और ज़्यादातर जानकारियां उनके पास अपने आप पहुंच रही थीं. पत्रकारिता में एक ऐसी स्थिति आती है जब आप ख़ुद को स्थापित कर लेते हैं तो सारी ख़बरें अपने आप चलकर आ जाती हैं. जेडे इसी श्रेणी के पत्रकार थे. जेडे को श्रद्धांजलि देने के साथ हम पत्रकारिता के अपने अनुभव के बारे में बात करना चाहेंगे. हमारे बीच में ऐसे पत्रकारों की भरमार है, जो पत्रकारिता के बुनियादी पेशे की ज़िम्मेदारी का निर्वाह करने के बजाय पीआर जर्नलिज़्म यानी पब्लिक रिलेशन जर्नलिज़्म करने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं.

बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेस कटिंग के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं. ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं, जो फील्ड में जाते हैं और तथ्यों की जांच पड़ताल करते हैं और सत्य के साथ खड़े होते हैं. जेडे सत्य के साथ खड़े होने वाले पत्रकारों में से एक थे. इसलिए जेडे की शहादत हमें कई सीख देती है. पहली सीख यह देती है कि अगर सही पत्रकारिता करने वाले लोग एकजुट नहीं हुए तो अपराध, ख़ासकर सफ़ेदपोश लोगों के साए में चलने वाला अपराध उन्हें अभी और परेशान करेगा. जेडे की मौत यह भी सीख देती है कि सही पत्रकारिता करने वाले लोग अगर आसान ज़िंदगी जीना चाहेंगे तो यह उनके लिए संभव नहीं होगा. अगर हम इतिहास में देखें तो पहला नाम याद आता है गणेशशंकर विद्यार्थी का, जिनकी हत्या कानपुर में सत्य लिखने की वजह से हुई थी.

हिंदुस्तान में बहुत सारे पत्रकार सिर्फ़ इसलिए मार दिए गए, क्योंकि उन्होंने अपने क़स्बे में चीनी की चोरबाज़ारी के बारे में रिपोर्टें लिखी थीं. बांदा में रामकृष्ण गुप्ता ऐसे पत्रकार थे, जिनकी इसी वजह से हत्या हुई, क्योंकि वह स्थानीय कालाबाज़ारियों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखते थे. वह दैनिक अख़बार के पत्रकार थे. फ़ेहरिस्त लंबी है, हर प्रदेश में, हर ज़िले में भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त ऐसे संगठित गिरोह मिल जाएंगे, जिन्होंने सच लिखने वाले पत्रकारों पर हमले कराए.

पत्रकारों की जानें कई और वजहों से भी जाती हैं. अगर आप दंगा कवर करते हैं, युद्ध कवर करते हैं, भूकंप कवर करते हैं तो कहीं ऐसी घटना हो जाती है, जिसमें आपकी जान जाने का ख़तरा रहता है और यही हमारे पेशे की क़ीमत है. मुझे याद है, अफ़ग़ानिस्तान में लड़ाई चल रही थी. मैं उसे कवर कर रहा था. मैंने यह घटना अपनी आंखों से देखी. एक पत्रकार कवर कर रहा था, दूसरा पत्रकार उसके साथ था. वह पीस टू कैमरा कर रहा था. अचानक एक गोली आई और कैमरे के सामने बोलने वाले पत्रकार को लग गई और वह वहीं गिर गया. मैं सलाम करता हूं, दूसरे पत्रकार को जिसके हाथ में कैमरा था. उसने हाथ से कैमरा गिरने नहीं दिया और शूटिंग जारी रखी. उसी ने बताया कि किस तरह पीस टू कैमरा करने वाले को गोली लगी और उनके पीछे क्या घटनाएं चल रही थीं.

आज भी हिंदुस्तान में हर जगह ईमानदारी से पत्रकारिता का धर्म निभाने वाले लोग हैं, लेकिन उन सब पर अपनी-अपनी तरह के ख़तरे मंडरा रहे हैं. कहीं किसी ज़िले में ठेकेदार, नेता और प्रशासन का गठजोड़ है, तो कहीं प्रदेश स्तर पर नेताओं और अपराधियों की साठगांठ है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माफ़िया उन पत्रकारों पर नज़र रखे हुए है, जिनकी क़लम पैनी और सख़्त है. पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है, जिसे समाज और आम लोगों ने मान्यता और इज़्ज़त दी है. संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि पत्रकारिता देश का चौथा खंभा है. इसे जन मान्यता मिली हुई है. न ही कहीं यह लिखा हुआ है और न ही ऐसा कोई नियम है कि पत्रकार किसी को कहीं भी रोक सकता है, लेकिन जनमानस ने समाज में पत्रकारों को यह हक़ दिया है कि वह कहीं भी किसी को रोककर सवाल पूछ सकता है. पत्रकार की यह समानता कोई दूसरा वर्ग या किसी दूसरे पेशे से जुड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता है. पत्रकार चाहे तो किसी भी ज़िलाधिकारी या मंत्री को रोककर, कह सकता है कि मैं अमुक अख़बार या पत्रिका का संवाददाता हूं, मुझे आपसे सवाल पूछना है. वह आदमी रुकेगा और वह कह सकता है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है. हो सकता है कि वह बिना रुके और अनसुना करके भी चला जाए. यह ताक़त पत्रकारों को समाज ने दी है. समाज ने ही पत्रकारों को यह भी ताक़त दी है कि वे इस लोकतंत्र को चलाने वाले चौथे खंभे के रूप में जाने जाएं. जनता के किसी वर्ग को जब अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, या किसी नेता या प्रशासन के अधिकारी के सामने उसकी सुनवाई नहीं होती है तो उसके सामने सिर्फ़ एक रास्ता बचता है कि वह किसी पत्रकार या अख़बार वालों के पास जाए और अपनी समस्या बताए.

जेडे सत्य के साथ खड़े होने वाले पत्रकारों में से एक थे. इसलिए जेडे की शहादत हमें कई सीख देती है. पहली सीख यह देती है कि अगर सही पत्रकारिता करने वाले लोग एकजुट नहीं हुए तो अपराध, ख़ासकर सफ़ेदपोश लोगों के साए में चलने वाला अपराध उन्हें अभी और परेशान करेगा. जेडे की मौत यह भी सीख देती है कि सही पत्रकारिता करने वाले लोग अगर आसान ज़िंदगी जीना चाहेंगे तो यह उनके लिए संभव नहीं होगा. अगर हम इतिहास में देखें तो पहला नाम याद आता है गणेशशंकर विद्यार्थी का, जिनकी हत्या कानपुर में सत्य लिखने की वजह से हुई थी.

आज भी लोगों की समस्याएं सुनने वाले पत्रकार हैं, जो उन्हें अपने अख़बार या अपनी पत्रिका में जगह देते हैं. इसलिए पत्रकारिता के पेशे का सम्मान जनता के मन में बहुत ज़्यादा है. लोग आपस में कहते भी हैं कि अगर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी या अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम अख़बार वालों के पास चले जाएंगे. अख़बार में प्रकाशित जन समस्याओं पर सरकार और प्रशासन कार्यवाही भी करता है. आज भी अख़बारों में छपी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है और अपनी तरफ़ से नोटिस भी जारी करता है.

जेडे की मौत एक ऐसे पत्रकार की शहादत है, जो बड़ा क्राइम रिपोर्टर था, लेकिन उसके पास भी मोटरसाइकिल थी. वह चाहते तो कहीं से भी समझौता करके अपने लिए मुंबई में अच्छी सुविधाएं जुटा सकते थे, लेकिन जेडे ने ऐसा नहीं किया. जेडे की मौत भी मोटरसाइकिल पर चलते हुए उन लोगों की वजह से हुई, जो सही पत्रकारिता से बुरी तरह घबरा जाते हैं. इसमें कोई पुलिस अधिकारी शामिल है, पता नहीं. इसमें कोई अंडरवर्ल्ड शामिल है, पता नहीं. जेडे की हत्या की जांच कहीं पहुंच भी पाएगी, पता नहीं, क्योंकि इतने सारे पत्रकार जिन्हें दुख हुआ है, वे भी रोज़ी रोटी के काम में थोड़े दिनों में लग जाएंगे और जेडे का नाम सिर्फ़ यादों में रह जाएगा. लगता है कि उनके हत्यारों की तलाश को लेकर पड़ने वाला दबाव भी थोड़े दिनों में कम हो जाएगा, लेकिन जेडे जैसी मौत और जेडे जैसी पत्रकारिता करने वाले लोग समाज में हमेशा इज़्ज़त की निगाहों से देखे जाएंगे. पत्रकारिता के पेशे की यही क़ीमत है.

डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि वह अपने मरीज़ों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा. बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन यह सच नहीं है. सच वह डॉक्टर है जो 24 घंटे अपने मरीज़ों के लिए उपलब्ध रहता है. पुलिस के पेशे की क़ीमत है 24 घंटे क़ानून व्यवस्था के ऊपर नज़र बनाए रखे. फ़ौज की क़ीमत है 24 घंटे अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहे. फायर ब्रिगेड के पेशे की क़ीमत है 24 घंटे आग से जूझने के लिए तैयार रहे. वहां न बीमारी का बहाना चलता है और न ही तबीयत ख़राब होने का. पत्रकारिता के पेशे की क़ीमत है अपनी जान. जेडे की मौत ने इसे साबित किया है. जिन लोगों को पत्रकारिता के पेशे में आना है, उन्हें इस सबक़ को दोबारा याद करना चाहिए. वे पीआर जर्नलिज़्म करने वालों की सेना में शामिल हो जाएं या फिर सही पत्रकारिता करने वाले लोगों के पदचिन्हों पर चलें और अगर सही पत्रकारिता करने वालों के पदचिन्हों पर चलना है तो इज़्ज़त मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा. हो सकता है कहीं से कोई गोली भी मिल जाए. जेडे को हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और जेडे से यह वादा करते हैं कि हम उस क़तार में हमेशा बने रहेंगे, जो सच्ची पत्रकारिता की पक्षधर है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

निर्मल रानी

मिलावटख़ोरों को फांसी हो

हमारे देश में इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर व्यापक बहस छिड़ी हुई है. देश में फैला मिलावटख़ोरी व नक़ली वस्तुएं बेचने वालों का नेटवर्क भी इसी भ्रष्टाचार का एक सर्वप्रमुख अंग है, परंतु बावजूद इसके कि लगभग प्रत्येक भारतीय इस समय कहीं न कहीं मिलावटख़ोरी या नक़ली वस्तुओं की ख़रीद फ़रोख़्त का स्वयं शिकार हो रहा है. फिर भी यही भुक्तभोगी आम नागरिक इन राष्ट्रविरोधी मिलावटख़ोर माफ़िया के विरुद्ध अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रहा. इसका कारण जहां उपभोक्ताओं का असंगठित होना है, वहीं मिलावटख़ोर माफ़िया तंत्र का संगठित होना है. साथ ही शासन व प्रशासन तक पहुंचने वाले उनके लंबे हाथ भी इसका मुख्य कारण है. इसके अतिरिक्त इस संबंध में आने वाले अदालती फ़ैसलों ने भी कभी न कभी उपभोक्ताओं को मायूस किया है. उदाहरण के तौर पर दिसंबर 2009 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय लखनऊ बेंच द्वारा 2005 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में पेट्रोल में मिलावट करने वाले माफ़िया द्वारा मंजुनाथन की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में अपना निर्णय सुनाया था. जस्टिस केके मिश्रा तथा जस्टिस डीवी शर्मा की खंडपीठ ने मंजुनाथन हत्या कांड के मुख्य अभियुक्त पवन कुमार उर्फ़ मोनू मित्तल को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश लखीमपुर खीरी द्वारा दी गई सज़ा-ए-मौत को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का आदेश दिया था, जबकि इसी मामले में आजीवन कारावस की सज़ा पाए 7 अन्य अभियुक्तों में दो को बरी कर दिया गया था. शेष 5 अभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास की सज़ा को बरक़रार रखा गया है. मुख्य अभियुक्त की फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास की सज़ा में तब्दील करते हुए न्यायपीठ ने कहा कि यह मामला अभूतपूर्व मामलों की श्रेणी अर्थात रेअर ऑफ द रेअरेस्ट की श्रेणी में नहीं आता.

मूलरूप से कर्नाटक से संबंध रखने वाला 27 वर्षीय कंप्यूटर इंजीनियर एवं एमबीए की शिक्षा प्राप्त यह प्रतिभाशाली युवक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मार्केटिंग अधिकारी के पद पर तैनात था. लखनऊ के आईआईएम से 2003 के बैच में डिप्लोमा ग्रहण करने वाले इस होनहार छात्र की पहली नियुक्ति उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में की गई थी. इसी जनपद के अंतर्गत पड़ने वाले गोला गोकर्ण नाथ क्षेत्र के मित्तल ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप पर मंजुनाथन ने अक्टूबर-नवंबर 2005 में मिलावटी पेट्रोल बेचने की शिकायत मिलने पर उसे अपनी हरकत से बाज़ आने तथा मिलावटी कारोबार बंद करने की चेतावनी दी थी, परंतु धनबल, बाहुबल तथा ऊंची राजनीतिक पहुंच के नशे में डूबा उक्त पेट्रोल पंप का मालिक अपनी भ्रष्ट हरकतों से बाज़ नहीं आया. आख़िरकार मंजुनाथन ने उक्त पेट्रोल पंप पर 19 नवंबर 2005 को छापा मारा तथा मिलावटी पेट्रोल का सैंपल ज़ब्त कर लिया. मंजुनाथन की कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से चिढ़कर पेट्रोल पंप के मालिक के पुत्र पवन कुमार उर्फ़ मोनू मित्तल ने अपने आधा दर्जन से अधिक लोगों के साथ मिलकर मंजुनाथन को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला. इतना ही नहीं इस ईमानदार अधिकारी की हत्या के बाद उसकी लाश को भी ग़ायब करने का प्रयास किया गया. हत्या के अगले दिन पुलिस गश्त के दौरान सीतापुर के समीप एक नहर के किनारे कुछ संदिग्ध लोगों के क़ब्ज़े से एक कार में रखी मंजुनाथन की लाश बरामद की गई थी. हत्यारे, मंजुनाथन की लाश को नहर में फेंकना चाहते थे, परंतु पुलिस की गिरफ़्त में आने के कारण हत्यारों की योजना सफल नहीं हो सकी. तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी इस हत्या से बेहद दुखी हुए थे. मंजुनाथन के माता-पिता ने नई दिल्ली में एक बड़े मीडिया घराने द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति कलाम से यह पूछा था कि क्या हमारे देश में ईमानदारी की राह पर चलने वालों को ऐसे ही पुरस्कार मिला करेंगे. इस पर राष्ट्रपति महोदय ने भारी लहजे में घटना पर अफ़सोस ज़ाहिर करते दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की उम्मीद जताई थी. निश्चित रूप से इस मुक़दमे की सुनवाई लखीमपुर के ज़िला एवं सत्र न्यायालय द्वारा बहुत तेज़ी से की गई तथा मात्र 9 महीने के भीतर न्यायाधीश एसएमए आबदी ने हत्या के मुख्य अभियुक्त मोनू मित्तल को फांसी की सज़ा सुनाई, जबकि इस हत्याकांड में शामिल उसके अन्य 7 सहयोगियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई. सत्र न्यायालय के इस फ़ैसले के विरुद्ध अभियुक्त पक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गया, जहां मुख्य अभियुक्त की फांसी की सज़ा आजीवन कारवास में परिवर्तित कर दी गई तथा दो अन्य अभियुक्त बरी कर दिए गए. यहां यह प्रश्न उठता है कि इस फ़ैसले के बाद क्या कोई दूसरा नवयुवक भ्रष्टाचार के विरुद्ध मंजुनाथन जैसी आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा? किसे कहते हैं रेअर ऑफ द रेअरेस्ट की श्रेणी में आने वाला अपराध? एक सरकारी कर्मचारी पूरी ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है तो दूसरा भ्रष्टाचारी उसकी हत्या कर रहा है? इतना ही नहीं, हत्यारा उसकी लाश ग़ायब करने की भी कोशिश कर रहा है. सब कुछ प्रमाणित है. घटना के 23 गवाह पेश हुए थे, जिनमें 3 दबाववश मुकर गए, 20 गवाहों ने जमकर गवाही दी. इसके बावजूद फांसी के हक़दार को अदालत ने फांसी के तख़्ते पर झूलने से बचा लिया.

मुट्ठी भर लोगों पर आधारित यह माफ़िया अपने रसूख, धनबल व बाहुबल द्वारा आम लोगों पर अपनी मनमानी वस्तुएं थोंपता आ रहा है. जाने अनजाने में इन्हीं नक़ली दवाइयों तथा नक़ली खाद्य सामग्री का सेवन करने से न जाने कितनी मौतें हो जाती होंगी, परंतु मिलावटख़ोरों के हौसले हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसे में भ्रष्टाचार तथा मिलावटख़ोरी जैसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के विरुद्ध शासन-प्रशासन एवं न्यायपालिका को न केवल कड़ा रुख़ अपनाने की ज़रूरत है, बल्कि चीन से यह सबक़ लेने की भी ज़रूरत है कि बिना समय गंवाए मिलावटख़ोरों को कैसे उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है.

2009 में ही मिलावटख़ोरी नेटवर्क के एक अन्य मामले में बुलंदशहर के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश महेश नोटियाल ने नक़ली दूध तथा नक़ली मावा (खोया) बनाने व बेचने वाले दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने जैसी सख़्त सज़ा सुनाई थी. 20 फ़रवरी 2008 को थानाध्यक्ष आक़िल रशीद ने इस मिलावटी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए इन दो लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. ठीक इसी प्रकार 2006 में भी बुलंदशहर जनपद के एक अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र सिंह ने नक़ली दूध बनाने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. भ्रष्टाचार तथा मिलावटख़ोरी के विरुद्ध शासन द्वारा उठाए जाने वाले ताज़ातरीन क़दमों के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने आबकारी अधिनियम में एक बड़ा परिवर्तन किया है. दिल्ली सरकार ने आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अब ज़हरीली शराब बनाने या बेचने वालों के विरुद्ध उम्रक़ैद अथवा फांसी की सज़ा का प्रावधान किया है. इस नए आबकारी विधेयक को दिल्ली विधानसभ में मंज़ूरी भी मिल चुकी है.

इस विषय पर चीन सरकार द्वारा उठाए जाने वाले क़दमों से हमें सबक़ लेना चाहिए. मिलावट व भ्रष्टाचार के दोषी दो व्यक्तियों को कुछ समय पूर्व चीन में फांसी दे दी गई थी तथा इसी सिलसिले में एक महिला मैनेजर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी. चीन में एक मिलावटी नेटवर्क द्वारा अक्टूबर 2007 से अक्टूबर 2008 के मध्य लगभग 600 टन नक़ली सूखा दूध बनाकर बेचा गया था. इस दूध के सेवन से 6 बच्चों की मौत हो गई थी तथा 3 लाख बच्चे बीमार पड़ गए थे. इस नेटवर्क के कर्ताधर्ताओं को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने के बाद से लेकर अभी तक इस प्रकार के दूसरे मिलावटी नेटवर्क की सक्रियता की कोई ख़बर नहीं है. साफ़ है कि शासन व अदालती फ़ैसलों की दहशत ने ही मिलावटख़ोरों के हौसले पस्त कर डाले.

बड़े आश्चर्य का विषय है कि देश में मिलावटख़ोरी करने, नक़ली खाद्य सामग्री बेचने यहां तक कि नक़ली जीवन रक्षक दवाइयां बनाने व बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. मुट्ठी भर लोगों पर आधारित यह माफ़िया अपने रसूख, धनबल व बाहुबल द्वारा आम लोगों पर अपनी मनमानी वस्तुएं थोंपता आ रहा है. जाने अनजाने में इन्हीं नक़ली दवाइयों तथा नक़ली खाद्य सामग्री का सेवन करने से न जाने कितनी मौतें हो जाती होंगी, परंतु मिलावटख़ोरों के हौसले हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसे में भ्रष्टाचार तथा मिलावटख़ोरी जैसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के विरुद्ध शासन-प्रशासन एवं न्यायपालिका को न केवल कड़ा रुख़ अपनाने की ज़रूरत है, बल्कि चीन से यह सबक़ लेने की भी ज़रूरत है कि बिना समय गंवाए मिलावटख़ोरों को कैसे उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है. बेहतर होगा कि अदालतें मिलावटोख़ोरी करने वालों को भी रेअर ऑफ द रेअरेस्ट के अपराध की श्रेणी में रखें, ताकि देश को एक-दो नहीं सैकड़ों और हज़ारों मंजुमाथन और यशवंत सोनावणे व सत्येंद्र दुबे जैसे जांबाज़, देशभक्त और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी और मिल सकें. यदि मिलावटख़ोरों को फांसी के बजाए माफ़ी देने या उनके साथ नरमी बरतने के प्रयास किए गए तो निश्चित रूप से जहां भ्रष्टाचारियों व मिलावटख़ोरों की हौसला अफ़ज़ाई होगी, वहीं उनके विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने वालों के हौसले पस्त होंगे.

feedback@chauthiduniya.com

हैंडल्सब्लाट अख़बार के अनुसार उन्हें पार्टी में मौजूद एक मेहमान ने बताया कि मेहमान महिलाओं को चारों तरफ़ से ढके एक विशाल पलंग पर ले जा सकते थे और जो चाहे वो कर सकते थे.

सूचना का अधिकार जानने का अधिकार जीने का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

कैसे करें अपील और शिकायत

इस बार हम आपको बताते हैं कि आरटीआई क़ानून के तहत शिकायत व अपील कब और कैसे करते हैं. साथ ही इस अंक में हम अपील व शिकायत का एक प्रारूप भी प्रकाशित कर रहे हैं. दरअसल, अपील और शिकायत में एक बुनियादी फ़र्क़ है. कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने आरटीआई आवेदन में जो सवाल पूछा है उसका जवाब आपको ग़लत दे दिया जाता है. आपको पूर्ण विश्वास है कि जो जवाब दिया गया है वह ग़लत, अपूर्ण या भ्रामक है. इसके अलावा, आप किसी सरकारी महकमे में आरटीआई आवेदन जमा करने जाते हैं और पता चलता है कि वहां तो लोक सूचना अधिकारी ही नियुक्त नहीं किया गया है या फिर आपसे ग़लत फीस वसूली जाती है. ऐसे मामलों में सीधे राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत कर सकते हैं. ऐसे मामलों में अपील की जगह सीधे शिकायत करना ही समाधान है. आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को एक लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी हासिल करने का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको किसी जानकारी को देने से मना किया गया है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग, जैसा मामला हो, में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सूचना क़ानून की धारा 18 (1) के तहत यह केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य है, जैसा भी मामला हो, वे एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें और पूछताछ करें. आप तब शिकात दर्ज करा सकते हैं जब इस अधिनियम के तहत कोई जानकारी तक पहुंचने या देने से मना कर दिया गया हो. ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सूचना के लिए अनुरोध या सूचना तक पहुंच के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया हो वे भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही, जब शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता न हो और आपसे शुल्क की मांग की जाती हो. यदि आवेदक को यह विश्वास हो कि उसे इस अधिनियम के तहत अपूर्ण, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है या इस अधिनियम के तहत अभिलेख तक पहुंच प्राप्त करने से रोका जाए. इसके अलावा, आप यदि मिली हुई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं और यह लगता है कि अधूरी या भ्रामक सूचना दी गई है तो अपील भी कर सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301, ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

दूसरी अपील/शिकायत का प्रारूप

सेवा में,
केंद्रीय/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19/18 केतहत द्वितीय अपील/शिकायत.

क्रमांक	वांछित सूचनाएं	आवेदक द्वारा भरा जाए
1.	आवेदक/ शिकायतकर्ता का नाम एवं पता	
2.	(क) लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पता जिसकेविरुद्ध अपील/शिकायत है. (ख) आवेदन जमा करने की तिथि (ग) लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब की तिथि	
3.	(क) प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता (ख) प्रथम अपील जमा करने की तिथि (ग) प्राप्त जवाब की तिथि	
4.	आदेशों का विवरण, यदि कोई हो	
5.	अपील किए जाने से पहले तक केतथ्यों का संक्षिप्त विवरण	
6.	यदि अपील डिम्ड रिफयजल केविरुद्ध किया जाना है तो जिस लोक सूचना अधिकारी केयहां आवेदन किया गया था उसका नाम एवं पता और तिथि एवं नंबर सहित आवेदन का संक्षिप्त विवरण दें.	
7.	आयोग से निवेदन व प्रार्थना	लोक सूचना अधिकारी को मेरे आवेदन में मांगी गई सूचना बिना किसी शुल्क केतुरंत सात दिनों में प्रदान करने का आदेश दें. साथ ही आयोग से यह भी निवेदन है कि लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध क़ानून की धारा 20(1) के तहत जुर्माना लगाएं और धारा 20(2) केतहत लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही केलिए सिफ़ारिश भी करें. आयोग से निवेदन है कि मैं इस मामले की सुनवाई में स्वयं या अपने प्रतिनिधि केमाध्यम से उपस्थित रहना चाहता हूं. अत: मुझे सभी सुनवाइयों की अग्रिम सूचना अवश्य प्रदान करें. साथ ही में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर फ़ैसला सुनवाई करने केबाद ही करें.
8.	निवेदन व प्रार्थना का आधार	लोक सूचना अधिकारी ने सूचनाएं अब तक उपलब्ध नहीं कराई हैं, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19/18 केतहत अपील/शिकायत दायर की जा रही है. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(6) का संज्ञान लेते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेश दें कि सभी सूचनाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएं. साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) एवं (2) के तहत लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन केहिसाब से जुर्माना लगाएं और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सिफ़ारिश भी करें.
9.	अन्य सूचनाएं (यदि हैं तो)	उपरोक्त अपील/ शिकायत के तथ्यों को दिनांक.....को सत्यापित किया गया है.
10.	सत्यापन	

मैं .....उपरोक्त अपील/शिकायत के तथ्यों को दिनांक.....को सत्यापित किया गया है.

मैं ..... सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में नहीं की गई है अथवा विचाराधीन नहीं है. इस अपील में प्रदान की गई सूचनाएं मेरी जानकारी में सही हैं.

संलग्न सूची:
1- आवेदन की प्रति
2- शुल्क रसीद का प्रति
3- आवेदन पत्र को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद
4- प्रथम अपील की प्रति (यदि हो)
5- प्रथम अपील को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद (यदि हो)
6- द्वितीय अपील की प्रति को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी को भेजे जाने की रसीद

नाम: .....
पता: .....

स्थान:
तिथि:

नोट: (केवल केंद्रीय सूचना आयोग केलिए)
1. द्वितीय अपील/शिकायत की एक-एक प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी को भेजें.
2. द्वितीय अपील/शिकायत की दो प्रति केंद्रीय सूचना आयोग में भेजनी होंगी. साथ ही एक प्रति आपने पास रखें.

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. धन लाभ के योग बन रहे हैं. कुछ तनाव रह सकता है. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे. कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ व्यर्थ विवाद हो सकता है.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई

इस सप्ताह किसी भी विवाद से बचें. वाणी पर संयम रखें. ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी. जीवनसाथी से संबंध मधुर होंगे. अचानक ही लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा.

मिथुन 21 मई से 20 जून

इस सप्ताह आपके धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी. पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. भाई या पड़ोसी का सहयोग प्राप्त होगा. अनावश्यक कार्यों में व्यस्त रहेंगे. कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है. कोई ऐसी बात हो सकती है, जो आपके हित में न हो. पारिवारिक व व्यावसायिक परेशानियां आ सकती हैं. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह आपको व्यर्थ की परेशानी व उलझनें रहेंगी. पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा. निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे. किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा. यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें, चोरी या खोने की आशंका बनी हुई है.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

इस सप्ताह आपको अचानक कहीं दूर यात्रा पर जाना पड़ सकता है. संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. व्यावसायिक मामलों में चल रहा प्रयास सफल होगा. मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे. मांगलिक कार्यों के लिए किया जा प्रयास सफल साबित होगा.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी. धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी. जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा. समाज के कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे. नेत्र से संबंधी शिकायत हो सकती है, डॉक्टर को अवश्य दिखाएं.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

इस सप्ताह क़ानूनी मामले को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा. कई दिनों से रुका हुआ कार्य इस सप्ताह संपन्न हो जाएगा. किसी रिश्तेदार के कारण अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

रचनात्मक कार्य की दिशा में चल रहा प्रयास सफल होगा. कुछ भी ऐसा न करें जो कष्टकारी हो. आय के क्षेत्र में नए स्त्रोत बनेंगे. इस सप्ताह अगर आप धैर्य रखेंगे, तो प्रोफेशनल सफलता मिलनी तय है. कठिन मामलों को निपटाने के लिए सही तरीक़े से चलने की ज़रूरत है. फाइनेंशल बदलाव अच्छे रहेंगे.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

इस सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर आपके लिए अच्छा चलेगा, साथ ही व्यवसायिक क्षेत्र में ग्रोथ भी अच्छी रहेगी. पिता समान कोई व्यक्ति परिवार के मामलों में तनाव की वजह बनेगा. यात्रा पर जाने की योजना बनाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो बेहतर होगा.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

इस सप्ताह किसी के लड़ाई-झगड़े में न फंसे तो बेहतर होगा, क्योंकि परिस्थितियां आपके लिए प्रतिकूल साबित हो सकती हैं. कहीं आप ही न फंस जाए. वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने में ही भलाई है. स्वास्थ्य के लिहाज़ से आप ठीक रहेंगे.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा. संबंधों में मधुरता आएगी. घर में किसी बुज़ुर्ग का स्वास्थ्य चिंता का सबब बन सकता है. अगर कहीं यात्रा पर जा रहें हों तो उसे टालने में ही भलाई है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

तक़दीर वाला भालू

फ़िलहाल यह भालू चार महीने का है, लेकिन इस प्रजाति के भालू वयस्क होने पर 350 किलोग्राम के हो जाते हैं. ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े मांसाहारियों में शामिल हैं. एक अनाथ नर भालू पूर्वी यूरोप के देश स्लोवेनिया में लोगों को अपने कारनामों से हैरान कर रहा है. अब सरकार उसे वन्य जीव केंद्र में ले जाने का प्रयास कर रही है. मेडो के नाम से मशहूर इस भालू को मीडिया ने तक़दीर वाला क़रार दिया है. यह स्लोवेनिया के एक गांव के लोगर परिवार के घर क़रीब एक महीना पहले पहुंचा था. परिवार के सदस्य इस भालू से बहुत प्यार करते हैं और यह भालू कुत्ते और घर पर रखे फ़र्नीचर से ख़ूब खेलता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि चार महीने का यह भालू बड़ा होने के बाद ख़तरनाक साबित हो सकता है. उधर, परिवार ने भालू के एक बाड़े का निर्माण करने की इजाज़त मांगी है. स्लोवेनिया में इस भालू की कहानी मीडिया में ख़ूब छाई हुई है. ऐसा माना जा रहा है कि भालू को उसकी मां ने छोड़ दिया है.

इस भूरे रंग के भालू का वैज्ञानिक नाम उर्सस आर्कटॉस है और वयस्क होने पर इसका वज़न साढ़े तीन सौ किलो तक पहुंच सकता है. शायद इसी वजह से स्लोवेनिया का वन्यजीव विभाग चिंतित है.

यह कैसा गिफ्ट

कंपनी का कहना है कि इस तरह के इनाम अब नहीं दिए जाते. दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक ने अपने सबसे क़ाबिल एजेंटों को इनाम में यौनकर्मी की सेवाएं दी थीं. म्यूनिख़ आरई दुनिया की सबसे बड़ी पुनर्बीमा - यानी बीमा कंपनियों का बीमा करने वाली कंपनी है. इस कंपनी की एक इकाई आर्गो ने बीबीसी को बताया कि सबसे अच्छा काम करने वाले बीमा विक्रय एजेंटों के लिए ये पार्टी 2007 में रखी गई थी. कंपनी के एक प्रवक्ता का कहना है कि जिन लोगों ने इस पार्टी का आयोजन किया था वे सभी अब कंपनी छोड़ चुके हैं. जानकारी के अनुसार यह आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के एक हमाम में किया गया था. इस पार्टी में सौ मेहमानों के लिए बीस यौनकर्मियों की सेवाएं ली गईं थीं. जर्मनी के एक अख़बार का कहना है कि यौनकर्मियों के हाथों पर उनकी उपलब्धता के हिसाब से रंगीन पट्टियां बांधी गईं थीं. उन महिलाओं के हाथों पर उनके द्वारा हर एक सेवा देने पर एक मोहर भी लगाई गई थी.

हैंडल्सब्लाट अख़बार के अनुसार उन्हें पार्टी में मौजूद एक मेहमान ने बताया कि मेहमान महिलाओं को चारों तरफ़ से ढके एक विशाल पलंग पर ले जा सकते थे और जो चाहे वो कर सकते थे.

अख़बार ने उस मेहमान के हवाले से कहा, पुरुषों के साथ हर मुलाक़ात के बाद उस पार्टी में महिलाओं के हाथ के निचले हिस्से पर एक मोहर लगा दी गई थी, ताकि यह पता लग सके कि उनकी सेवाएं कितनी बार ली गई हैं.

अख़बार में छपे ब्यौरे के अनुसार महिलाएं दो समूहों में थीं, एक वो जो पार्टी की देखभाल कर रही थीं और एक वो जो हर इच्छा पूरी कर रही थीं. अख़बार में छपा है, वहां पर हाथों में सफ़ेद पट्टियां बांधे महिलाएं भी थीं जो केवल बोर्ड के सदस्यों और श्रेष्ठतम बीमा विक्रयकर्ताओं के लिए आरक्षित थीं. अर्गो के एक प्रवक्ता ने बीबीसी से बात करते हुए माना कि ऐसी पार्टी हुई थी, पर उसने यह भी कहा कि अच्छे काम का इनाम देने का कंपनी का यह सामान्य तरीक़ा नहीं है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

3 जून को तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वह ओसामा की मौत का बदला लेकर रहेगा. यह चेतावनी पाकिस्तान के वरिष्ठ तालिबान नेता मौलवी फ़कीर मोहम्मद ने दी थी.

इलियास का इफेक्ट

राजीव रंजन तिवारी

पहले अल क़ायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन, फिर उसके सक्रिय सदस्य इलियास कश्मीरी का मारा जाना और अब पाकिस्तान में धड़ाधड़ हो रहे बम धमाकों ने सबको सकते में डाल दिया है. पता नहीं पाकिस्तान को अब भी इस बात का एहसास है या नहीं कि उसने जो वर्षों पहले भारत विरोधी आतंकवाद की फ़सलें बोई थीं, अब वही फलफूल रही हैं. वहां के राजनीतिज्ञों और राजनयिकों को कम से कम अब तो चेत ही जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का भविष्य बेहतर हो सके. वैसे मौजूदा हालात को देखकर यह नहीं लगता कि वहां की स्थितियां इतनी जल्दी बदलने वाली हैं, क्योंकि ख़ून-ख़राबे की जड़ें पाकिस्तान में गहरी हैं.

11 जून की देर रात पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुए दो बम धमाकों में कम से कम 34 लोगों की मौत हुई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं. ये धमाके ऐसे इलाक़े में हुए जहां कई राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय और सेना से जुड़े लोगों के मकान हैं. बताते हैं कि ये धमाके रिमोट से किए गए. ख़ास बात यह है कि धमाके तब हुए जब अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई इस्लामाबाद आए हुए थे. ग़ौरतलब है कि पिछले महीने पाकिस्तान में अल क़ायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन अमेरिकी कार्रवाई में मारा गया और उसके बाद दक्षिणी वज़ीरिस्तान में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में मुंबई ब्लास्ट में कथित रूप से शामिल और अल क़ायदा के क़रीबी इलियास कश्मीरी की मौत हो गई थी. तब से पाकिस्तान में चरमपंथियों के हमलों में तेज़ी आ गई है. अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि पहले लादेन और बाद में इलियास कश्मीरी के मारे जाने से चरमपंथी बौखला गए हैं. कहा जा रहा है कि 11 जून की देर रात पेशावर में हुए धमाके इलियास का साइड इफेक्ट हैं. यदि समय रहते पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा इन चरमपंथियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो शायद ये हमले और तेज़ हो सकते हैं. इधर कुछ दिनों से पाकिस्तान में धमाकों की श्रृंखला बढ़ गई है. अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर पश्चिमी वज़ीरिस्तान में 100 से ज़्यादा तालिबान चरमपंथियों ने एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया था. इसमें 12 तालिबान लड़ाके और आठ सैनिक मारे गए थे. ऐसा पहली बार हुआ था कि जब तालिबान लड़ाकों ने इतनी ताक़त का इस्तेमाल किया था.

इसके अलावा 8 जून को पाकिस्तान के क़बायली इलाक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में अमेरिकी मानव रहित विमान के हमले में 15 लोग मारे गए. अमेरिकी ड्रोन विमानों ने चरमपंथियों के एक ठिकाने को निशाना बनाया. इससे चरमपंथियों का ठिकाना पूरी तरह ध्वस्त हो गया. ग़ौरतलब है कि क़बायली इलाक़ों विशेषकर वज़ीरिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमलों में भी अचानक तेज़ी देखने को मिली. पिछले क़रीब एक हफ्ते में यह पांचवा हमला था. इससे पहले दक्षिणी वज़ीरिस्तान में हुए ड्रोन हमले में मुंबई हमलों में कथित रूप से शामिल और अल क़ायदा का क़रीबी इलियास कश्मीरी मारा गया था. वर्ष 2009 के अंत में भी इलियास कश्मीरी के मारे जाने की ख़बर आई थी, लेकिन वह झूठी साबित हुई. इलियास कश्मीरी को पिछले महीने पाकिस्तान के कराची में मेहरान नौसेना अड्डे पर हुए हमले का भी मास्टर माइंड बताया गया था. अमेरिका ने उसका पता बताने वाले को 50 लाख डॉलर इनाम देने की घोषणा की थी. इतने दूरगामी इलाक़े में इलियास कश्मीरी का मारा जाना अमेरिकी गुप्तचर एजेंसियों के बीच प्रभावी होने का सबूत है. चरमपंथी संगठन हरकतुल जेहाद अल इस्लामी भारत, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में हुए कई हमलों का ज़िम्मेदार है. इसमें 2006 में कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हुआ हमला भी शामिल है. बताते हैं कि इलियास कश्मीरी के इस संगठन से भी संबंध थे.

उधर, 2 जून को अफ़ग़ानिस्तान से आए चरमपंथियों ने एक मुठभेड़ में कम से कम 23 सुरक्षाकर्मियों को मार दिया. चरमपंथियों ने एक दिन पहले उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के अपर दीर इलाक़े में प्रवेश किया था और एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया था. बताते हैं कि इसमें कुछ आम नागरिकों की भी मौत हुई है. इस घटना के बारे में बताया गया था कि अफ़ग़ानिस्तान की सीमा पार करके दो सौ से अधिक चरमपंथियों ने पाकिस्तान में प्रवेश किया था. वे सैनिकों की यूनीफ़ॉर्म पहने हुए थे. बताया गया कि चरमपंथियों की गोलीबारी में पांच आम नागरिक मारे गए, उनमें दो महिलाएं भी हैं. दो महीने पहले इसी इलाक़े में हुए चरमपंथी हमले में कम से कम 13 जवान मारे गए थे. यह वही क़बायली इलाक़ा है जहां पाकिस्तानी सेना ने दो साल पहले अल क़ायदा और तालिबान के चरमपंथियों के ख़िलाफ़ व्यापक कार्रवाई की थी.

3 जून को तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वह ओसामा की मौत का बदला लेकर रहेगा. यह चेतावनी पाकिस्तान के वरिष्ठ तालिबान नेता मौलवी फ़कीर मोहम्मद ने दी थी. वैसे पिछले काफ़ी समय से यह माना जा रहा था कि फ़कीर ने गुप्त रूप से सरकार के साथ समझौता कर लिया है, इसीलिए वह ख़ामोश है, लेकिन उसकी अचानक इस चेतावनी ने सबके होश उड़ा दिए थे. इससे पहले तालिबान के प्रवक्ता सज्जाद मोहम्मद ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन की मौत का बदला लेने के लिए उसने व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान में आज जो हमले हो रहे हैं वह आतंकियों व चरमपंथियों का पूर्व नियोजित कार्यक्रम है. इस बारे में सरकार को भी समय से पहले चेतावनियों के रूप में पता चल गया था. इसके बावजूद पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की कोशिश नहीं की गई, वरना बीती रात हुए बम धमाके को विफल किया जा सकता था. पाकिस्तानी सरकार और राज्य व्यवस्था को समझना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और न ही कोई दोस्त और देश होता है. अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है. अगर पाकिस्तान अपनी सलामती चाहता है तो उसे आतंकियों का तंत्र तोड़ना होगा, अन्यथा पाकिस्तान को तबाह होने से बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिना मेहनत किए धन नहीं मिलता है, फिर भी धन प्राप्ति में मनुष्य के कर्मों का भी बहुत योगदान होता है.

साई बाबा और तात्या का भाग्य

तात्या, एक फावड़ा ले आओ, बाबा ने कोठरी में चारों ओर निगाह घुमाते हुए कहा. तात्या फावड़ा ले आया. उसकी और वाइजा बाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि बाबा ने फावड़ा क्यों मंगाया है? तात्या, इस पलंग के सिरहाने वाले दाएं ओर के पाए के नीचे खोदो, इतना कहकर बाबा ने पलंग एक ओर सरका दिया. तात्या ने अभी तीन-चार फावड़े ही मारे थे कि अचानक फावड़ा किसी धातु से टकराया.

शिरडी में सबसे पहले बाबा ने वाइजा बाई के घर से ही भिक्षा ली थी. वाइजा बाई एक धर्मपरायण स्त्री थीं. उनकी एक ही संतान तात्या था, जो पहले ही दिन से बाबा का परम भक्त बन गया था. वाइजा बाई ने यह निर्णय कर लिया था कि वह रोज़ाना बाबा के लिए खाना लेकर स्वयं द्वारिका माई मस्जिद जाया करेंगी और अपने हाथों से बाबा को खाना खिलाया करेंगी. अब वह रोज़ाना दोपहर को एक टोकरी में खाना लेकर द्वारिका माई मस्जिद पहुंच जाती थीं. एक दिन वाइजा बाई जब बाबा को खोजती हुई मस्जिद पहुंचीं तो उन्होंने बाबा को धूनी के पास अपने आसन पर बैठे पाया. वाइजा बाई को देखकर बाबा बोले, मां, मैं तुम्हें बहुत कष्ट देता हूं. जो बेटा अपनी मां को दुःख दे, उससे अधिक अभागा और कोई नहीं हो सकता. मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा. जब भी तुम खाना लेकर आया करोगी, मैं तुम्हें मस्जिद में ही मिला करूंगा. बाबा ने कहा, तुम घर जाकर तात्या को भेज देना. वह तो लकड़ी बेचने गया है, आते ही भेज दूंगी, कहने के बाद वाइजा बाई के चेहरे पर सहसा गहरी उदासी छा गई. वाइजा बाई की आपबीती सुनकर बाबा की आंखें भीग गईं, वह कुछ देर तक मौन बैठे रहे और फिर बोले, वाइजा मां, भगवान भला करेंगे, फ़िक्र मत करो. सुख और दुःख तो इस ज़िंदगी के ज़रूरी अंग हैं. जब तक इंसान इस दुनिया में ज़िंदा रहता है, उसे यह सब तो भोगना ही पड़ता है.

तात्या अभी थोड़ी सी ही लकड़ियां काट पाया था कि अचानक एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, ओ लकड़ी वाले! उसने ज़ोर से पुकारा, कौन है भाई?

तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया. लकड़ियां बेचोगे? उस आदमी ने पूछा.

हां-हां, क्यों नहीं बेचूंगा भाई! कितने पैसे लोगे इन लकड़ियों के? जो मर्ज़ी हो, दे दो, आज तो लकड़ियां बहुत कम हैं और भीग भी गई हैं, जो भी दोगे ले लूंगा. लो, यह रुपया रख लो. तात्या हैरानी से उस व्यक्ति को देखने लगा. कम है तो और ले लो, उस आदमी ने जल्दी से जेब से एक रुपया और निकाल कर तात्या की ओर बढ़ाया.

नहीं-नहीं, कम नहीं है, ज़्यादा है, लकड़ियां थोड़ी हैं, तात्या ने जल्दी से कहा.

तो क्या हुआ, आज से तुम रोज़ाना मुझे यहां पर लकड़ियां दे जाया करो. मैं तुम्हें यहीं मिला करूंगा. यदि आज ये लकड़ियां कुछ कम हैं तो कल लकड़ियां ज़्यादा ले आना, तब हमारा-तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा, उसने हंसते हुए कहा और रुपया ज़बरदस्ती उसके हाथ पर रख दिया.

घर पहुंच कर तात्या ने मां के हाथ पर रुपये रखे तो वह आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगी. इतने रुपये कहां से ले आया तात्या? मां ने आशंकित होकर पूछा. तात्या ने अपनी मां को पूरी घटना बता दी. यह तूने ठीक नहीं किया बेटा, कल उसे ज़्यादा लकड़ियां दे आना. इंसान को अपनी ईमानदारी की कमाई पर ही संतोष करना चाहिए. अगले दिन जब तात्या जंगल में गया तो उस समय वर्षा रुक गई थी. आकाश एकदम साफ़ था. तात्या ने जल्दी-जल्दी और दिनों से ज़्यादा लकड़ियां काटीं और गट्ठर बनाने लगा. गट्ठर भारी था. रोज़ाना तो वह अकेले ही लकड़ियों का गट्ठर उठाकर सिर पर रख लिया करता था, लेकिन आज लकड़ियां ज़्यादा थीं, वह अकेला उस गट्ठर को उठा नहीं सकता था. अचानक उसे सामने से एक मुसाफ़िर आता हुआ दिखाई दिया. जब वह पास आ गया तो तात्या ने उससे कहा, भाई ज़रा मेरा बोझा उठवा दो. उस मुसाफ़िर ने तात्या के सिर पर गट्ठर उठवा कर रखवा दिया. अब तात्या तेज़ी से चल पड़ा.

अरे भाई तात्या, क्या बात है, आज तुमने इतनी देर कैसे कर दी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं, पिछले दिन वाले आदमी ने मुस्कराते हुए कहा.

आज लकड़ियां और दिनों के मुक़ाबले ज़्यादा हैं. रोज़ाना लकड़ियां कम होती थीं, इसलिए मैं अकेले ही गट्ठर उठा लेता था, आज भारी होने के कारण मैं नहीं उठा पा रहा था. बहुत देर बाद जब एक आदमी आया तो मैं उसकी सहायता से गट्ठर उठवा कर सिर पर रख पाया और फिर सीधा भागता हुआ चला आया हूं. उस आदमी ने लकड़ी के गट्ठर पर एक नज़र डाली और बोला, आज तो तुम ढेर सारी लकड़ियां काट लाए. तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन कल तुम्हें बहुत कम लकड़ियां मिली थीं, पर तुमने पैसे पूरे दे दिए थे. इसलिए तुम्हारा हिसाब भी तो बराबर करना था. कल तुमने रुपये दे दिए थे, उसी के बदले सारी लकड़ियां ले जाओ, अब तक का हिसाब बराबर, तात्या ने हंसते हुए कहा. कहां ठीक है तात्या भाई! जिस तरह तुम ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहते, उसी तरह मैंने भी बेईमानी करना नहीं सीखा, उस आदमी ने कहा और अपनी जेब से रुपया निकाल कर तात्या की हथेली पर रख दिया, लो इसे रखो, हमारा आज तक का हिसाब-किताब बराबर. आज लकड़ियां और दिनों से दोगुनी हैं, इसलिए हिसाब भी दोगुना होना चाहिए.

तात्या ने रुपया लेने से बहुत इंकार किया, पर उस आदमी ने समझा-बुझाकर वह रुपया तात्या को लेने पर विवश कर दिया. तात्या ने रुपया जेब में रखा और फिर वह गांव की ओर चल दिया. अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक उसे कुल्हाड़ी की याद आई. जल्दबाज़ी में वह कुल्हाड़ी जंगल में ही भूल आया था. अपनी भूल का एहसास होते ही वह तेज़ी से जंगल की ओर लौट पड़ा. अब उसे वह आदमी और लड़कियों का गट्ठर कहीं भी दिखाई न दिया.

घर आकर वह अपनी मां के साथ द्वारिका माई मस्जिद आया. वाइजा बाई ने दोनों को खाना लगा दिया. खाना खाते समय तात्या ने लकड़ी ख़रीदने वाले के बारे में बाबा को बताया. बाबा बोले, तात्या, इंसान को वही मिलता है, जो परमात्मा ने उसके भाग्य में लिखा है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिना मेहनत किए धन नहीं मिलता है, फिर भी धन प्राप्ति में मनुष्य के कर्मों का भी बहुत योगदान होता है. वैसे चोर-डाकू भी चोरी-डाका डालकर लाखों रुपये ले आते हैं, लेकिन वे सदैव ग़रीब ही बने रहते हैं. न तो उन्हें समय पर भरपेट भोजन मिलता है और न चैन की नींद आती है, जबकि एक ग़रीब आदमी थोड़ी सी मेहनत करके इतना पैसा पैदा कर लेता है, जिससे बड़े आराम से उसकी और उसके परिवार की गुज़र-बसर हो सके. वह स्वयं भी इत्मीनान से रूखी-सूखी खाता है और चैन की नींद सोता है तथा मुझ जैसे फ़कीर की झोली में भी रोटी का एक-आध टुकड़ा डाल देता है. तुम्हें जो कुछ मिलता है, वह तुम्हारे भाग्य में लिखा है. लेकिन वह आदमी और लकड़ियों का गट्ठर कहां ग़ायब हो गया? तात्या ने हैरानी से पूछा.

भगवान के खेल भी बड़े अजब-ग़जब हैं तात्या! इंसान अपनी साधारण आंखों से उसे देख नहीं पाता, बाबा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें बेवजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. वास्तव में तात्या के मन में बाबा के प्रति अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास था, इसी कारण बाबा का भी उस पर विशेष स्नेह था. अचानक बाबा उठकर खड़े हो गए और बोले, चलो तात्या, घर चलो, कहकर वह मस्जिद की सीढ़ियों की ओर चल दिए.

बाबा सीधे वाइजा बाई की उस कोठरी में गए, जहां पर वह सोया करती थीं. उस कोठरी में एक पलंग पड़ा था. तात्या, एक फावड़ा ले आओ, बाबा ने कोठरी में चारों ओर निगाह घुमाते हुए कहा. तात्या फावड़ा ले आया. उसकी और वाइजा बाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि बाबा ने फावड़ा क्यों मंगाया है? तात्या, इस पलंग के सिरहाने वाले दाएं ओर के पाए के नीचे खोदो, इतना कहकर बाबा ने पलंग एक ओर सरका दिया. तात्या ने अभी तीन-चार फावड़े ही मारे थे कि अचानक फावड़ा किसी धातु से टकराया. कुछ देर बाद उसने तांबे का एक कलश निकाल कर बाबा के सामने रख दिया. तात्या ने कलश पर रखा ढक्कन हटाकर उसे फर्श पर उलट दिया. देखते ही देखते उस कलश में से सोने की अशर्फ़ियां, मूल्यवान ज़ेवर और हीरे निकल कर बिखर गए.

यह तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति है. तुम्हारे भाग्य में ही मिलना लिखा था, तुम्हारे पिता के भाग्य में यह संपत्ति नहीं थी, बाबा ने कहा, इसे संभाल कर रखो और समझदारी से ख़र्च करो. वाइजा बाई बोलीं, बाबा, हम यह सब रखकर क्या करेंगे? हमारे लिए तो रूखी-सूखी रोटी ही बहुत है. आप ही रखिए और मस्जिद के काम में लगा दीजिए. बाबा ने वाइजा बाई का हाथ पकड़ कर कहा, नहीं मां, यह सब तुम्हारे भाग्य में था. यह सारी संपत्ति केवल तुम्हारी है. मेरी बात मानो, इसे अपने पास ही रखो.

बाबा की बात वाइजा बाई को माननी पड़ी, उन्होंने कलश रख लिया. तात्या ने इस संपत्ति से नया मकान बनवा लिया और बहुत ठाठ-बाट से रहने लगा. गांव वाले हैरान थे. तात्या को संपन्न देख धन के लोभी, लालची लोग भी बाबा के पास जाने लगे. रात-दिन सेवा किया करते कि शायद बाबा प्रसन्न हो जाएं और उन्हें भी धनवान बना दें. कुछ तो इतने बेशर्म लोग थे कि बाबा से एकदम स्वयं को धनवान बनाने के लिए कहते, बाबा, हमें भी तात्या की तरह धनवान बना दो. उन लोगों की बातें सुनकर बाबा कहते, भला मेरे पास कहां से कुछ आया. बाबा का ऐसा जवाब सुनकर सब चुप रह जाते, फिर आगे कोई भी कुछ न कह पाता.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ ख़ाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

प्रभाष जी के जीवन काल में ही 2003 में राजकमल प्रकाशन ने उनके लेखों का संग्रह हिंदू होने का धर्म छापा था जिसकी ख़ासी चर्चा हुई थी.

अनंत विजय

किताबों में बनता इतिहास

प्रभाष जोशी हमारे समय के बड़े पत्रकार थे. उनके सामाजिक सरोकार भी उतने ही बड़े थे. समाज और पत्रकारिता को लेकर उनकी चिंता का दायरा भी बेहद विस्तृत था. हिंदी पट्टी और हिंदी समाज में प्रभाष जी की काफ़ी इज़्ज़त भी थी. उनके निधन के बाद हिंदी पत्रकारिता में एक ख़ालीपन आ गया है. जिस तरह से प्रभाष जोशी समाज को लेकर चिंतित रहा करते थे या फिर पत्रकारिता के गिरते स्तर को बचाने के लिए उन्होंने जिस तरह से एक अभियान की अगुवाई की थी वह हम सबके लिए अनुकरणीय है. प्रभाष जी जो भी सोचते थे बेख़ौफ़ होकर उसे या तो अपने स्तंभ में व्यक्त करते थे या फिर सभाओं या गोष्ठियों के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे. देश भर की यात्राओं के बावजूद प्रभाष जोशी अपने स्तंभ लेखन को लेकर बेहद सतर्क रहते थे और बिना नाग़ा उसको लिखते थे. हर हफ्ते हमलोग रविवार का इंतज़ार इस बात के लिए करते थे कि कागद कारे पढ़ने को मिलेगा. प्रभाष जी के स्तंभ से पाठकों का जो एक अपनापन क़ायम हुआ था वही उनकी ताक़त थी. अपने स्तंभ के माध्यम से प्रभाष जी का पाठकों से सीधा संवाद था, लेकिन उनके निधन के बाद ये संवाद टूट गया. जनसत्ता और अन्य पत्र–पत्रिकाओं में लिखे उनके स्तंभ हिंदी समाज के लिए थाती हैं और पाठकों के लिए सहेजकर रखने वाली धरोहर.

प्रभाष जी के जीवन काल में ही 2003 में राजकमल प्रकाशन ने उनके लेखों का संग्रह हिंदू होने का धर्म छापा था जिसकी ख़ासी चर्चा हुई थी. अब एक बार फिर से राजकमल प्रकाशन से ही उनके लेखों के दो संग्रह–आगे अंधी गली है और 21वीं सदी पहला दशक–छपे हैं. इन दोनों पुस्तकों का संपादन वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा ने किया है. आगे अंधी गली है, में प्रभाष जोशी के प्रथम प्रवक्ता और तहलका हिंदी में छपे लेख संकलित हैं. अपने संपादकीय में सुरेश शर्मा ने लिखा है कि आगे अंधी गली प्रभाष जी के अंतिम दिनों का लेखन है. वे प्रथम प्रवक्ता और तहलका में कॉलम लिख रहे थे. ये कॉलम अपने समय की धड़कनों के जीवंत दस्तावेज़ हैं.

इस पुस्तक के संपादकीय में सुरेश शर्मा ने प्रभाष जी की ज़िंदगी के अंतिम दिनों पर विस्तार से लिखा है. सुरेश शर्मा के इस लेख से आम पाठकों के मन पर प्रभाष जी के व्यक्तित्व की तस्वीर और साफ़ होती है. बीमारी में भी, समाज और पत्रकारिता के अपने पेशे के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए प्रभाष जी ने अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया. तबीयत ख़राब होने के बावजूद उन्होंने हिंद स्वराज पर आयोजित गोष्ठी में हिस्सा लिया और अपनी बात श्रोताओं के साथ साझा की. सुरेश शर्मा ने प्रभाष जी की अंतिम घड़ी को उनकी अदम्य जिजीविषा से जोड़कर एक बेहद संजीदा तस्वीर पेश की है. इस किताब में कई ऐसे लेख हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में भी प्रासंगिक है. जैसे मई 2008 में प्रथम प्रवक्ता में प्रभाष जी ने लिखा–राहुल के अंदेशे से दुबली मायावती. प्रभाष जी का यह लेख उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तीन साल पहले था. उस वक़्त दलितों के घर राहुल के खाना खाने और रात बिताने को लेकर मायावती परेशान थीं और आज भट्टा पारसौल में राहुल के धरने ने मायावती को परेशानी में डाल रखा है. मायावती की परेशानी पर प्रभाष जी विस्मित होते हुए लिखते हैं कि राहुल गांधी के दलित प्रेम से मायावती इतनी घबरा क्यों गई हैं. दूसरे नेताओं की तरह वह कोई जड़विहीन हवाई नेता नहीं जो मीडिया में लगातार बने रहने के कारण नेता हो गई हैं. मई 2008 में ही प्रभाष जी ने एक और लेख लिखा था– चूके अवसरों की महादेवी. इस लेख के केंद्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं. इस लेख में प्रभाष जी ने निराशा भरे लहजे में लिखा था– इस त्याग (प्रधानमंत्री पद ठुकराना) ने सोनिया गांधी को भारत के जनमानस में वह जगह दी जो उन्हें अपनी पार्टी कांग्रेस में प्राप्त थी. उन्हें ऐसा नैतिक आभामंडल मिला जो उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी के पास भी नहीं था. अपने इस लेख में सोनिया की रहनुमाई में चल रही सरकार के चार साल के कार्यकाल से प्रभाष जी निराश थे, निराश तो वह सोनिया गांधी के प्रदर्शन से भी थे. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस को फिर से सरकार बनाने का मौक़ा मिलेगा, लेकिन वह हो नहीं सका और कांग्रेस ने सोनिया की अगुवाई में 2004 के मुक़ाबले ज़्यादा सीटें हासिल कीं. प्रभाष जी के लेखों में विभिन्न विषयों की जो रेंज थी वह उनकी विद्वता और अध्ययन को दिखाता है. समाज और राजनीति के अलावा प्रभाष जी साहित्य के भी गहरे अध्येता थे. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का शताब्दी वर्ष जिस तरह से हिंदी समाज में मनाया गया और जो लापरवाहियां हुईं उस पर भी प्रभाष जी ने एक बेहद तल्ख़ टिप्पणी लिखी. जिस तरह से दिनकर शताब्दी समारोह में बिहार के एक मंत्री ने बाद में मंच पर आकर ऊल जलूल बातें कीं उससे प्रभाष जी बेहद खिन्न थे. दिनकर जन्म शताब्दी वर्ष में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार की लापरवाही से भी प्रभाष जी दुखी थे. इसी तरह से एक और अन्य विषय समलैंगिकता पर भी इसमें प्रभाष जी का एक लेख संकलित है. कुल मिलाकर यह किताब प्रभाष जी की विचारधारा और अपने समय, समाज और राजनीति को जानने की एक कुंजी है जिसे इसके संपादक सुरेश शर्मा ने श्रमपूर्वक तैयार किया है.

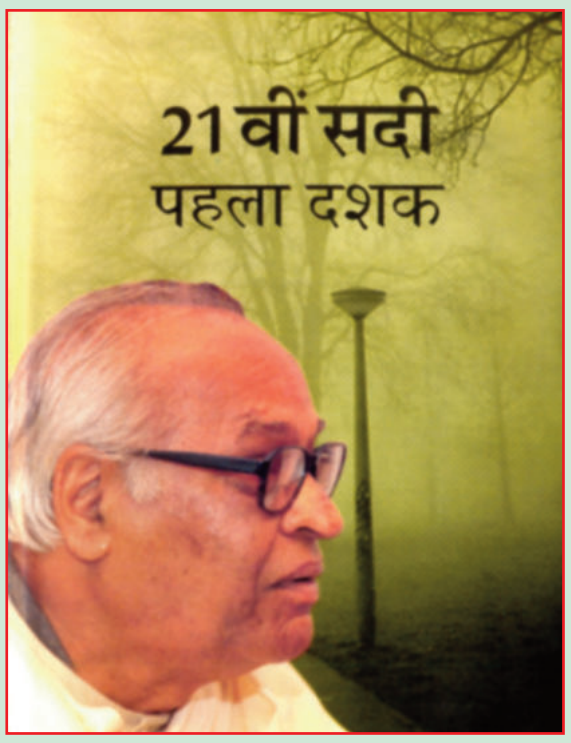

दूसरी किताब–21वीं सदी पहला दशक है, जिसमें प्रभाष जोशी के दो हज़ार एक से लेकर 2009 तक के बीच में जनसत्ता में लिखे लेख संकलित हैं. संपादक का कहना है कि इस जनसत्ता में प्रकाशित इस कालखंड के तक़रीबन सारे लेख इस किताब में संकलित किए गए हैं. यह संकलन इस लिहाज़ से अहम है कि इसमें लगभग एक दशक की राजनीति गतिविधियों की एक मुकम्मल तस्वीर बनती है. प्रभाष जी के लेखों को पढ़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के काम करने के तरीक़ों को समझने में मदद मिल सकती है, लेकिन दोनों किताबों के कुछ लेखों में मोहभंग को भी साफ़ तौर रेखांकित किया जा सकता है. मई 2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा कर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मनोनीत किया था तो प्रभाष जी को उनमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी. उन्होंने एक लेख लिखा था–आइए सोनिया जी, अनंत संभावनाओं की दहलीज़ पर. इस लेख में प्रभाष जी ने सोनिया गांधी की भूरि–भूरि प्रशंसा की थी. इस लेख की दो पंक्तियां देखिए–किन्हीं भी कारणों और कैसे भी इरादों से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा हो, पर सच बताइए कितने माई के लाल ऐसा कर सकते हैं और कितनों ने ऐसा किया है? जिसने किया है, उठिए और उनको सलाम कीजिए. लेकिन चार साल में ही प्रभाष जी का सोनिया से मोहभंग हो गया और 2008 में मई में लिख डाला–चूके अवसरों की महादेवी. इसका ज़िक्र मैं ऊपर कर चुका हूं. इस तरह के कई लेख देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश और पत्रकारिता का मूड कैसा रहा होगा. प्रभाष जी के वस्तुनिष्ठ लेखों से समाज की उस सोच का भी पता चलता है जिसमें लोग राजनेताओं के बारे में क्या विचार रखते हैं. प्रभाष जोशी के इन लेखों को एक साथ सामने लाने के लिए सुरेश शर्मा ने जो श्रम किया उसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं.

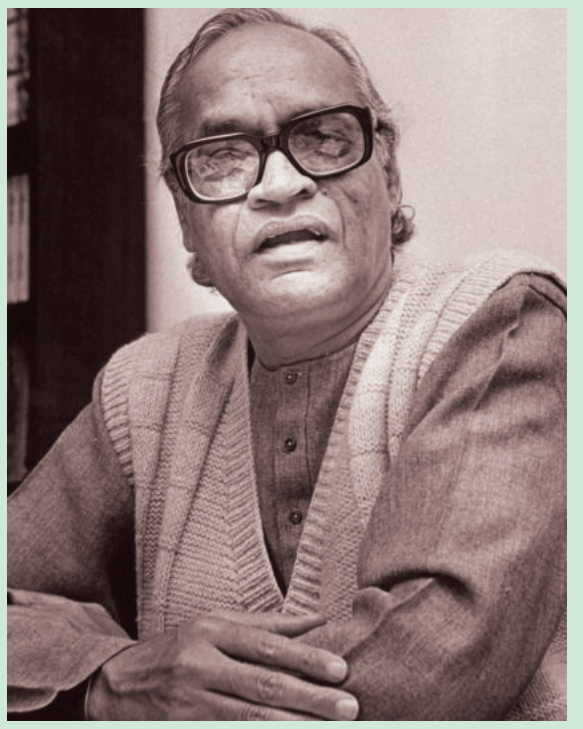

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

उर्दू पत्रकारिता की दिशा और दशा

डॉ. क़मर तबरेज़

पत्रकारिता को अंग्रेज़ी में जर्नलिज़्म कहते हैं. इसकी व्यापक परिभाषा देना बहुत कठिन है. कई लोगों ने इसे अपने तौर पर समझाने की कोशिश की है. अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध साहित्यकार मैथू आर्नल्ड ने पत्रकारिता को जल्दबाज़ी में लिखा गया साहित्य कहा है, जो इस पेशे का निरादर है और मौजूदा दौर का कोई भी पत्रकार इस परिभाषा से संतुष्ट नहीं होगा. पत्रकारिता एक गंभीर और प्रतिष्ठित पेशा है. इसके लिए दिमाग़ी क्षमताओं के साथ–साथ साहस और क़ुर्बानी की भी ज़रूरत होती है. शुरू में सहाफ़त शब्द का प्रयोग सिर्फ़ अख़बार में काम करने के लिए होता था, लेकिन अब अख़बार के साथ–साथ रेडियो और टीवी में काम करने वाले लोग भी ख़ुद को जर्नलिस्ट कहलाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं. वैसे पत्रकारिता का प्रयोग अब व्यापक अर्थों में किया जाने लगा है.

मौजूदा दौर में रेडियो और टेलीविज़न को अधिक लोकप्रियता प्राप्त हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अख़बार का महत्व अपनी जगह बरक़रार है. इसके प्रकाशन में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है. जो लोग रेडियो और टीवी पर ख़बरें सुनने और देखने के आदी हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अख़बार पढ़ना बंद कर दिया हो, बल्कि रेडियो–टीवी पर कुछ शब्दों में कही गई ख़बर को सुनने के बाद उनमें ख़बर की गहराई और विस्तार को जानने की इच्छा और बढ़ जाती है. अख़बार ख़बरों को जितनी गहराई और विस्तृत तथ्यों के साथ पेश करते हैं, रेडियो और टीवी पेश नहीं कर पाते. हालांकि रेडियो और टीवी पर अब एक नई तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा है कि वह किसी ख़ास ख़बर पर उसके विशेषज्ञ को बुलाकर चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे दस्तावेज़ के रूप में सुरक्षित नहीं रख सकते. रेडियो–टीवी पर कोई भी ख़बर हम एक ही बार सुन सकते हैं या देख सकते हैं, भले ही वह पूरी ख़बर आपको समझ में आई हो या न आई हो. अख़बारों के साथ यह समस्या नहीं है. आप जितनी बार चाहें पढ़ें, और उसे हवाले के रूप में इस्तेमाल करें या दस्तावेज़ के रूप में आने वाली नस्लों के लिए सुरक्षित रखें. इसलिए रेडियो–टीवी के मुक़ाबले अख़बार का महत्व और उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है.

यहां यह सवाल उठता है कि आख़िर इंसान ने बोलने की ज़रूरत महसूस ही क्यों की. इसलिए कि उसने अपनी भावनाओं और अहसास को या फिर किसी ऐसी घटना को जिसे सिर्फ़ वही जानता है, दूसरों तक पहुंचाना चाहता था. यहीं से ख़बर की बुनियाद पड़ी. फिर धीरे–धीरे उन्हीं ख़बरों ने दास्तान और इतिहास का रूप धारण कर लिया. कल की ख़बर आज की कहानी बन गई, और फिर एक ज़माना ऐसा आया जब यह एक पेशा बन गया. अख़बार पढ़ना आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, और बने भी क्यों न. आज अगर हम दिन प्रतिदिन की घटनाओं से आगाह नहीं होंगे तो हमें हर पल यह ख़तरा रहेगा कि ज़िंदगी की इस दौड़ में हम कहीं दूसरों से पीछे न छूट जाएं. इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी से इसका गहरा संबंध है.

काग़ज़, स्याही और प्रेस के आविष्कारों से पहले ख़बरें बनतीं और फैलती थीं और लोगों को शासकों के आदेशों से बाख़बर रखा जाता था. इसलिए सबसे बेहतर तरीक़ा यह था कि धार्मिक स्थलों के मुख्य द्वार पर महत्वपूर्ण ख़बरें और शाही घोषणाओं व आदेशों को लिखवा दिया जाता था, क्योंकि इस समय यही वह स्थान होता था, जहां आम लोग भारी संख्या में जमा होते थे. अगर हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो पाएंगे कि हर राज्य और देश में ख़बरी कारिंदे किसी न किसी रूप में मौजूद रहते थे. मुग़ल साम्राज्य में इन लोगों को घटनाकार नाम से पुकारा जाता था. वे जनता के बीच रहकर काम करते थे, लेकिन लोगों को उनके पेशे से संबंधित कोई जानकारी नहीं होती थी. पश्चिमी देशों में तो 18वीं सदी के मध्य में ही इन ख़बरों ने अख़बार का रूप ले लिया था, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई.

भारत में पत्रकारिता की बाक़ायदा शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी जेम्स आग्सटस हिक्की ने की. हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को कोलकाता से एक साप्ताहिक अख़बार हिकेज़ गज़ट के नाम से निकाला, जो कलकत्ता जनरल एडवरटाईज़र के नाम से भी जाना जाता है. यहीं से भारत में पत्रकारिता आरंभ हुई. उर्दू का सबसे पहला अख़बार जाम–ए–जहांनुमा भी मई 1822 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ. इस अख़बार के मालिक हरीहर दत्त थे और संपादक मुंशी सदासुख थे. यह अख़बार साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित होता था, लेकिन इसे अंग्रेज़ों ने अपने हितों के लिए कभी फ़ारसी तो कभी उर्दू में प्रकाशित कराया. फिर इस अख़बार से एक ग़लती हो गई जिसकी वजह से इसे अंग्रेज़ी सरकार की ज़्यादतियों का शिकार होना पड़ा. इस अख़बार ने अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब के सिक्ख राज्य पर हमला करने की तैयारी का भंडाफोड़ कर दिया था, जिसकी वजह से इस अख़बार को ही बंद कर दिया गया था.

उर्दू अख़बारों ने शुरू से ही विरोधी रवैया अपनाया. चूंकि उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था. लिहाज़ा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विरोध की शुरुआत उर्दू अख़बारों ने ही की और देश में आज़ादी और एकता का पैग़ाम दूर–दूर तक पहुंचाया. यहां तक कि जंग–ए–आज़ादी में शहीद होने वाला पहला पत्रकार भी उर्दू अख़बार का ही एक संपादक था. वह पत्रकार मौलवी मोहम्मद बाक़िर थे, जो दिल्ली उर्दू अख़बार निकाला करते थे. अगर हम उर्दू पत्रकारिता की दिशा और गति को देखें तो इसके दौर को आसानी से तीन बड़े युगों में बांट सकते हैं. पहला युग 19वीं सदी का है जब भारत में उर्दू पत्रकारिता का आरंभ हुआ था. दूसरा युग 1901 से भारत–विभाजन यानी 1947 तक का है और तीसरा युग विभाजन से लेकर आधुनिक दौर का है. ये तीनों युग ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं. लिहाज़ा पत्रकारिता के मैदान में भी इन युगों में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं.

पहले प्रेस कमीशन के अनुसार 1953 में भारत से प्रकाशित होने वाले उर्दू अख़बारों की संख्या 436 थी, जो चार साल के बाद बढ़कर 513 हो गई. 1983 से देश से उर्दू में प्रकाशित होने वाले अख़बारों की कुल संख्या (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक) 1330 थी. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उर्दू अख़बार पढ़ने वाले भारी संख्या में थे. इसलिए अख़बारों के प्रकाशन और संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी. इस दौर के प्रसिद्ध अख़बार मिलाप और प्रताप दिल्ली से प्रकाशित होना शुरू हुए और हिंद समाचार ने जालंधर (पंजाब) से अपना नाम कमाया. ये अख़बार आज भी शान से प्रकाशित हो रहे हैं. हैदराबाद से निकलने वाला अख़बार मुंसिफ़ और मुंबई से प्रकाशित होने वाला उर्दू अख़बार इंक़लाब आज भी पत्रकारिता के क्षितिज पर क़ायम है. लेकिन रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने वर्तमान में बेहद लोकप्रियता हासिल की है. उर्दू पत्रकारिता का अतीत बेहद शानदार रहा है, लेकिन इसके भविष्य को लेकर पत्रकारों के ज़ेहन में कोई साफ़ और स्पष्ट लक्ष्य नहीं है.

qamartabrezr@gmail.com

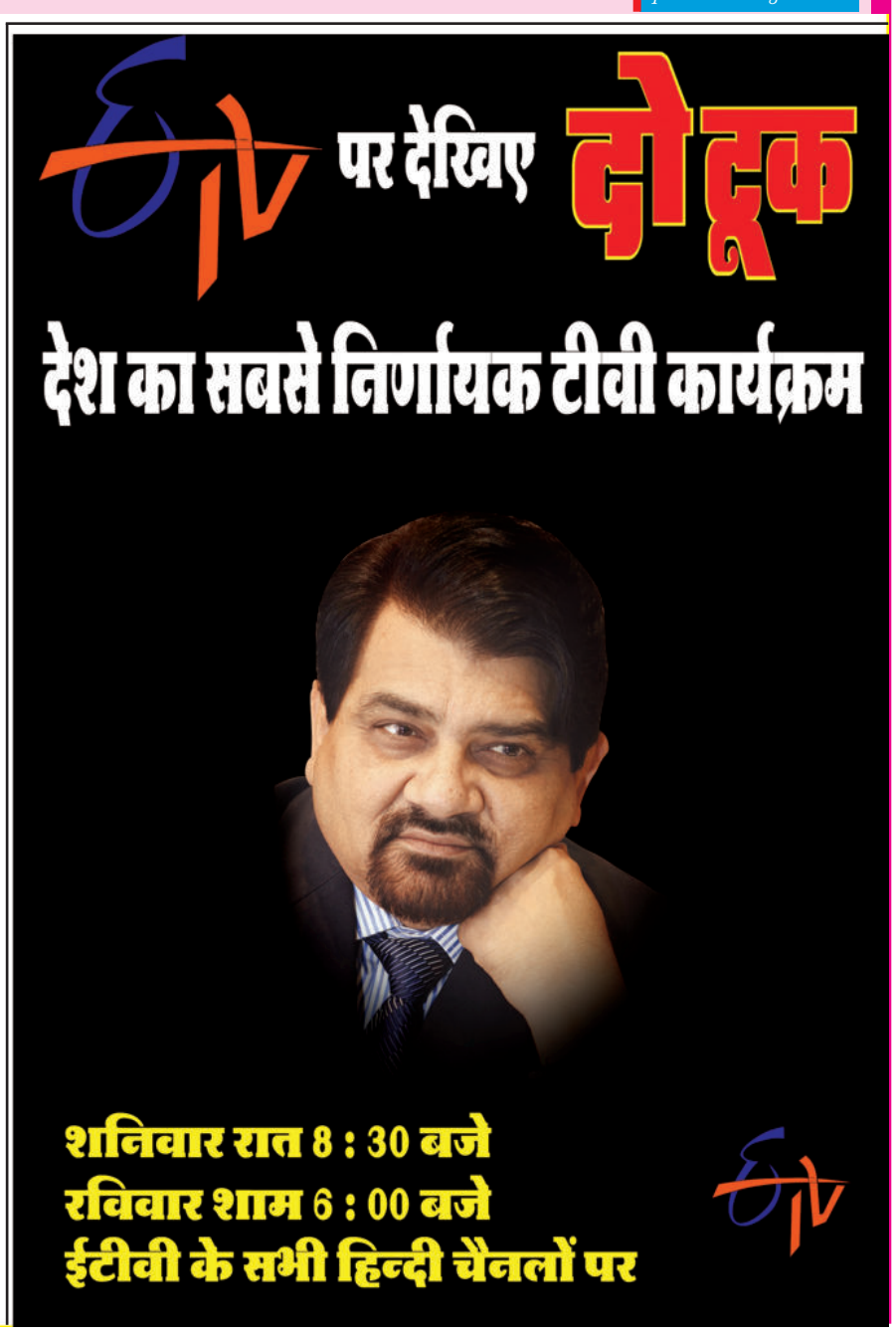

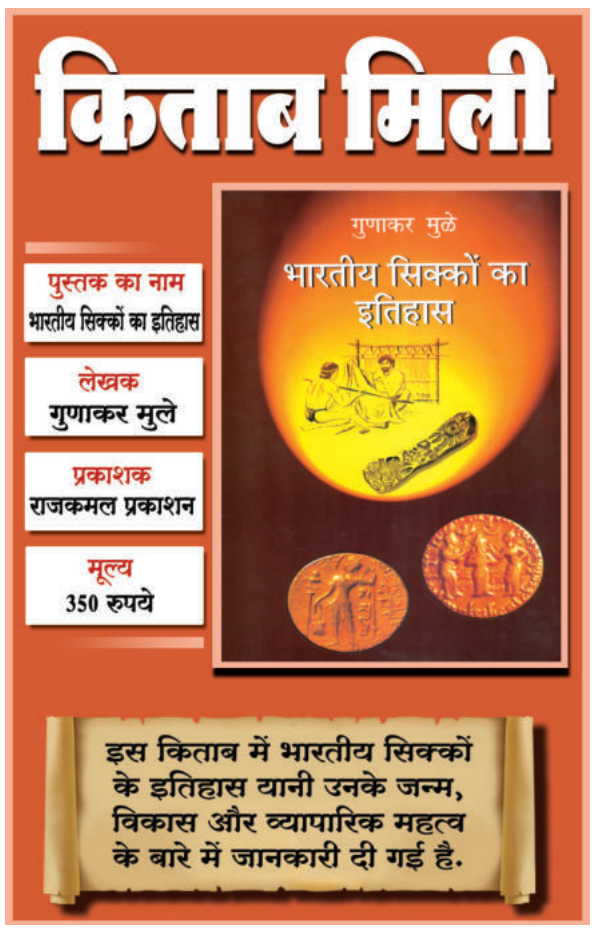

माइक्रोमैक्स ने नए फीचरों वाला एक मोबाइल हैंडसेट बाज़ार में उतारा है, जिसमें 7.1 सेमी की टच स्क्रीन है.

रेनो की नई लग्जरी कार

फ्लुएंस के अलग-अलग मॉडलों की दिल्ली में एक्स शोरूम क़ीमत 12.99 लाख से लेकर 14.40 लाख रुपये तक रखी गई है. रेनो इंडिया के प्रबंध निदेशक मार्क नसिफ ने कहा कि रेनो फ्लुएंस को एशियाई बाज़ार के अनुकूल डिज़ाइन किया गया है.

अगर आप भी लग्जरी कार ख़रीदने की सोच रहे हैं तो अब बाज़ार में आपके लिए एक और नया विकल्प मौजूद है. फ्रांस की जानी-मानी कार निर्माता कंपनी रेनो मोटर्स ने भारतीय बाज़ार में अपनी लग्जरी सेडान फ्लुएंस को लांच कर दिया है. कंपनी ने इसे डीजल और पेट्रोल दोनों तरह के वैरिएंट्स के साथ पेश किया है. फ्लुएंस के अलग-अलग मॉडलों की दिल्ली में एक्स शोरूम क़ीमत 12.99 लाख से लेकर 14.40 लाख रुपये तक रखी गई है. रेनो इंडिया के प्रबंध निदेशक मार्क नसिफ ने कहा कि रेनो फ्लुएंस को एशियाई बाज़ार के अनुकूल डिज़ाइन किया गया है. इसलिए कंपनी को विश्वास है कि यह अपने वर्ग में हलचल पैदा करेगी और भारतीय ग्राहकों को एक ऐसा अनुभव देगी, जिससे उन्हें रेनो के बारे में पता लगे कि कंपनी उनके लिए क्या कर सकती है. फ्लुएंस कंपनी की पहली कार है, जिसकी एसेंबलिंग चेन्नई स्थित कारखाने में की जाएगी. इसका पेट्रोल मॉडल 2000 सीसी और डीजल वैरिएंट 1500 सीसी के इंजन से लैस होगा.

यामाहा के स्कूटर

कंपनी सुराजपुर और फरीदाबाद स्थित अपने संयंत्र में इन स्कूटरों का निर्माण करेगी. इंडिया यामाहा के सीईओ एवं एमडी हिरोयुकी सुजुकी ने कहा कि हम स्कूटर निर्माण की क्षमता 10 लाख करने के लिए 2012 तक 10 मिलियन डॉलर का निवेश करेंगे.

अमेरिका और यूरोप के बाद जापान की दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी यामाहा अब भारतीय बाज़ार में अपनी पैठ बनाना चाहती है. इसके लिए वह जल्द ही अपने स्कूटर लांच करने जा रही है. यामाहा मोटर इंडिया के डायरेक्टर एवं चीफ सेल्स ऑफिसर जुन नकाता ने बताया कि अमेरिका और यूरोप में स्कूटर बेचने के बाद अब कंपनी भारतीय बाज़ार का अध्ययन कर रही है. हम जल्द ही यहां अपने प्रारंभिक स्तर के स्कूटर लांच करेंगे. कंपनी सुराजपुर और फरीदाबाद स्थित अपने संयंत्र में इन स्कूटरों का निर्माण करेगी. इंडिया यामाहा के सीईओ एवं एमडी हिरोयुकी सुजुकी ने कहा कि हम स्कूटर निर्माण की क्षमता 10 लाख करने के लिए 2012 तक 10 मिलियन डॉलर का निवेश करेंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई नया संयंत्र स्थापित नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले से ही स्थापित संयंत्रों की क्षमता में विस्तार किया जाएगा. वर्ष 2011 के दौरान कंपनी को पांच लाख यूनिट बिक्री का अनुमान है. इनमें से 3.5 लाख वाहन घरेलू बाज़ार में उतारे जाएंगे और बाक़ी निर्यात किए जाएंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आईफोन प्रोटेक्टर केस

आईफोन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने वाले लोगों के लिए केस्टोन ने बाजार में एक नया प्रोटेक्टर केस उतारा है. कंपनी का कहना है कि यह केस अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार किया गया है. इसमें तीन परतें हैं, जो आईफोन को पूरी सुरक्षा देती हैं. इसमें पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी ध्यान में रखा गया है, इसलिए इसे आईपी 45 पर्यावरण प्रोटेक्शन रेटिंग के तहत बनाया गया है. इसे 360 डिग्री पर रोटेट किया जा सकता है. साथ ही इसे हैंडबैग्स, ब्रीफकेस और बेल्ट के साथ अटैच किया जा सकता है. इसका साइज 129 मिमी बाई 69.5 मिमी बाई 18 मिमी रखा गया है.

ऑल इन वन पीसी

एलजी ने बाज़ार में एलजी वी-300 नामक नया पर्सनल कंप्यूटर उतारा है. कंपनी ने इस पीसी को इंटेल के साथ मिलकर तैयार किया है. इसमें नई तकनीक का प्रयोग किया गया है और दूसरी पीढ़ी के इंटेल कोर प्रोसेसर, डीएफपीआर डिस्प्ले एवं तीन कैमरे लगाए गए हैं. इसमें 750 जीबी की मेमोरी है. सा थ ही स्टीरियो माइक्रोफोन और अन्य कई चीजें भी. कंपनी का कहना है कि इस पीसी में ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिससे ऊर्जा की खपत में भी कमी आएगी.

माइक्रोमैक्स का नया हैंडसेट

भारत की चर्चित मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स ने नए फीचरों वाला एक मोबाइल हैंडसेट बाज़ार में उतारा है, जिसमें 7.1 सेमी की टच स्क्रीन है. साथ ही जीपीएस सपोर्ट और वाई फाई वायरलेस पॉकेट इंटरनेट की सुविधा भी है. इसमें 3 मेगा पिक्सल का कैमरा है और 32 जीबी की मेमोरी. इस फोन में मोबाइल रेडियो के साथ ही ऑन डिमांड जैसी सुविधा भी है. यह फोन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर काम करेगा.

साटा रेव 3 ड्राइव

स्टोरेज गैजेट्स के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी किंगस्टन ने नई साटा रेव 3.0 सॉलिड स्टेट ड्राइव लांच करने की घोषणा की है. इस ड्राइव में 6 जीबी प्रति सेकेंड के हिसाब से डाटा ट्रांसफर करने की क्षमता है. इसमें 120 जीबी और 240 जीबी की स्टोरेज क्षमता है. इसमें रीडिंग और राइटिंग क्षमता 525 और 480 प्रति सेकेंड है. इस ड्राइव को तीन साल की वारंटी के साथ बाज़ार में उतारा जाएगा. इसकी क़ीमत के बारे में कंपनी ने अभी कुछ नहीं कहा है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

ब्राजील के लिए 97 अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबले खेल चुके रोनाल्डो ने आंसुओं के साथ अपने फुटबॉल करियर की समाप्ति की घोषणा की.

अलविदा

राजेश एस कुमार

कुछ खेल ऐसे होते हैं जो खिलाड़ियों को नाम, दाम और शौहरत दिलाते हैं और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिनके नाम से उस खेल की पहचान जुड़ जाती है. फुटबॉल का नाम लेते ही आम फुटबॉल प्रेमियों के ज़ेहन में पहला नाम पेले का आता है और पेले के बाद माराडोना, लेकिन नई पीढ़ी के लिए अगर कोई नाम इस तरह का है तो वह निश्चित तौर पर रोनाल्डो का है. वैसे लोग भी जो फुटबॉल में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, वे भी रोनाल्डो के नाम से अपरिचित नहीं हैं. रोनाल्डो फुटबॉल के मैदान में ही नहीं खेल की दुनिया का एक ऐसा चमचमाता सितारा है, जिसकी चमक आने वाले कई सालों तक धूमिल नहीं पड़ने जा रही है. बावजूद इसके कि फुटबॉल मैदान पर रोनाल्डो का वह रोमांचित करने वाला कारनामा देखने को फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि रोनाल्डो ने फुटबॉल को अलविदा कह दिया है. बिना रोनाल्डो का नाम लिए लीजेंड लिस्ट पूरी ही नहीं हो सकती है. अगर फुटबॉल का जादूगर पेले को माना जाता है तो इस खिलाड़ी का जादू भी फुटबॉल प्रेमियों के सर कम चढ़कर नहीं बोला है, लेकिन फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह बहुत बुरी ख़बर है. अब रोनाल्डो को चाहने वालों को इस महान खिलाड़ी की किक देखने को नहीं मिलेगी. इसकी वजह यह है कि रोनाल्डो ने हाल ही में फुटबॉल को अलविदा कह दिया है. जी हां, ब्राजील के रोनाल्डो लुइस नाज़ारियो डी लीमा ने फुटबॉल से आख़िरकार अलविदा कह ही दिया. ग़ौरतलब है कि रोनाल्डो पिछले कुछ समय से लगातार चोटों से दो चार हो रहे थे. ऐसे में क़यास लगने शुरू हो गए थे कि अब शायद यह नायाब खिलाड़ी बहुत दिनों तक मैदान में टिक नहीं पाएगा. ऐसा ही हुआ.

ब्राजील के लिए 97 अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबले खेल चुके रोनाल्डो ने आंसुओं के साथ अपने फुटबॉल करियर की समाप्ति की घोषणा की. रोनाल्डो ने कहा कि अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता. मैं खेलना चाहता हूं, लेकिन शरीर इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है. विश्व के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार रोनाल्डो तीन बार फ़ीफ़ा द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी चुने जा चुके हैं. यहां पर ग़ौर करने वाली बात यह है कि रोनाल्डो ने अपने संन्यास की घोषणा अपनी बढ़ती उम्र की वजह से नहीं, बल्कि चोट के कारण की है. 2010 की फ़रवरी में रोनाल्डो ने कहा था कि वह 2011 में खेल से रिटायर हो जाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया. उनकी उपलब्धियों का ज़िक्र किया जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाएं. फुटबॉल के जादूगर पेले ने दुनिया के महानतम फुटबॉलरों की सूची तैयार की थी, उसमें रोनाल्डो का भी नाम था. पिछले साल ही फुटबॉल की एक मशहूर वेबसाइट गोल डॉट कॉम के एक ऑनलाइन पोल में दशक के खिलाड़ी के रूप में रोनाल्डो को सबसे ज़्यादा वोट मिले. इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस खिलाड़ी में जीत का कितना जज़्बा था. 34 वर्षीय रोनाल्डो फ़ीफ़ा द्वारा तीन बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉल खिलाड़ी हैं. इससे पहले फ्रांस के जिनेदिन जिदान को यह सम्मान मिल चुका है. रोनाल्डो 1994 और 2002 में विश्व कप जीतने वाली ब्राजीली टीम के सदस्य रह चुके हैं. फुटबॉल के इतिहास में जिनेदिन जिदान और रोनाल्डो ही दुनिया के सिर्फ़ दो ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें खेल की शीर्ष संस्था फ़ीफ़ा का प्लेयर ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड तीन बार हासिल हुआ है.

22 सितंबर 1976 को रोनाल्डो लुइस नाज़ारियो दि लीमा नाम के साथ जन्मे रोनाल्डो फुटबॉल खेल जगत में उस समय चमक के साथ प्रकट हुए थे जब 20वीं सदी का आख़िरी दशक चल रहा था और 21वीं सदी आ रही थी. 21 साल की उम्र में अपना पहला ख़िताब पाने वाले रोनाल्डो फुटबॉल की वह जादुई चमक हैं जिसकी झलक पेले और माराडोना ने दिखाई थी. पेले और माराडोना के बाद रोनाल्डो समकालीन लातिन फुटबॉल के सर्वाधिक प्रसिद्ध खिलाड़ियों में एक हैं. रोनाल्डो के खेल की यह रोचकता है कि उन्हें देखते ही प्रतिस्पर्धी दाएं बाएं नहीं हो जाता. वह उन्हें कुछ इस तरह दोस्ताना चुनौती में सहजता में साथ ले आते हैं और फिर उनके बीच अपनी वह निराली विनम्र टॉसिंग फ्लिकिंग करते थे. वहां गेंद प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के पांव से टकराती हुई वापस रोनाल्डो के पांवों से चिपक जाती है. वह अपने दोनों पांवों को गेंद खेलाते हुए दौड़ते जाते हैं. रोनाल्डो ने बड़ी स्ट्राइको की अपेक्षा बजाय ज़्यादातर सरकाते हुए कोण बनाते हुए ऐन गोलपोस्ट तक पहुंचते हुए छकाते हुए गोल किए हैं. अपने दिग्गज अग्रजों और अपने प्रतिभाशाली समकालीन खिलाड़ियों की खेल ऊर्जा को रोनाल्डो ने अपने खेल में समाहित करने की कोशिश की थी. रोनाल्डो ने खेल की बदौलत अपार लोकप्रियता, अपार प्रतिष्ठा और अपार अमीरी हासिल की.

वह उन असाधारण दिनों में अपनी पीली जर्सी पहने चमक रहे थे, जब बाज़ार फुटबॉल के मैदान में बढ़ता ही चला आ रहा था. रोनाल्डो ऐसे ही उस दौर के शिकंजे में आए हुए बीमार पस्त खिलाड़ी रह चुके थे जब 1998 के विश्व कप में उनकी टीम को फ्रांस से मात खानी पड़ी थी. इंजेक्शन देकर उन्हें मैदान पर उतारा गया था. वह फ़ाइनल खेलने लायक़ नहीं थे. पारिवारिक मुश्किलों, अवसाद और चोटों से बीमार रोनाल्डो ड्रेसिंग रूम में उल्टी कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम उनके देश उनकी कंपनी उनके क्लब उनके नाम का इतना भारी दबाव था कि रोनाल्डो को न उतारने की कल्पना कोई कर ही नहीं सकता था. ख़ुद रोनाल्डो हैरान थे. उस दिन उन्हें पहली बार लगा था कि प्रेत भी फुटबॉल के मैदान पर जाकर भाग सकते हैं. इधर–उधर निरीह ढंग से गेंद को धकियाते ख़ुद को फेंकते रह सकते हैं. 2002 का विश्व कप इसका गवाह है. जहां रोनाल्डो अविश्वसनीय और ऐतिहासिक ज़िद के साथ मैदान पर उतरे थे और अपनी टीम को विश्व कप जिताने में प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई थी. रोनाल्डो इस जीत के बाद ब्राज़ील ही नहीं, सहसा पूरे खेल के ही महानायक बन गए थे. कहते हैं कि किसी की भी सफलता में उसके संघर्ष की महान गाथा छिपी होती है, ऐसी ही गाथा रोनाल्डो की भी है. अपने प्रदर्शन और योगदान की बदौलत कुछ ऐसी भूमिका में आ जाते हैं कि उनके जाने के बाद उस टीम के अस्तित्व की कल्पना करना ही मुश्किल हो जाता है. ऐसा लगने लगता है कि जब यह खिलाड़ी संन्यास की घोषणा करेगा तो फिर उसकी जगह कैसे भरेगी. जहां क्रिकेट में मास्टर बलास्टर सचिन तेंदुलकर को लेकर इस तरह की चर्चाएं होंगी, वहीं रोनाल्डो के संन्यास लेने के बाद फुटबॉल प्रेमियों के बीच भी कुछ ऐसी ही बहस छिड़ गई है. बहरहाल, रोनाल्डो ने भले ही ख़ुद को फुटबॉल मैदान से दूर कर लिया, लेकिन उनके करोड़ों फैंस उन्हें अपने दिल से दूर नहीं कर सकेंगे.

तमगे ज़्यादा और कंधा छोटा

रोनाल्डो ने यूरोप और दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल क्लबों के लिए खेलते हुए 350 से अधिक गोल किए. रोनाल्डो को वर्ष 1997 में सबसे पहले 21 वर्ष की उम्र में यूरोप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था. वर्ष 2007 में फ्रांस फुटबॉल ने अपने सर्वकालिक महान अंतरराष्ट्रीय टीम में रोनाल्डो को जगह दी. इसके अलावा फीफा ने इसी वर्ष रोनाल्डो को ब्राजील के महानतम खिलाड़ी पेले के साथ अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के 100 शीर्ष खिलाड़ियों में स्थान दिया. इंटर के लिए रोनाल्डो ने 68 मैचों में 49 गोल किए, जबकि रियल के लिए उन्होंने 127 मैचों में खेलते हुए 83 गोल किए. विश्व कप के लिए ब्राजीली टीम में जगह नहीं मिलने से निराश रोनाल्डो ने 2009 में ब्राजील के क्लब कोरिंथियंस के साथ क़रार किया और अपने करियर के अंतिम दिनों तक इसी क्लब के लिए खेले. इस क्लब के लिए रोनाल्डो ने 31 मैचों में 18 गोल किए. रोनाल्डो ने विश्व कप में कुल 15 गोल किए हैं. वर्ष 2006 के फ़ीफ़ा विश्व कप में हिस्सा लेने वाले रोनाल्डो ने विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया. उन्होंने इस वर्ष जर्मनी के गर्ड मुलर के 14 गोल के रिकार्ड को ध्वस्त किया.

रोनाल्डो के नाम और भी कई रिकॉर्ड हैं. 2007 में हुए एक पोल में उन्हें सर्वकालिक टीम के ग्यारह खिलाड़ियों में से एक चुना गया.

rajeshy@chauthiduniya.com

फुटबॉल के 100 शीर्ष खिलाड़ियों में स्थान दिया. इंटर के लिए रोनाल्डो ने 68 मैचों में 49 गोल किए, जबकि रियल के लिए उन्होंने 127 मैचों में खेलते हुए 83 गोल किए. विश्व कप के लिए ब्राजीली टीम में जगह नहीं मिलने से निराश रोनाल्डो ने 2009 में ब्राजील के क्लब कोरिंथियंस के साथ क़रार किया और अपने करियर के अंतिम दिनों तक इसी क्लब के लिए खेले. इस क्लब के लिए रोनाल्डो ने 31 मैचों में 18 गोल किए.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 27 जून–3 जुलाई 2011

ख़बर है कि सेलिना जेटली सामाजिक गतिविधियों से लगातार जुड़ी हुई हैं. अब वह लोगों को पर्यावरण के प्रति भी जागरूक करने में लग गई हैं.

हिट शो के लिए तरसते शो मैन

कैसे ब्लैक एंड व्हाइट हुए कलरफुल सुभाष घई

सुषमा गुप्ता

वर्ष 1993 में उस वक़्त के सबसे बड़े निर्देशक सुभाष घई की फिल्म आई खलनायक. संजय दत्त स्टारर इस फिल्म ने ख़ूब वाहवाही बटोरी, लेकिन इसकी बड़ी वजह फिल्म के साथ जुड़े विवाद रहे. चाहे वह संजय दत्त का जेल जाना रहा हो या फिर इसका गीत चोली के पीछे....फिल्मी पंडितों और दर्शकों को इसमें वह बात नज़र नहीं आई, जो सुभाष घई को उस दौर में राजकपूर का खिताब दिलाती थी. यह भारतीय सिनेमा के एक निर्देशक का फिल्मी साम्राज्य ख़त्म होने का दौर था. इसके बाद 1994 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन. यह फिल्म उसी युवा निर्देशक सूरज बड़जात्या की थी, जिसकी 1989 में आई पहली फिल्म मैंने प्यार किया ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और मारधाड़ मय हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री में फिर से प्यार की अलख जगाई थी, लेकिन हम आपके हैं कौन के रूप में सबसे बड़ी कामयाबी बड़जात्या का इंतज़ार कर रही थी. रिलीज़ के साथ ही इस फिल्म ने मैंने प्यार किया की कामयाबी को भी पीछे छोड़ दिया. फिल्म का क्रेज़ ऐसा कि जिस शहर की आबादी केवल 3 लाख के क़रीब है, वहां इसने सिल्वर जुबली मनाई. यह फिल्म भारतीय फिल्म इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना साबित हुई. लोग पूरे परिवार के साथ गांव से बैलगाड़ी में बैठकर इसे देखने आए. यह फिल्म इस इंडस्ट्री में एक नए साम्राज्य के उदय और पुराना साम्राज्य ढलने का संदेश लेकर आई. जो स्थान, जो तमगा सुभाष घई को मिला था, वह सूरज बड़जात्या को मिल गया. दो ब्लॉक बस्टर के साथ सूरज बड़जात्या भारतीय फिल्मोद्योग के सबसे बड़े निर्देशक बन गए और उन्हें शो मैन कहा जाने लगा. वहीं माना जाने लगा कि सुभाष का सूरज ढलान पर आ गया है.

समय के पहिए को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं वर्तमान में. वर्ष 2011. एक बार फिर हालात पूरी तरह बदले हुए हैं. आज न बड़जात्या की लिखी कहानी कमाल दिखा पा रही है और न उनके बैनर की कोई फिल्म. 1994 से 2011 के बीच सिनेमा काफी कुछ बदला. इस दौरान कई फिल्मकार आए, जो कुछ समय के लिए छाए रहे. कभी जौहर का बोलबाला रहा तो कभी यशराज की धूम. कभी संजय लीला भंसाली को विमल राय का उत्तराधिकारी बताया गया तो कभी राम गोपाल वर्मा अपना लोहा मनवाते रहे. दरअसल इस दौर में निर्देशकों की जगह बैनरों ने ले ली और इसकी शुरुआत की यशराज ने. कुछ साल पहले तक इस बैनर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की गारंटी मानी जाती थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी सारी फिल्में पिट रही हैं. आज नए दौर के सिनेमा का ज़माना है, जहां पुराने हिट फिल्मकार दर्शकों की नब्ज़ पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं. पुराने ज़माने के शो मैन हिट शोज़ के लिए तरस रहे हैं. जो हाल घई और बड़जात्या का है, वही हाल संजय लीला भंसाली, राम गोपाल वर्मा, इंद्र कुमार और करण जौहर जैसे फिल्मकारों का है. हैरानी की बात यह है कि प्रतिभाशाली निर्देशक उस दौर में पिछड़ रहे हैं, जिसमें नई कहानियों पर बनी क़रीब हर फिल्म सफलता हासिल कर रही है. अख़िर भूल कहां हो रही है. इन काबिल निर्देशकों से ज़्यादा बेहतर यह बात कोई नहीं जानता होगा कि कमी कहां रही है, लेकिन उनकी फिल्मों को देखकर कुछ आकलन तो हो सकता है. सबसे पहले बात सुभाष घई की, जो आजकल फिल्म निर्देशन के अलावा मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले नई–नई फिल्मों का भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उनमें कौन सी फिल्म चलेगी, इसकी गारंटी वह ख़ुद भी नहीं दे सकते. एक वक़्त था, जब वह राजकपूर के बाद दूसरे शो मैन कहे जाते थे. उनका नाम ही फिल्म को हिट करने की गारंटी होता था. क़र्ज़, विधाता, हीरो, कर्मा, सौदागर, राम लखन जैसी एक के बाद एक कई हिट फिल्में. जिस दौर में फिल्म इंडस्ट्री का मतलब अमिताभ बच्चन था, उस दौर में सुभाष घई की मुक्ता आर्ट्स कामयाबी का दूसरा नाम थी. उस दौर में अभिनेताओं का बोलबाला था, लेकिन सुभाष घई उन गिने–चुने निर्देशकों में से थे, जो निर्देशक होते हुए भी बॉक्स ऑफिस पर सितारा थे. सुभाष घई की फिल्में पूरी तरह मसाला फिल्में होती थीं, जिनमें बड़ी स्टारकास्ट, ज़ुबान पर चढ़ने वाला संगीत, रोमांस और मारधाड़ यानी सब कुछ होता था. अमूमन उनकी कहानी असत्य पर सत्य की जीत की थीम पर आधारित होती थी, लेकिन कहानी का बढ़िया ट्रीटमेंट उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी ख़ासियत हुआ करता था. बेअसर खलनायक के बाद उनकी शाहरुख, अनिल कपूर और जैकी श्राफ स्टारर त्रिमूर्ति फ्लॉप हो गई.

बड़जात्या, चोपड़ा और जौहर की फिल्मों के साथ जब सिनेमा ने ऐसे दौर में क़दम रखा तो फैमिली ड्रामा के साथ चलने वाली लव स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का फॉर्मूला बन गई. तब सुभाष घई को शायद लगा कि वह भूल कर रहे हैं और उन्होंने अपना ट्रैक चेंज कर लिया. त्रिमूर्ति के फ्लॉप होने के बाद वह शाहरुख ख़ान के साथ परदेस लेकर आए. फिल्म हिट साबित हुई, लेकिन फिल्म की कहानी, उसके पात्र, सब बदले हुए थे. यह बड़जात्या–चोपड़ा नुमा विशुद्ध एनआरआई लव स्टोरी थी. इसमें सुभाष घई की छाप ग़ायब थी. इसके दो साल बाद वह फिर एक फिल्म लेकर आए ताल. फिल्म हिट हुई. ए आर रहमान ने शानदार संगीत तैयार कराया. यह फिल्म भी लव स्टोरी थी, लेकिन इसमें अनिल कपूर के माध्यम से घई की छाप नज़र आई, पर यह फिल्म सुभाष घई के निर्देशन में आख़िरी हिट साबित हुई. इसके बाद सुभाष घई की कहानी विदेशों में चली गई. अपनी फिल्मों का मसाला तो पहले ही उन्होंने फीका कर दिया था. कहानी के विदेश जाने के बाद यह और फीका हो गया. गाने हिट हुए, लेकिन वह धूमधड़ाका ग़ायब था, जिसके लिए उन्हें जाना जाता था. इसके बाद उनकी फिल्म आई किसना, लेकिन ए आर रहमान का संगीत और विदेशी नायिका का साथ भी किसना को नहीं बचा पाया. किसना में प्रेम का एक और रूप दिखाया गया था, लेकिन दर्शकों के लिए यह प्रेम समझ से परे था. इस बीच उन्होंने सिर्फ़ प्रोड्यूसर की कुर्सी पर बैठकर कई फिल्में दूसरे निर्देशकों से बनवाईं, लेकिन इक़बाल को छोड़कर किसी फिल्म ने उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं की. इस बीच घई ने एक और फिल्म निर्देशित की, ब्लैक एंड व्हाइट. उन्होंने एक अलग किस्म की फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन यह भी दर्शकों को नहीं लुभा पाई. इस फिल्म के फ्लॉप होने के साथ ही यह तय हो गया कि सुभाष घई का जादू ख़त्म हो चुका है.

सुभाष घई ने एक बार फिर सबसे हॉट जोड़ी सलमान–कैटरीना को लेकर युवराज बनाई. संगीत दमदार हो, लिहाज़ा उन्होंने ए आर रहमान को लिया, लेकिन इसका संगीत भी लोगों के दिल में जगह नहीं बना सका. दरअसल उनका जादू भारतीय मसाला किस्म के सिनेमा में बसता था, जिसमें भारत का समाज होता था, रिश्तों की गर्माहट होती थी, ख़ुशी–गम साझा होते थे और दर्शक भी उसमें ख़ुद को जुड़ा हुआ पाते थे. उनकी पकड़ भारतीय दर्शकों की नब्ज़ पर थी, लेकिन वह अपनी कहानी को और दुरुस्त करने के बजाय नई तकनीक का समावेश करने के चक्कर में अपने सिनेमा को ही बदल बैठे. इंडिया की फिल्म बनाने के चक्कर में उन्होंने मौलिकता ही छोड़ दी. सुभाष घई की फिल्मों की ख़ासियत उसका संगीत होता था, लेकिन हर फिल्म में नए संगीतकार को लेकर उन्होंने अपनी एक टीम नहीं बनाई, जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से संगीत तैयार कर सकें. सुभाष घई की फिल्मों में ज़िंदगी के हर रंग होते थे, हंसी होती थी, उल्लास होता था, गम होता था, लेकिन ख़ुद को बदलने के चक्कर में उन्होंने न केवल एक–एक करके सारे रंग फीके किए, बल्कि सबको ग़ायब करके उसे ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया.

feedback@chauthiduniya.com

लीजा की तन्मयता

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से उबरने में लगी लीजा रे में ग़ज़ब की हिम्मत है. कनाडा में रहने वाली भारतीय-कनाडाई अभिनेत्री लीजा को फिल्मी दुनिया में वापसी की जल्दी नहीं है. वह कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और किताब लिखने के लिए प्रयासरत हैं. कोशिकाओं के एक दुर्लभ कैंसर के इलाज के बाद स्वस्थ जीवन जी रहीं 38 वर्षीय लीजा कहती हैं कि वह आगे भी फिल्मों में काम करेंगी, लेकिन अब यह काफी अलग होगा. लीजा की बीमारी मल्टीपल माईलोमा में सुधार हुआ है, पर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है. डॉक्टर उन पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और अब वह स्वस्थ और सामान्य जीवन जीने की कोशिश में लगी हैं. लीजा को अपनी फिल्म कुकिंग विद स्टेला के प्रदर्शन का भी इंतज़ार है. लीजा सिर्फ़ वह काम करना चाहती हैं, जिसमें उन्हें सुकून मिले और वह ज़िंदगी अपनी ही शर्तों पर जीना चाहती हैं. लीजा ने करियर के लिए अपने जीवन में बहुत समझौते किए और कैंसर उनके लिए एक चेतावनी की तरह है. अब वह कैंसर के विषय में जागरूकता फैलाना चाहती हैं और इन दिनों उसी पर काम कर रही हैं. फिल्मों के साथ अब कैंसर भी उनके करियर का हिस्सा बन गया है. कुकिंग विद स्टेला के बाद लीजा ने फ़िलहाल फिल्मों के नए प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए हैं. फ़िलहाल उन्हें कैंसर पर चर्चा के लिए अमेरिका बुलाया गया है.

समाज सेविका सेलिना जेटली

सेलिना को भले ही फिल्मों में काम न मिल रहा हो, लेकिन उन्हें जहां भी मौक़ा मिलता है, वह समाज सेवा करके सुर्ख़ियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़तीं. हाल में उन्होंने होमो सेक्सुअल लोगों के एनजीओ की ब्रांड एंबेसडर के रूप में कई जगहों पर प्रचार किया. अब ख़बर है कि सेलिना जेटली सामाजिक गतिविधियों से लगातार जुड़ी हुई हैं. अब वह लोगों को पर्यावरण के प्रति भी जागरूक करने में लग गई हैं. ख़बर है कि उन्हें प्लांट अ ट्री नामक एक कैंपेन के लिए ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है. इसका नेतृत्व करते हुए वह लोगों में देश को हरा–भरा रखने के लिए जागरूकता पैदा करेंगी. सेलिना कहती हैं कि यह कैंपेन लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सही प्लेटफॉर्म है और उन्हें उम्मीद है कि इस काम में सभी उनका सहयोग करेंगे. दोस्तों की मदद करने में भी काफी आगे रहती हैं सेलिना. अभी हाल में वह एक विवाद में बिपाशा बसु का साथ देने के लिए कूद पड़ी थीं. बिपाशा का नाम राजनेता अमर सिंह के साथ जुड़ गया था, लेकिन बिपाशा ने उस टेप में अपनी आवाज़ होने से इंकार कर दिया था. सेलिना ने उनका साथ देते हुए कहा कि वह बिपाशा को कोलकाता के दिनों से जानती हैं और बिपाशा की आवाज़ टेप में नहीं है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

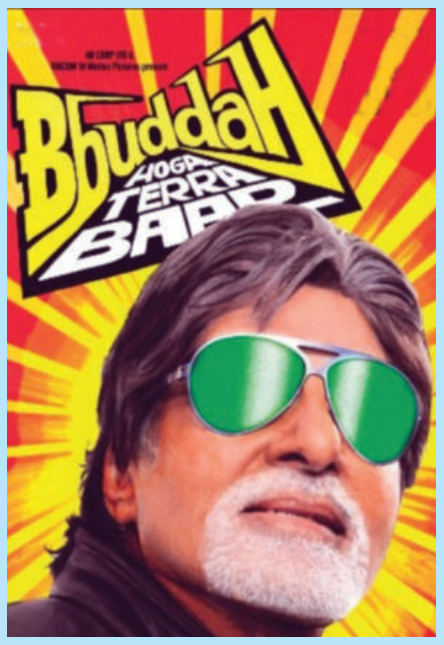

बुड्ढा होगा तेरा बाप

इन दिनों चर्चा हो रही है कि फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप की. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपनी चिर-परिचित एंग्री यंग मैन वाली छवि में नज़र आएंगे. सिर्फ़ यहीं नहीं, बुड्ढा होगा तेरा बाप में अमिताभ बच्चन स्टाइलिश दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. यानी एक बार फिर अपना मेकअप और कॉस्टयूम का अंदाज़ बदल लेने से उनकी यह फिल्म बन गई है चर्चा का विषय. इस फिल्म के डायरेक्टर हैं पुरी जगन्नाथ और प्रोड्यूसर हैं राम गोपाल वर्मा. फिल्म में बिग बी के साथ उनके ही दौर की ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी और आज के दौर के कलाकारों में मिनिषा लांबा, रवीना टंडन, सोनल चौहान, नेहा शर्मा एवं सोनू सूद हैं. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे शख़्स का रोल निभाया है, जिसकी उम्र तो है 60 साल, लेकिन वह ख़ुद को किसी जवान से कम नहीं समझता है. हालांकि इस वजह से उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अपने डिज़ाइनर स्कार्व्स, डेनिम्स और ब्रैंडेड ग्लेयर्स के साथ इन दिनों उन्हें बेहद कूल लुक में देखा जा सकता है. इसी स्टाइल के चलते उन्होंने फिल्म में एक साथ दो घड़ियां पहनी हैं. देखते हैं, स्टाइल के साथ बिग बी का यह डबल डोज स्क्रीन पर कैसा रहता है!

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 27 जून-3 जुलाई 2011

www.chauthiduniya.com

सरकार ने रोके शिक्षा के द्वार

शिक्षा-उच्च शिक्षा में विकास भी बड़े पैमाने पर हुआ. लेकिन इस विकास के बावजूद आज यह तथ्य मौजूद है कि क्या यह विकास आज उस वर्ग तक पहुंच पाया जिस वर्ग के लिए इसे पहुंचना था? अब नए सिरे से विचार की नौबत आ गई है. कई प्रश्न खड़े हो गए हैं. क्या शिक्षा पर सबका अधिकार है? क्या उच्च शिक्षा आज आम आदमी का मूलभूत अधिकार है? क्या शिक्षा आज आम आदमी तक उपलब्ध है?

प्रवीण महाजन

शिक्षा के नाम पर सरकार की घोषणाएं बचकानी हैं. शिक्षा के नाम पर सरकार के आश्वासन बकवास हैं. देश में सर्व शिक्षा अभियान का ढिंढोरा पीटना दूर के ढोल सुहावने जैसा है. 1964 में बनी कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना तो दूर उसकी अनुशंसा के अनुरूप कुल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी तो दूर अब तक 4 फीसदी भी शिक्षा पर ख़र्च नहीं किया गया है. सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विकास का बुनियादी आधार क्या है? जब विकास के बुनियादी आधार तय किए गए, तो उनमें स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख थे. कमोवेश आज दोनों ही क्षेत्रों में सरकार की बेपरवाही या यूं कहें सरकार में बैठे नेताओं की स्वार्थ लोलुपता का तकाजा है कि निजी क्षेत्र इस क़दर हावी हो चुके हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है. शिक्षा के नाम पर महज़ 10 वीं पास करा देना या फिर 7वीं पास करा देना ही सरकार ने सर्वसाधारण के लिए शिक्षा के मायने समझ लिया है. कितनी दुखद और शर्मनाक स्थिति है एक देश के लिए, उस देश के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश कहलाता है, जो दुनिया की 10 बड़ी महाशक्तियों में शरीक़ है, जो भविष्य की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो, जिसकी प्रतिभाओं से अमेरिका जैसा विकसित देश घबरा रहा है.

यह असंतुलन है. असंतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है. पूंजीवाद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है. आज़ादी के बाद से ही जब हम परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो नियोजनकर्ताओं के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा का मामला प्राथमिक रहा. शिक्षा-उच्च शिक्षा में विकास भी बड़े पैमाने पर हुआ. लेकिन इस विकास के बावजूद आज यह तथ्य मौजूद है कि क्या यह विकास आज उस वर्ग तक पहुंच पाया जिस वर्ग के लिए इसे पहुंचना था? अब नए सिरे से विचार की नौबत आ गई है. कई प्रश्न खड़े हो गए हैं. क्या शिक्षा पर सर्वाधिकार है? क्या उच्च शिक्षा आज आम आदमी का मूलभूत अधिकार है? क्या शिक्षा आज आम आदमी तक उपलब्ध है? 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रास एनरोलमेंट 18 से 20 फीसदी तक करने का प्रयास ही यह दर्शाता है कि उच्च शिक्षा देश के कितने लोगों तक उपलब्ध है. अगर शिक्षा को महिला-पुरुष, शहरी-ग्रामीण, पिछड़ा-अगड़ा में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है. यथार्थ सामने आ जाता है. शिक्षा सहज उपलब्ध नहीं है. यह सत्य है. खौफनाक सत्य है. यहां स्पष्ट कर दें कि सवाल शिक्षा के अधिकार की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं.

एक ज़माना था जब वर्ण आधारित समाज था. यानी सब कुछ वर्ण के आधार पर होता था. शिक्षा भी वर्ण के आधार पर होती थी. आज कास्ट (जाति) नहीं बल्कि कोस्ट (धन) के आधार पर शिक्षा उपलब्ध होती है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आख़िर क्यों बढ़ा ख़र्च? जवाब साफ़ है. शिक्षा के क्षेत्र में शासन की भागीदारी कम हो रही है. कायम बिना अनुदानित शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है. महाराष्ट्र में 1980 के दशक के बाद निजी शिक्षण संस्थाएं अस्तित्व में आईं. 1990 के बाद ये संस्थाएं मज़बूत हुईं और सन 2000 के बाद ये पूरी तरह राज्य में मज़बूत हो गईं. इसके बाद शुरू हो गया शिक्षा के क्षेत्र में सब्सिडी का पूरी तरह ख़ात्मा और गुणवत्तापूर्ण और उच्च शिक्षा से आम आदमी की पूरी तरह दूरी. जिसके पास पैसा है, उसके पास शिक्षा है. जिसके पास पैसा है, उसके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है. इन सबके बीच खो गया शिक्षा का सर्वाधिकार. हां, उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विदेशों में शिक्षा के रास्ते ज़रूर बेहतर हुई है. लेकिन किसके लिए? सिर्फ़ चंद लोगों के लिए. समाज के उस घटक के लिए जो अभिजात्य है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सरकारी सब्सिडी का आज स्थान कहां है? क्यों सरकार ने इस ओर आंखें मूंद ली हैं? क्या सिर्फ़ इसलिए क्योंकि यह अनुत्पादक है? एजुकेशन फॉर मासेस या फिर एजूकेशन फॉर क्लासेस-लाख टके का सवाल है यह. सरकार क्या चाहती है. क्यों असमानता की खाई को सरकार इतना गहरा कर देना चाहती है कि एक बार फिर ग़रीब और अमीर के बीच के बीच का संघर्ष आक्रामक हो जाए. क़ीमत आधारित शिक्षा का विरोध इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम शिक्षा के सर्व व्यापीकरण की बात करते हैं को वह क़ीमत आधारित हो ही नहीं सकती.

राज्य के शैक्षणिक विस्तार में सबसे अधिक असंतुलन का एक और पहलू है इसका भौगोलिक पक्ष. महाराष्ट्र में पांच मुख्य शहरों में ही शैक्षणिक संस्थाओं का विकास हुआ है. मुंबई, पुणे और नाशिक को गोल्डन जोन माना जाता है जबकि औरंगाबाद और नागपुर को पेरिफेरल जोन. इसके अलावा पूरा महाराष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में ख़ासकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में सूखा-सूखा है. पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपुर वे शहर हैं जहां प्रति व्यक्ति रहने का ख़र्च काफ़ी अधिक है. यहां मकान का किराया अधिक है. यहां आवागमन के लिए ख़र्च अधिक है. यहां खान-पान का ख़र्च अधिक है. बड़े शहरों में आम आदमी का जीना दूभर है. क़ीमत आधारित शिक्षा का सीधा मतलब अब योग्यता बनाम संपन्नता हो गया है. हमने विकास के नाम पर जितने टापू खड़े किए हैं, आज उनकी क्या स्थिति है. शिक्षा के नाम पर भी शहरीकरण को बढ़ रहा है. गांव विस्थापित हो रहे हैं. कृषि आधारित ग्रामीण व्यवस्था उजड़ रही है. तीसरा अंतर प्रतिभा बनाम अवसरों का है. यहां सवाल यह उठता है कि क्या हमारा अभ्यासक्रम विश्व स्तर पर टिक सकता है. क्या यह रोज़गारमूलक है? क्या यह गुणवत्तापूर्ण है. क्या हम जिस वाइट कॉलर्ड फोर्स का निर्माण कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता व्यापक है? नहीं, उसकी उपयोगिता व्यापक नहीं है. वह अधपका, अधकचरा और अनुपयोगी है.

शिक्षा के व्यापारीकरण में एक और बात दब गई है और वो है सेवाभाव, दान भावना का अभाव. इसे आज एक कमोडिटी के रूप में बेचा जा रहा है. एक उद्योग के रूप में संचालित किया जा रहा है. एक दार्शनिक भाव के बनिस्बत एक विरोधाभासी रूप में अभिव्यक्त किया जा रहा है. आज इस देश की 52 फ़ीसदी जनता 25 वर्ष से कम आयु की है. 72 फ़ीसदी जनता 35 साल से कम उम्र की है. ऐसे में शिक्षा की योजना बनाते समय इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है. इस वर्ग को अगर शिक्षा के माध्यम से तैयार कर लिया जाए तो हम कहीं न कहीं वैश्विक स्पर्धा में टिके रह सकते हैं. इस वर्ग को राष्ट्र को तैयार करने का संकल्प देने होगा. लेकिन शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हम पाते हैं कि गुणवत्ता का अभाव, योग्य वातावरण की अनुपस्थिति, क़ीमत के कारण सीमाएं, बाज़ारवाद के कारण सीमाएं और अब तो आने वाले समय में विदेशी विश्वविद्यालयों के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां समूची शिक्षा प्रणाली और उसके सामाजीकरण को ही क्षतविक्षत कर देंगी.

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र में 1980 के दशक के बाद निजी शिक्षण संस्थाएं अस्तित्व में आईं. 1990 के बाद ये संस्थाएं मज़बूत हुईं और सन 2000 के बाद ये पूरी तरह राज्य में मज़बूत हो गईं. इसके बाद शुरू हो गया शिक्षा के क्षेत्र में सब्सिडी का पूरी तरह ख़ात्मा और गुणवत्तापूर्ण और उच्च शिक्षा से आम आदमी की पूरी तरह दूरी. जिसके पास पैसा है, उसके पास शिक्षा है. जिसके पास पैसा है, उसके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है.

शिक्षा माफ़िया का बढ़ता प्रभाव

महाराष्ट्र में शिक्षा माफिया का प्रभाव इस क़दर बढ़ता जा रहा है कि न क़ानून और न ही सरकार कुछ करने की हालत में है. प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए तो बाहर के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में बाक़ायदा एजेंटों की नियुक्ति की जाती है. इन एजेंटों की कोचिंग क्लासेस के मालिकों से साठगांठ रहती है. कोचिंग क्लासेस के मालिक बाक़ायदा बच्चों को बताते हैं कि फलाने कॉलेज में हमारे पहचान के हैं. वहां चले जाना और जाकर बात कर लेना. छात्र या छात्रा जब इन इंजीनिरिंग कॉलेजों के दफ्तरों में पहुंचते हैं तो पहले तो वहां की चकाचौंध से ही भ्रमित हो जाते हैं. फिर उन्हें धीरे-धीरे डोरे डाल कर क़ब्ज़े में ले लिया जाता है. अब शुरू होती है डोनेशन की बात. डोनेशन में लाखों रुपए टेक्निकल एजूकेशन के कॉलेज के लोग डकार जाते हैं. लेकिन जब कॉलेज में छात्र प्रवेश लेता है तो हक़ीक़त सामने आती है. वहां उसे वे सुविधाएं नहीं मिलती जिनका वादा प्रवेश के पहले ये संस्थाएं करती हैं. कई कॉलेजों में एआईसीटीई और एमसीआई के निर्धारित मापदंड भी पूरे नहीं किए जाते हैं. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मापदंडों की भी शिक्षण संस्थाओं द्वारा धज्जियां उड़ाई जाती हैं.

निजी-शासकीय भागीदारी एकमात्र उपाय

शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त व्यापक असंतुलन को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि इस क्षेत्र में निजी-शासकीय भागीदारी शुरू की जाए. यानी 50-50 फ़ीसदी की भागीदारी. सरकार की भागीदारी 50 फ़ीसदी हो और निजी क्षेत्र की भागीदारी 50 फ़ीसदी हो. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सामाजिककरण होगा. यानी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का सर्वव्यापीकरण होगा. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गड़चिरोली में भी उपलब्ध होगी और गोंदिया में भी. यह नांदुरबार में मिलेगी और जलगांव में भी. पब्लिक फंडिंग से इसमें समाज की हिस्सेदारी बढ़ेगी और निजी भागीदारी से इसकी गुणवत्तापूर्ण बढ़ेगी. सरकार को तत्काल इस दिशा में प्रयास शुरू करना होगा. अन्यथा देश को बेच खाने का पाप जो सरकारें कर रही है, वह उसे जला कर खाक कर देंगी.

सैम और मैम के बीच कुपोषण

परतवाड़ा ज़िले का आदिवासी अंचल मेलघाट हमेशा से कुपोषण के लिए चर्चित रहा है. इस क्षेत्र को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार हर साल करोड़ो रुपये ख़र्च करती है. करोड़ो रुपये का अनुदान, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के बावजूद मेलघाट में पिछले वर्ष 844 बालमृत्यु हुईं. मेलघाट की धारणी और चिखलदरा तहसीलो में बीते दो माह में करीब 67 मासूमों को कुपोषण ने निगल लिया है. इससे सवाल उठना लाजिमी है कि आख़िर हर साल ख़र्च होने वाले करोड़ों रुपये जाते कहां हैं? बारिश का मौसम शुरू होते ही मेलघाट में कुपोषण का हैवान एक बार फिर तांडव करने लगा है. संबंधित वरिष्ठ अधिकारी अपनी खाल बचाने की कोशिश में लग गए हैं. पिछले कुछ वर्षो की तुलना में बालमृत्यु का प्रमाण 5.6 फीसदी कम होने का दावा स्वास्थ्य विभाग कर रहा है. हक़ीक़त यह है कि बालमृत्यु का प्रमाण ज़रूर घटा है बावजूद इसके स्थिति में ख़ास बदलाव नहीं आया है. कुपोषण से बालमृत्यु का आंकड़ा हैरानी में डालने वाला है क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस साल बालमृत्यु की दर में 35 अंक का इज़ाफ़ा हुआ है. इस मौत की सूची में 4 माताओं की मृत्यु भी दर्ज है. बीते एक दशक में कुपोषण को लेकर जितना बवाल खड़ा किया गया, उतनी ही बैठकें, चर्चाएं कुपोषण पर उपाय योजनाओं को लेकर की गई हैं. मेलघाट में स्वास्थ्य विभाग ने हमेशा अपनी पीठ ख़ुद थपथपाने का काम किया है, पर यह उस वक़्त जायज था जब 1993 के बाद कुपोषण से बालमृत्यु में कमी आने लगी थी. मगर बीते दो माह में जिस तरह बच्चे कुपोषण के गाल में समा रहे हैं, उसने स्वास्थ्य विभाग की कलई खोल दी

अधिकारियों का नया फंडा-मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के नाम से विख्यात इस क्षेत्र को कुपोषण के तांडव ने हिन्दुस्तान भर में कुख्यात कर दिया है. विगत बीस वर्ष से मेलघाट और कुपोषण एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं. राज्य में सत्ता किसी की भी रहे, कोई भी मुख्यमंत्री रहे और विपक्षी दल का नेता, सभी का मेलघाट दौरा कर सांत्वना देने का एक अनिवार्य कार्यक्रम बन चुका है. इसी काम में सुधाकरराव नाईक, शरद पवार, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुन्डे, नितिन गडकरी, नारायण राणे, अशोक चव्हाण और वर्तमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण तक सभी मेलघाट का दौरा कर चुके हैं. पूर्व में स्वास्थ्य विभाग ने शून्य से 06 उम्र के कुपोषित बच्चों को विभिन्न श्रेणी में बांट रखा था. इसमें कुपोषण को एक से लेकर चार श्रेणी बनाई गई थी. चौथी श्रेणी का कुपोषित बालक यानी जिसकी बचने की उम्मीद करना भी बेमानी है. अब मुंबई, नागपुर और अमरावती मुख्यालय में बैठे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नया फंडा ईजाद किया ताकि कुपोषण के भूत से पीछा छुड़ाया जा सके. अब कुपोषित बच्चे को ग्रेड सहित कुपोषित दर्शाने की जगह उसे सैम और मैम जैसे भारी भरकम अंग्रेजी शब्दों से परिभाषित किया गया है. इसमे सैम का अर्थ होता है सिव्हियर एक्यूब मालन्यूट्रेशन यानी गंभीर रूप से कुपोषित बालक और मैम अर्थात मॉडरेट एक्यूब मालन्यूट्रेशन जिसका अर्थ होता है कुपोषण की प्राथमिक अवस्था से पीड़ित बालक. स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी अब कुपोषित बच्चों को श्रेणी या ग्रेड की बजाय सैम और मैम में दर्शाने लगे हैं. सैम में उन बालकों को बताया जाता है जो ग्रेड दो से चार के बीच जीवनयापन कर रहे हैं, जबकि ग्रेड एक के बच्चे मैम कहके संबोधित किये जाते हैं. इस प्रकार सैम और मैम की लीपापोती के बीच फलफूल रहा है

देना, स्वास्थ्य शिक्षण व जागृति का अभाव, बंजर भूमि पर फसल का तैयार ना होना, ग़रीबी, बेरोजगारी और अज्ञानता के कारण कुपोषण सदाबहार बन मानवता को यहां चिढ़ाता रहता है. मेलघाट से कुपोषण को ख़त्म करने के लिये सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर तो रही है, पर आदिवासियों के पास पहंचने से पहले ही पैसा बंट जाता है. परिणामस्वरूप रोजगार के रूप में, अनुदान के रूप में, किसी वस्तु के रूप में लोगों को लाभ नहीं मिल पाता. प्रसूति के दौरान बालमृत्यु को रोकने के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्र की ही शिक्षित महिलाओं की दाई पद पर नियुक्ति की गई है जो आदिवासी महिलाओं को प्रसूति संबंधी जानकारी देने सहित उन्हें अस्पताल आने को प्रेरित करने का कार्य भी करती हैं. फ़िलहाल मेलघाट में 588 दाई कार्यरत होने की जानकारी है. स्वास्थ्य पर प्रशासन चौकन्ना यहां कुपोषण को बढ़ने से रोकने के लिये बारिश से पूर्व दो चरणों में सर्वेक्षण कराने की बात स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे हैं. उपचार तथा टीकाकरण अभियान के साथ ही विशेष अभियान के लिये प्रतिनियुक्ति किए जाने का दावा किया जा रहा है. संबंधित डॉक्टरों को मेलघाट में मुकाम कर काम को अंजाम देने के निर्देश दिए गए हैं. बारिश के दिनों में बालमृत्यु में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज होती है, इस स्थिति से निपटने के लिए ज़िला परिषद ने विशेष इंतज़ाम किए हैं. यहां स्वास्थ्य सेवा देने के लिये नियुक्त किए प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारियों में ज़िला मलेरिया अधिकारी डॉ. तरोडेकर को बिजूधावडी, हरिसाल, डॉ. आसोले को टेंब्रुसोंडा, अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बोबडे को साद्राबाडी, धुलघाट, डॉ. निकोसे को सलोना और सेमाडोह, डॉ. केचे को काटकुंभ और हतरू और सहायक संचालक डॉ. पाटिल को कलमखार, बैरागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर अभियान तक ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. मेलघाट के मामलों में ज़िला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओमप्रकाश बफोरिया स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं. विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाने हेतु 40 दल तैयार करने का दावा स्वास्थ्य महकमा कर रहा है. [illegible]

कम उम्र में लड़की का विवाह, गर्भावस्था में भारी काम करना और कम आहार लेना, नवजात शिशु को प्रसूति के तुरंत बाद दूध नहीं पिलाना, बच्चे को क्षयरोग (टी.बी.) होना आदि, ये सभी कुपोषण को बढ़ाते हैं. बीमारी का तुरंत इलाज नहीं करना और अस्पताल नहीं जाना भी कुपोषण वृद्धि का कारण बताया जाता है.

[illegible]

संजय जोशी
feedback@chauthiduniya.com

सभी के हाथ दलित कार्ड

राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का दौर

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

राजेश नामदेव

महाराष्ट्र के राजनीतिक दल भविष्य में होने वाले राजनैतिक दंगल के लिए अभी से ताल ठोंक रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है. कोई पानी परिषद कर रहा है, तो कोई सामाजिक परिवर्तन अधिकार परिषद, कोई अपने गठबंधन की ताक़त को महारैली बता रहा है. सभी मानो कह रहे हों- आ..देखें ज़रा किसमें कितना है दम. बहरहाल इनकी ज़ोर-आजमाइश के लिए थोड़ा वक़्त है, जब महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बजेगा. मगर जिस तरह की आक्रामकता सभी दल के नेता एक-दूसरे के प्रति दिखा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है, मानो राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हों. विशेष बात यह है कि इस राजनीतिक द्वंद्व या बिसात का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा है दलित-पिछड़ा वर्ग. सभी को एकाएक दलित समाज की दयनीय स्थिति की याद सताने लगी है. सभी दलित उत्थान के कशीदे पढ़ना शुरू कर दिया है. इसके लिए कोई रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा कर रहा है, कोई दलितों वर्ग के हितों के संबंध में मांग पत्र पेश कर रहा है. एक गठबंधन तो दलितों का भाग्य बदलने तक का दावा कर रहा है. साथ ही एक-दूसरे दल के नेताओं को कोसने और गरियाने (गाली बकने) में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं. दलितों को राज्य की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाने का श्रेय जाता है रिपब्लिकन नेता रामदास आठवले को. जबसे रामदास आठवले ने शिवसेना-भाजपा के साथ मिलकर भीमशक्ति-शिवशक्ति के राजनैतिक समीकरण को ईजाद किया है, तब से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं को दलितों की चिन्ता सताने लगी है. इसी के साथ की राजनैतिक शक्ति प्रदर्शन की व्यूह रचना सभी दलों में शुरू हो गई थी. राज्य मे शक्ति प्रदर्शन का शुभारंभ किया कांग्रेस ने 26 मई को यवतमाल में पानी परिषद का आयोजन करके. इस परिषद में पानी पर विचार मंथन कम और राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में चल रही तनातनी का अधिक प्रदर्शन हुआ. ख़ासकर कांग्रेस नेताओं ने पानी को हथियार बनाकर केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को निशाना बनाया था. उसके बाद ही अचानक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने 30 मई को दलितों-आदिवासियों के हितों की 60 सूत्रीय मांग पत्र की घोषणा कर यह ज़ाहिर करने का प्रयास किया कि उनकी पार्टी ही दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की हमदर्द है. राज्य की राजनीति के व्याकरण को बदलने के लिए गठित शिवसेना-रिपब्लिकन-भाजपा गठबंधन ने 9 मई को मुंबई के आज़ाद मैदान में महारैली कर शिवशक्ति-भीमशक्ति का प्रदर्शन किया. आजाद मैदान में जय शिवाजी-जय भवानी के नारों के बीच उद्धव ठाकरे, रामदास आठवले, एकनाथ खड़से, विनोद तायड़े ने मिलकर कांग्रेस-राकांपा को जमकर कोसा और देश की सभी समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार ठहराया. उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस-राकांपा ग़रीबों, दलितों का शोषण करने में सबसे आगे है, यह बात अब दलित वर्ग अच्छी तरह समझ गया है. अब बारिश की बूंदों के साथ ही भगवा और भीमशक्ति के दिलों का मैल पूरी तरह धुल गया है. आघाड़ी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह महायुति चंद दिनों के लिए नहीं, बल्कि उम्र भर के लिए बनी है. उद्धव ने बालासाहब ठाकरे पर तीखी टिप्पणी करने वाले उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए खिल्ली उड़ाई. वहीं रामदास आठवले ने आरोप लगाया कि कांग्रेस-राकांपा ने अब तक दलितों का उपयोग सत्ता हासिल करने के लिए किया है. ग़रीबों और दलितों को न्याय दिलाने के लिए आरपीआई ने शिवसेना और भाजपा के साथ गठबंधन किया है. हमारा यह गठबंधन महायुति है और यह सिर्फ़ महाराष्ट्र तक ही सीमित न रहकर पूरे देश में एक नई ताक़त के रूप में उभरेगा. शिवसेना-रिपाई के नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए भाजपा नेता एकनाथ खड़से ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार ने दलितों के कल्याण में ख़र्च किया जाने वाला पैसा दूसरी अन्य योजनाओं में ख़र्च कर दिया. भाजपा-शिवसेना की सरकार ने दलितों के उद्धार व आर्थिक-सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए जो योजनाएं बनाई थीं, उनको इस सरकार ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया. दलितों को बरगलाकर अपने फ़ायदे के लिए उपयोग किया पर बदले में दिया कुछ नहीं. भाजपा के ही विनोद तायड़े ने इसी कांग्रेस ने भंडारा से डॉ. बाबासाहब आंबेडकर को लोकसभा चुनाव में हरवाया था, परंतु जनसंघ ने बाबासाहब को बंगाल से सीट खाली कराकर लोकसभा भेजा था. उसी तरह कांग्रेस ने रामदास आठवले को शिर्डी से हरवाया और हम लोग उन्हें राज्यसभा भेजेंगे. सबसे रोचक बात यह रही कि मुंबई में लगाये गए पोस्टरों, बैनर, होर्डिंग में शिवशक्ति-भीमशक्ति गठबंधन को एटीएम नाम दिया गया. इन होर्डिंगों में आठवले, ठाकरे और मुंडे की तस्वीरें थीं, यानी ए से आठवले, टी से ठाकरे ऑर एम से मुंडे हुआ. मगर इस महायुति की महारैली से गोपीनाथ मुंडे नदारद थे. उनकी अनुपस्थिति के राजनीतिक निहितार्थ अब निकाले जा रहे हैं क्योंकि मुंडे ने ही इस महायुति को साकार करने में अहम भूमिका निभाई थी. इसी के साथ राज्य में भाजपा में व्याप्त गुटबाजी की पुनः चर्चा शुरू हो गई है. बालासाहब ठाकरे ने भी रैली में मुंडे के न आने पर नाख़ुशी ज़ाहिर की है. इसके अलावा इस रैली से अजीत पवार और बालासाहब ठाकरे के बीच विवाद को लेकर शरद पवार द्वारा किया गया समझौता टूट गया. उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार के ख़िलाफ़ रैली में फिर से मोर्चा खोल दिया है, जिसका जवाब काका-भतीजे ने 10 जून को राकांपा के स्थापना दिवस पर आयोजित रैली में दिया. राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर मुंबई के सायन क्षेत्र में स्थित सोमैया ग्राउंड में सामाजिक परिवर्तन अधिकार परिषद का आयोजन कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया. ज़ाहिर तौर पर सामाजिक परिवर्तन अधिकार परिषद का संयोजक जलापूर्ति राज्यमंत्री लक्ष्मण ढोबले को बताया गया क्योंकि वे दलित हैं, पर इस की पूरी योजना परदे के पीछे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने ही सारा तामझाम खड़ा किया. ढोबले का दलित समाज में कोई विशेष प्रभाव नहीं है. परिषद के सभी मुख्य वक्ताओं के भाषण में रामदास आठवले ही छाये रहे. राकांपा सुप्रीमो ने कहा कि रामदास आठवले ने बाबासाहब की शिक्षाओं को भुला दिया है. उन्होंने बताया कि बाबासाहब ने बौद्ध दीक्षा लेने के बाद 22 प्रतिज्ञाएं ली थी और किसी हिंदू देवी-देवता की पूजा न करने को कहा था. लेकिन आठवले तो हिन्दुत्व के विचार पर चलने वालों व खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताने वाले व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं तो क्या आठवले बाबासाहब की शिक्षा को भूल गए हैं. उपमुख्यमंत्री अजीज पवार ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग राकांपा को जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं. ऐसे लोगों को जैसे का तैसा जवाब दिया जाएगा. हम किसी के मुंह नहीं लगते पर जो हमारे मुंह लगता है उसे सबक भी सिखाते हैं.. ग़रीब, दलित व पिछड़ों लोगों के विकास में किसी तरह की धन की कमी नहीं आने दी जाएगी. हम सभी को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं. इतने भारी-भरकम इंतजाम की अपेक्षा परिषद फीकी ही रही. इन शक्ति प्रदर्शनों से जो बात उभर कर सामने आई, उसका सार यह है कि रामदास आठवले के भाजपा-शिवसेना के साथ जाने से कांग्रेस-राकांपा को अपने वोट बैंक में कमी आने का भय सता रहा है. कांग्रेस अपने इस वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद कर रही है तो राकांपा आठवले के जाने के बाद पार्टी को रहे नुक़सान की भरपाई लिए दलित कार्ड खेल रही है. दूसरी ओर शिवसेना-भाजपा दलितों के वोट मिलने की संभावनाओं से गदगद है. परन्तु इसके लिए ज़रूरी होगा विधानसभा व लोकसभा चुनाव तक टिके रहना जिस पर अभी से शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं. वजह यह है कि इस गठबंधन की मज़बूती का पता चुनाव के समय सीटों के बंटवारे पर चलेगा. भाजपा-शिवसेना रिपाई के लिए कितनी सीट छोड़ती हैं, जिससे आठवले संतुष्ट होते हैं कि नहीं. यह भी साफ़ हो गया कि अजीत पवार और शिवसेना नेता के बीच तकरार जारी रहेगी.

इस राजनीतिक द्वंद्व या बिसात का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा है दलित-पिछड़ा वर्ग. सभी को एकाएक दलित समाज की दयनीय स्थिति की याद सताने लगी है. सभी दलित उत्थान के कशीदे पढ़ना शुरु कर दिया है. इसके लिए कोई रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा कर रहा है, कोई दलितों वर्ग के हितों के संबंध में मांग पत्र पेश कर रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

अब तो कुछ कीजिए ना

राज्य में आतंकी हमला हो या किसी व्यक्ति या पत्रकार की हत्या हो, हमेशा सरकार यही कहती है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. गुनहगारों को पकड़ने का पुलिस प्रयास कर रही है. जांच चल रही है और सरकार सुरक्षा के पुख्ता उपाय कर रही है. जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, मालेगांव विस्फोट हुआ, दंगा हुआ, जर्मन बेकरी पर आतंकी हमला हुआ, नागपुर में पत्रकारों पर हमला हुआ, अपर कलेक्टर यशवंत सोनवने को तेल माफिया ने दिनदहाड़े ज़िंदा जलाया तब भी और आज जब वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय (जॉय) डे की ऑफिस से घर जाते समय हत्या कर दी गई, तब भी महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद की शोभा आप ही तो बढ़ा रहे हैं. पर बाबा आपके गृहमंत्रित्व में यह हो क्या रहा है.... जब भी कोई घटना घटित होती है तभी आपका घिसा-पिटा बयान आ जाता है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है. राज्य सरकार पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीरता से विचार कर रही है. सरकार इस संबंध में जल्द निर्णय लेगी. लेकिन कुछ समय बाद ही सब कुछ भुला दिया जाता है. आप जैसे धीर-गंभीर मंत्री से ऐसी अपेक्षा न थी कि हर बार गंभीर विचार करने का कोरा आश्वासन देकर समस्या को लटका दिया. पत्रकार बेचारे बार-बार अपनी जान की गुहार लेकर मुख्यमंत्री और आप के दरबार में हाजिर होते हैं और आप कभी समिति गठित करने की बात करते हैं, कभी विचार में डूबने का दिखावा. अब जे. डे. हत्या के बाद पुनः मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई. मीटिंग में गृहमंत्री होने के नाते आपने भी शिरकत की. मीटिंग ख़त्म हुई और फिर वही जुमला सुनाई दिया कि हमारी सरकार पत्रकारों को सुरक्षा देने पर गंभीरता से विचार कर रही है. इस संबंध में जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का फरमान दिया है. यह मीटिंग-आदेश-निर्देश का दिखावा आख़िर कब तक चलता रहेगा. बाबा अब तो जाग जाइए. राज्य में अपराधी बढ़ रहे हैं. अपराध बढ़ रहे हैं. ऐसे में राज्य की क़ानून-व्यवस्था का क्या होगा? अब जो बातें जे. डे. हत्या में झनकर आ रही हैं उससे पत्रकारों की चिन्ता और बढ़ जाती है. चर्चा है कि डे की हत्या में तेल माफिया की भूमिका है. यह भी कहा जा रहा है कि अपर कलेक्टर सोनवाने हत्याकांड मामले में जिन लोगों की धरपकड़ की गई वे तो छोटी मछलियां थीं. बड़े मगरमच्छों की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया गया. पुलिस की पर भी संदेह जताया जा रहा है. मुंबई की पत्रकार बिरादरी कहा जा रहा है कि डे पुलिस व माफिया के गठजोड़ को उजागर करने की तैयारी कर रहे थे. इसलिए माफिया के लोगों ने उनकी हत्या कर दी. इस स्थिति में पुलिस को संदेह से परे कैसे किया जा सकता है. यह स्थिति राज्य के लिए ठीक नहीं है. लोग तो यहां तक कहते हैं कि बाबा का अपने महकमे पर दबदबा ही नहीं है. सो पुलिस भी एक कान से सुनकर, दूसरे कान से निकाल देती है. बाबा आप की गृहमंत्री की छवि इन सब मामलों से धूमिल हो रही है. संभालिए अपने महकमे को. चुस्त-दुरुस्त करिए और अपनी जान हथेली पर रखकर दिन-रात काम करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर विचार नहीं, बल्कि गंभीर, समाधानकारक ठोस एक्शन लीजिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नो-किया केयर

अब ग्राहक लामबंद

असंगठित होने के कारण भारतीय ग्राहकों की आर्थिक लूट और मानसिक छल करने वाली मोबाइल कंपनियों के काले कारनामों पर अंकुश लगेगा. क्योंकि इन कंपनियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हक़ में लड़ाई लड़ने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स सोसायटी ऑफ इंडिया (पीसीआरएसआई) का गठन हाल ही में नागपुर में किया गया है. मोबाइल फोन ग्राहकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले इस संगठन ने सर्वप्रथम बहुराष्ट्रीय मोबाइल कंपनी के ख़िलाफ़ राष्ट्रव्यापी लड़ाई छेड़ने का फ़ैसला किया है. पूरे भारत में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. इस तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए अनेक देशी व विदेशी कंपनियां मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में उतर आई हैं. परंतु इसका लाभ उठाकर कई कंपनियां डिफेक्टिव माल ग्राहकों के माथे मढ़ देती हैं. उसके बाद जब ग्राहक को मोबाइल की ख़राबी पता चलती है और वह इसकी शिकायत लेकर कंपनी की एजेन्सी या कंपनी के केयर सेंटर पर जाता है तो सेवा देने में टालमटोल की जाती है और ग्राहक को परेशान किया जाता है. ऐसे में मोबाइल ग्राहक की शिकायतों की सुनवाई कहीं होती नहीं है. यह तथ्य पीसीआरएसआई के ध्यान में आ गया है. प्रचलित ग्राहक अधिकार संरक्षण क़ानून के तहत न्याय मिलने में बहुत समय लगता है जिसके कारण आम ग्राहक नुक़सान होने के बाद भी चुपचाप बैठ जाता है. इसका फ़ायदा कंपनी उठाती हैं. इस बात को ध्यान रखते हुए पीसीआरएसआई सोसायटी ने ग्राहकों के हब में लड़ने का संकल्प लिया है. पीसीआरएसआई में नागपुर सहित पूरे विदर्भ से चिकित्सकीय, सामाजिक, पत्रकारिता व सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यरत लोग शामिल हैं. सोसायटी ने जब नोकिया मोबाइल कंपनी के विषय में इंटरनेट की सूचनाओं को खंगाला तो पता चला कि इस कंपनी के ख़िलाफ़ बड़ी मात्रा में शिकायतें की गई हैं, जिन के आधार पर कंपनी पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया गया है. इस लिए सोसायटी ने सबसे पहले बहुराष्ट्रीय मोबाइल कंपनी नोकिया के ख़िलाफ़ संघर्ष करने का निर्णय लिया है. नोकिया मोबाइल कंपनी अपने उत्पादनों के माध्यम से ग्राहकों को कितना और किस तरह लूटती है, इसका अनुभव अनेक ग्राहकों को हुआ है. नोकिया कंपनी ने मार्च 2011 के अंतिम सप्ताह में ई-7 मोबाइल बिजनेस हैंडसेट बाज़ार में लांच किया था जिसकी क़ीमत 35,019 रुपये रखी गई थी. कुछ ही दिनों बाद इस हैंडसेट की क़ीमत तेज़ी से कम हुई और बेस्ट बाय प्राइज़ 29,999 रुपये कंपनी ने कर दी. इतना होने के बाद भी मोबाइल की पैंकिंग पर क़ीमत 35,019 रुपये ही रखी, जबकि उसी समय ई-7 हैंडसेट बाज़ार में 28 से 29 हज़ार रुपये में उपलब्ध था. उसके एक माह के बाद ही नोकिया की वेबसाइट पर ई-7 हैडसेट की क़ीमत 26,999 रुपये दिखाई जाने लगी. इसी दरम्यान नागपुर के बाज़ारों में यह मोबाइल हैडसेट 25 से 26 हज़ार रुपये में बिक रहा था. इसके बाद भी पैकिंग पर एमआरपी 35,019 रुपये ही रखी गई. इस तरह नोकिया ने ग्राहकों से करोड़ों रुपये लूट लिये. ग्राहकों को लूटी गई यह रकम कंपनी लिखित शिकायत कर वापस मांगने का आह्वान सोसायटी ने किया है. इस संबंध में लिखित ऑनलाइन शिकायत कस्टमरकेयर/नोकियाडॉटकाम और पीसीआरएसआई /जीमेलडॉटकॉम ई-मेल पर भेजी जा सकती है. नोकिया केयर सेंटर जाने का बुरा अनुभव हाल ही में संगठन के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया सलाहकार भास्कर लोंढे को हुआ है. लोंढे ने नोकिया ई-7 हैंडसेट कुछ ही दिनों पहले ख़रीदा था. ख़रीदने के दो दिन बाद ही हैंडसेट में आई ख़राबी को दुरुस्त करने के लिए नोकिया कयर सेंटर (मिलाफ इलेक्ट्रोनिक्स, झांसी रानी चौक, सीताबर्डी, नागपुर) गए. केयर सेंटर में कहा गया कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने पर ठीक हो जाएगा. कोई भी पार्ट बदलना नहीं पड़ेगा. इसके बावजूद केयर सेंटर में हैंडसेट का पार्ट बदल कर वापस देने का प्रयास किया गया. इस बात का ध्यान आते ही लोंढे ने हैंडसेट बदलकर देने की मांग की, उन्होंने दुरुस्त किया हैंडसेट लेने से इंकार कर दिया. इस पर नोकिया सेंटर के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि नया हैंडसेट बदल कर नहीं दिया जाएगा. इस की शिकायत नोकिया इंडिया के उपाध्यक्ष और व्यवस्थापकीय संचालक डी. शिवकुमार से दिल्ली तथा विदर्भ के सभी अधिकारियों को ई-मेल कर की. इसके अलावा ही इस पूरे प्रकरण की जानकारी दिल्ली, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के 200 से अधिक पत्रकारों व प्रतिष्ठित लोंगों को दी. जिसके चलते लोगों ने इस प्रकरण पर दखल लेते हुए नोकिया का बहिष्कार करने की मुहिम शुरू की है. इंटरनेट के माध्यम से कंपनी की हो रही बदनामी को गंभीरता से लेते हुए नोकिया कंपनी के मराठवाड़ा और विदर्भ के सर्विस मैनेजर अमित भालेराव ने तत्काल हैंडसेट बदलने और मानसिक रूप से हुई क्षति की भरपाई तैयारी दिखाई. उसके बाद मोबाइल हैंडसेट बदल कर दिया. इसके बाद अमित भालेराव के साथ ही नोकिया कार्यालय के लीगल सेल के अनिस राजपाल ने लोंढे को बार-बार फोन कर क्षतिपूर्ति करने के लिए और वक़्त मांगते गए. अंत में नोकिया कंपनी के अधिकारियों ने अपना असली रूप दिखा दिया और कहा कि ग्राहक न्यायालय के अध्यक्ष से हमारे घनिष्ठ संबंध हैं. नोकिया के विरुद्ध अनेक ग्राहकों ने न्यायालय में शिकायत की है तुम्हारी भी शिकायत से हमें कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है. होगा तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा हज़ार-दो हज़ार देने का दंड होगा. साथ ही लोंढे को किसी भी न्यायालय में जाने की सलाह दी. नोकिया के ई-7 हैंडसेट और अन्य टचस्क्रीन मोबाइल पर हिंदी भाषा के फांट नहीं पढ़े जा सकते हैं. शब्द एक-दूसरे से चिपके रहते हैं. इस बात की शिकायत भी लोंढे ने कंपनी के अधिकारी अमित भालेराव सहित प्रशांत फाटे, राहुल वर्मा व अन्य से की थी पर इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई. विदेशी कंपनी होने के कारण नोकिया कंपनी का राष्ट्रभाषा से कोई लेना-देना नहीं है. नोकिया के कई मोबाइल हैंडसेटों में हिंदी के फांट उपलब्ध नहीं हैं. इंटरनेट के माध्यम से खोजबीन करने पर नोकिया कंपनी के विरुद्ध इस तरह की हज़ारों शिकायत होने की जानकारी मिली है जिन पर कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की है. अब ग्राहकों को न्याय दिलाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा ग्राहकों लूटने और छल करने के ख़िलाफ़ संबंधित विभाग और इसी तरह सोशल नेटवर्किंग व अन्य प्रसार माध्यमों के सहयोग से राष्ट्रव्यापी लड़ाई लड़ी जाएगी.

सोसायटी ने जब नोकिया मोबाइल कंपनी के विषय में इंटरनेट की सूचनाओं को खंगाला तो पता चला कि इस कंपनी के ख़िलाफ़ बड़ी मात्रा में शिकायतें की गई हैं, जिन के आधार पर कंपनी पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

आईएनआईएफडी के डिजायनर्स शो की पूर्व संस्था पर डायरेक्टर सर्वेश अग्रवाल के साथ मॉडल्स.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में परेड करते हुए स्वयंसेवक और मंचासीन शंकराचार्य

अजब बंगला म्युजियम में अस्त्र-शस्त्रों का निरीक्षण करते हुए राज्य के सांस्कृतिक मंत्री संजय देवतले.

बचत भवन में आयोजित मिहान की बैठक को संबोधित करते हुए नागपुर के जिलाधिकारी सौरभ राव.

बारिश में कड़कड़ाती बिजली और पानी से सराबोर नागपुर के वेरायटी चौक का विहंगम दृश्य.

राज्य के उद्योग मंत्री नारायण राणे उद्योग विभाग द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए.

मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशें लागू करने की मांग करते हुए नागपुर श्रमिक पत्रकार संघ के पदाधिकारी व सदस्य.

चौथी दुनिया — हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार

महाराष्ट्र
आशिर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स धंतोली रेलवे पुल के पास, ग्रेट नाग रोड नागपुर- ४४०००३
फोन नं. - ०७१२- २७०७४१४/१५
Email:- chauthiduniya@gmail.com

राष्ट्रीय साप्ताहिक १६ पृष्ठों के साथ महाराष्ट्र के रंगीन ४ पृष्ठ

आज ही अपना अंक सुरक्षित करवाएं

हॉकर और बुक स्टॉल धारकों के लिए उपलब्ध

मुंबई	: दातार एंड सन्स, मुंबई	– 022–2203427
नागपुर	: पाठक ब्रदर्स, नागपुर	– 0712 2420293
नागपुर	: दांगट न्यूज पेपर, रामदासपेठ, नागपुर	
जलगांव	: पाठक ब्रदर्स, जलगांव	– 0257–2225806
नासिक	: पाठक ब्रदर्स, नासिक	– 0253–2506898
पुणे	: दांगट न्यूज पेपर, पुणे	– 9922419042
औरंगाबाद	: संदीप सुखधान	– 9762478014
अकोला	: कृष्णा मार्केटिंग, अकोला	– 9011325700
चंद्रपूर–गडचिरोली	: रतन न्यूज पेपर एजन्सी	– 07172–258554

चौथी दुनिया महाराष्ट्र
आवश्यकता
विज्ञापन व्यवस्थापक (पांच साल का अनुभव)
विज्ञापन प्रतिनिधि (कम से कम तीन साल का अनुभव)
प्रसार व्यवस्थापक (कम से कम तीन साल का अनुभव)
जिला प्रतिनिधि (महाराष्ट्र के हर जिले में– मानधन + कमीशन बेस पर)
वितरण एजेंट (महाराष्ट्र के हर जिले में)
संपर्क
आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स, धंतोली रेलवे पुल के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर- ४४०००३फोन नं. - ०७१२- २७०७४१४/१५
Email :- chauthiduniya@gmail.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

अभिभावक अब शैक्षणिक संस्थाओं की मनमानी शुल्क (फीस) बढ़ोत्तरी को लेकर सजग हो गए हैं और सवाल-जवाब भी करने लगे हैं.

फीस पर अंकुश आसान नहीं

स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोत्तरी से ग़रीब, मध्यम, अफसर-व्यवसायी सभी परेशान हैं. परन्तु सबसे अधिक मार पड़ती है ग़रीबों पर, क्योंकि वे जैसे-तैसे पैसों की व्यवस्था करके अपने बच्चों को अच्छे शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश दिलाते हैं, जब फीस के अलावा सत्र के बीच में तरह-तरह की गतिविधियों के लिए बार-बार पैसों की मांग स्कूलों द्वारा की जाती है तो उसे अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना टूटता-सा लगता है. अब राज्य सरकार शिक्षा संस्थाओं की मनमानी की शिकायतों के प्रति थोड़ा गंभीर हुई है.

अंजीव पांडेय

महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियम अधिनियम का मामला विधानसभा में अटका पड़ा है. पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने आश्वासन दिया था कि यह विधेयक इसी सत्र में पारित कर दिया जाएगा. लेकिन माफियाओं के दबाव की तरह अन्य विधेयकों की तरह यह विधेयक भी पारित हो न सका. इसका हश्र भी वही हुआ जो तेल माफियाओं, ज़मीन माफियाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुआ. आख़िर हो भी क्यों न. राजनेताओं ने अपनी तीन पीढ़ियों की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी जो कायम बिना अनुदानित शिक्षा की इस अंधी गली से सुनिश्चित कर ली है. पालक चिल्लाते हैं तो चिल्लाते रहें. समाज असमानता की गहरी खाई में गिरता हो तो गिरता जाए, किसी को क्या फ़िक्र. इन शिक्षा माफियाओं की तो पांचों उंगली घी में और सिर कड़ाही में है. वर्तमान में शैक्षणिक संस्थाएं सरस्वती या ज्ञान का मंदिर बनने की बजाय व्यावसायिक संस्थान बनकर रह गई हैं. आज स्कूलों में ही स्कूली पोशाक (ड्रेस), किताबों, बस्ता (स्कूली बैग) का शिक्षा के साथ खुलेआम व्यवसाय किया जाता है. सभी वस्तुओं की खुले बाज़ार की अपेक्षा अधिक कीमत वसूल की जाती है. ऊपर से भारी-भरकम फीस के लिए अभिभावकों को मोटी रकम चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि शिक्षा बिना उनके बेटे-बेटियों का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा. बच्चों को लगने वाले यूनीफॉर्म, किताब-कापियों की मनमानी मांगों की मनमानी क़ीमतों की वसूली पर जब कोई अभिभावक आपत्ति दर्ज कराता है तो उसे टका-सा जवाब मिलता है कि तुम्हें यहां अपने बच्चे को एडमीशन (प्रवेश) के लिए हमने कहा था क्या? बच्चे के कपड़ों-किताबों का पैसा नहीं चुका सकते तो पढ़ाते क्यों हो? इन सवालिया व्यंग्यों को सुन अपने बच्चे की भविष्य को लेकर परेशान अभिभावक चुपचाप अपनी जेब क्षमता से अधिक खाली कर देता है. स्कलों की मनमानी फीस बढ़ोत्तरी से ग़रीब, मध्यम, अफसर-व्यवसायी सभी परेशान हैं. परन्तु सबसे अधिक मार पड़ती है ग़रीबों पर, क्योंकि वे जैसे-तैसे पैसों की व्यवस्था करके अपने बच्चों को अच्छे शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश दिलाता है.

जब फीस के अलावा सत्र के बीच में तरह-तरह की गतिविधियों के लिए बार-बार पैसों की मांग स्कूलों द्वारा की जाती है तो उसे अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना टूटता-सा लगता है. अब राज्य सरकार शिक्षा संस्थाओं की मनमानी की शिकायतों के प्रति थोड़ा गंभीर हुई है. राज्य सरकार निजी शैक्षणिक संस्थाओं की मनमानी फीस बढ़ोत्तरी पर अंकुश लगाने के लिए फीस नियंत्रण क़ानून बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. मगर इस क़ानून के प्रस्तावित प्रारूप को लेकर कई प्रश्नचिन्ह भी लगाए जा रहे हैं. साथ ही कहा जा रहा है कि शुल्क नियंत्रण क़ानून कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाते ही निजी बिना अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं की मनमानियों व समस्याओं का समाधान हो जाएगा. इससे अधिक अपेक्षा रखना अव्यवहारिक होगा. इसके बावजूद यदि सरकार व प्रशासन ने राज्य के कुछ शिक्षा सम्राटों को मुंह न देखते हुए निष्पक्ष हो कर फीस नियंत्रण क़ानून के तहत मुनाफ़ा कमाने वाली शैक्षणिक संस्थानों पर भी कार्रवाई की तो इस क़ानून के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ेगा. पालकगण अब शैक्षणिक संस्थाओं की मनमानी शुल्क (फीस) बढ़ोत्तरी को लेकर सजग हो गए हैं और सवाल-जवाब भी करने लगे हैं. कई जगह तो स्कूलों की मनमानियों से तंग आकर पालकों ने आंदोलन भी किया है. यानी फीस वृद्धि का मामला अब सिर्फ़ स्कूलों का ही नहीं रह गया है. यह संस्था संचालकों और पालकों के बीच विवाद का मुद्दा बनने के साथ-साथ एक सामाजिक विवाद भी बन गया है क्योंकि शिक्षा सामाजिक प्रगति का मुख्य कारक है. एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनके बच्चे की स्कूल की फीस 40 हज़ार से बढ़ाकर एकाएक 75 हज़ार कर दी गई है. मगर क्या करूं बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाना हमारी मजबूरी बन गई है. अब सरकार फीस नियंत्रण के लिए जो क़ानून ला रही है वह भी कब लागू होगा, उस पर कब क्रियान्वयन होगा भी की नहीं, कहना मुश्किल है. उनका कहना है कि राज्य में अधिकांश शिक्षा संस्थाएं नेताओं और उनके समर्थकों की हैं जिससे शिकायतें होने के बाद भी हमारा शिक्षा महकमा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में असमर्थ हैं.

निजी कायम बिना अनुदानित स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों के ख़िलाफ़ शिक्षण शुल्क को लेकर यूं तो कोई शिकायत नहीं करता है. अधिकतर लोगों ने क़ीमत आधारित शिक्षा को स्वीकार कर लिया है, पर विवाद उठता है साल-दर-साल हज़ारों के निरंतर बढ़ते आंकड़ों के साथ विकास निधि, एक्टीविटी फीस, ड्रेस कोड के नाम पर वसूली जाने वाली मोटी रकम को लेकर. मुंबई के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में मात्र ड्रेस कोड के नाम पर 25 से 30 हज़ार रुपये तक वसूल किए जाते हैं. गैदरिंग के नाम पर साल के मध्य में अलग से छात्र-छात्राओं को पैसे लाने को कहा जाता है. प्राथमिक स्कूलों या कॉन्वेन्टों में एक ही दुकान से पुस्तकें, ड्रेस, जूते-मोजे खरीदने के लिए छात्र-छात्राओं के पालकों को सख्त हिदायत दी जाती है. कुछ स्कूलों में तो स्कूल के अंदर ही एडमिशन सत्र के दौरान बाक़ायदा दुकान लगाई जाती हैं और पुस्तकें, ड्रेस, जूते-मोजे, बेल्ट बेचे जाते हैं. यहां से न ख़रीदने पर प्रवेश रद्द करने की धमकी दी जाती है. इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर फीस नियंत्रण क़ानून बनाया जा रहा है. मगर इस क़ानून को बनाने और लागू करने पर सरकार की मंशा पर अभी से सवाल उठने लगे हैं. प्रस्तावित नये फीस नियंत्रण क़ानून को लेकर जहां पालक मुखर हैं और खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, वहीं शैक्षणिक संस्थानों के संचालक, प्राचार्य इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं. उनका कहना है कि क़ानून जब अभी बना नहीं है तो उस पर हम कैसे कोई टीका-टिप्पणी कर सकते हैं. जब आएगा तब देखा जाएगा. नागपुर के प्रियदर्शनी कॉलेज के प्रा. ए. मुले का स्पष्ट मत है कि माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा सभी तरह की शिक्षा पर सब का अधिकार है. इसलिए सभी की पहुंच में शिक्षा का हो ना आवश्यक है. निजी स्कूलों, कनिष्ठ महाविद्यालयों, महाविदृयालयों में शुल्क निर्धारण की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए. बिना किसी कारण के बेतहाशा फीस वृद्धि हज़ारों छात्रों को समय से पहले पढ़ाई छोड़ने को मजबूर कर देती है. ख़ासकर ग़रीब, आदिवासी फीस की रकम सुनकर ही आगे की पढ़ाई करने का विचार छोड़ देते हैं. मुंबई के स्प्रिंगलडेल पालक संघ के सहसचिव रणजीत जाधव का फीस नियंत्रण क़ानून पर कहना है कि हमारी मांग की महाराष्ट्र सरकार तमिलनाडु पैटर्न पर शैक्षणिक संस्थानों की फीस निर्धारित करने की प्रक्रिया को राज्य में भी अपनाये. इसके अलावा फीस वृद्धि निश्चित करने की प्रक्रिया में पालक संघ को भी सहभागी बनाया जाए. नए क़ानून की चर्चा ख़ूब हो रही है पर इसमें कई खामियां हैं जिन पर अभिभावकों व पालक संघों की आपत्तियों पर भी ग़ौर किया जाए. इसके लिए 24 मई को शिक्षा मंत्रालय में पालकों की मीटिंग बुलाई गई पर पता नहीं किस वजह से रद्द कर दी गई. इससे सरकार की नीयत पर संदेह होता है. क्रिसेंट स्कूल के पालक संघ के अध्यक्ष नितिन दीक्षित का कहना है कि नए फीस नियंत्रण कानून में पालकों व छात्र-छात्राओं के हितों की अपेक्षा स्कूल संचालकों के हितों का ध्यान अधिक रखा गया है. शिक्षा क्षेत्र में राजनीतिक स्तर पर होने वाले लेन-देन के मद्देनजर शिक्षा माफिया पर नियंत्रण करना सरकार के हाथ के बाहर है. शैक्षणिक संस्थान फीस लेंगे, उनको अपनी निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध फीस बढ़ाने का अधिकार रहेगा ही, अब इस पर किसका नियंत्रण रहेगा यह निश्चित हुए बिना आज की परिस्थिति में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है. जहां मुंबई उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थाओं की मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने का आदेश दिया है, वहीं इस क़ानून में मुनाफे की कोई व्याख्या ही नहीं की गई है. ऐसी स्थिति में स्कूलों की मुनाफाखोरी जारी रहने की ही अधिक संभावना है. इससे यही लगता है कि पालकों के व्यापक विरोध होने की आशंका के चलते सरकार ने गत माह मंत्रालय में पालकों के साथ होने वाली बैठक को बिना कोई कारण बताये रद्द कर दिया था. पालकों द्वारा उठायी जा रही शंकाओं व आपत्तियों को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई शैक्षणिक संस्थायें शुल्क वसूली में तानाशाही रुख अपनाती हैं. वे पालकों-पाल्य के प्रति जरा भी संवेदनशीलता नहीं दर्शाती हैं. ऐसे ही एक मामले में पुणे के संस्था संचालकों ने पालकों को सीधा धमकी भरा पत्र दिया था. पत्र में स्पष्ट कहा गया था कि फीस बढ़ाने के विरोध में यदि तुम लोगों का आंदोलन जारी रहा तो संस्था को ही बंद कर दिया जाएगा. मगर वृद्धि की गई फीस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. बताया जाता है कि यह मामला पुलिस तक गया था. ऐसे प्रकरणों के मद्देनजर फीस वृद्धि एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है और इसको लेकर विवाद निरंतर बढ़ रहा है. वहीं एक ओर अनुदानित स्कूल-कॉलेजों की शिक्षा गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की जा रही है तो दूसरी ओर अंग्रेजी माध्यम के शैक्षणिक संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मोह अभिभावकों में बढ़ता ही जा रहा है. इस मोह में सबसे अधिक जकड़ा है मध्यम वर्ग का अभिभावक, जिसका फ़ायदा शैक्षणिक संस्थान उठा रहे हैं. पिछले विधान सभा सत्र में विधान परिषद में सुरेश नवले, राजन तेली व अन्य सदस्यों ने निजी, बिना अनुदानित स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ाने का मामला उठाया था, अरुण गुजराती ने नए अधिनियम की जानकारी मांगी थी. सदस्यों के सवाल के जवाब में स्कूली शिक्षा राज्यमंत्री फौजिया खान ने कहा था कि फीस बढ़ाने के बाबत सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और उसी का हवाला देकर स्कूल प्रशासन फीस बढ़ाते हैं. सरकार ने फीस बढ़ाने के बाबत महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियम अधिनियम का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार कर लिया है और इसे मौजूदा सत्र में मंजूरी के लिए रखा जाएगा. उन्होंने कहा था कि प्राइवेट, बिना अनुदानित स्कूलों को फीस बढ़ाने की मंजूरी पहले स्कूल स्तर पर पीटीए (पैरेंट्स टीचर एसोसिएशन) से लेनी पड़ेगी. स्कूल की वार्षिक बैठक में फीस बढ़ाने का मसौदा रखना होगा. बैठक में किसी तरह का विवाद हुआ तो विभागीय स्तर पर बनाई गई समिति में चर्चा होगी. फिर भी मामला नहीं सुलझा तो राज्य स्तर पर बनाई गई समिति में फीस बढ़ाने का मामला रखा जाएगा. राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तर पर बनाई गई समिति ने दोषी पाया, तो उस स्कूल संचालक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा सकती है या फिर एक से तीन साल की सजा का प्रावधान है. यानी फीस बढ़ाने का कोई भी निर्णय स्कूल प्रबंधन अकेले नहीं कर सकेगा.

पत्र में साफ़ कहा गया था कि फीस बढ़ाने के विरोध में यदि तुम लोगों का आंदोलन जारी रहा तो संस्था को ही बंद कर दिया जाएगा. मगर वृद्धि की गई फीस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया बिहार झारखंड

दिल्ली, 27 जून-3 जुलाई 2011

www.chauthiduniya.com

फोटो-प्रभात पाण्डेय

सांसद फंड की फ़ज़ीहत

नीतीश कुमार ने अपनी दूसरी पारी में भ्रष्टाचार ख़त्म करने का ऐलान किया और इसी कड़ी में उन्होंने विधायक फंड को ख़त्म कर दिया. कहा गया कि विकास का यह पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था. सरकार के इस क़दम ने विधायकों को शक के दायरे में ला दिया और इस कारण उनमें गुस्सा भी है. उनके गुस्से को कई तरह से शांत करने की कोशिश की जा रही है.

सरोज सिंह

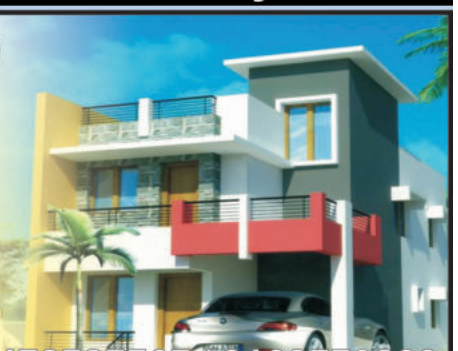

बिहार में हर जगह विकास और केवल विकास की रट लगी है. हर कोई इसके पक्ष व विपक्ष में गला फाड़ रहा है. इस आलेख में हम सिर्फ़ विकास के लिए आवश्यक ईंधन यानी फंड पर हो रही राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि ज़मीन पर विकास की सच्चाई बिल्कुल अलग विषय है. विकास के कामों का सेहरा अपने माथे पर बांधने में नीतीश सरकार अव्वल रही है. विपक्ष लाख कहे कि पैसा तो केंद्र सरकार का है पर एनडीए की सरकार यह मानती है कि सूबे में बनी सड़कों में लगा सारा पसीना नीतीश सरकार ने ही बहाया है. जनता को वर्षों बाद चलने के लिए अच्छी सड़क मिली तो इसने भी एनडीए के दावों को सही माना और नीतीश कुमार को दोबारा बिहार का ताज सौंप दिया.

अपनी दूसरी पारी में नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार ख़त्म करने का ऐलान किया और इसी कड़ी में उन्होंने विधायक फंड को ख़त्म कर दिया. कहा गया कि विकास का यह पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था. सरकार के इस क़दम ने विधायकों को शक के दायरे में ला दिया और इस कारण उनमें गुस्सा भी है. उनके गुस्से को कई तरह से शांत करने की कोशिश की जा रही है. विधायक फंड की जगह एक वैकल्पिक योजना मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना तैयार की गई है. माना जा रहा है कि इस योजना में विधायकों को कुछ फ़ैसले लेने की छूट रहेगी. सरकार को उम्मीद थी कि विधायक फंड ख़त्म करने का उसका फ़ैसला देश भर में सराहा जाएगा और बिहार का अनुसरण करते हुए अन्य राज्य सरकारें भी इस फंड को ख़त्म कर देंगी. नीतीश सरकार को यह भी उम्मीद थी कि केंद्र सरकार बिहार को उदाहरण मानते हुए सांसद फंड को ख़त्म कर देगी. पर जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सासंद फंड को लेकर राजनीति शुरू हो गई. नीतीश कुमार व सुशील मोदी ने राय दी कि चूंकि राज्य की एजेंसियों पर पहले से ही काम का बोझ ज्यादा है, इसलिए बेहतर होगा कि केंद्र सरकार अपने ही एजेंसी से सांसद फंड का काम करा ले. उन्होंने इस काम के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित करने की भी बात कही. ग्रामीण कार्य विकास मंत्री भीम सिंह की राय है कि विकास हमारी पहली प्राथमिकता है पर राज्य की ज़रूरतों का भी ख्याल केंद्र को रखना चाहिए. उन्होंने छह फीसदी सर्विस टैक्स का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बातचीत हो और बिहार व विकास के पक्ष में रास्ता निकले. जबकि विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार सरकार सांसद फंड को लेकर केवल राजनीति कर रही है और बिहार के विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है. पूर्व विधान पार्षद पी के सिन्हा कहते हैं कि अगर सांसद निधि से काम नहीं हुआ तो बिहार प्रतिवर्ष 280 करोड़ की विकास योजनाओं से वंचित हो जाएगा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार यह कहते हैं कि राज्य सरकार को इन योजनाओं का कार्यान्वयन करना है तो इसके लिए अलग से धनराशि दी जाए. जबकि सच्चाई यह है कि सांसद कोश में छह फीसदी की राशि कार्यान्वयन के लिए शामिल रहती है. यानी कि बिहार के 56 सांसदों की 280 करोड़ की राशि में छह फीसदी की दर से 16.8 करोड़ की राशि कार्यान्वयन के लिए ही होती है. सिन्हा के अनुसार संघीय ढांचे को कमज़ोर नहीं किया जाए और सांसद निधि का काम बिहार में ज़ोर शोर से शुरू हो. उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 257 के तहत केंद्र सरकार को प्राप्त शक्तियों के आधार पर राज्य सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जिनमें सांसद विकास योजनाएं भी शामिल हैं, के कार्यान्वयन को रोक ही नहीं सकती है. साफ कहें तो राज्य सरकार अगर ऐसा कोई क़दम उठाती है तो यह केंद्र सरकार से टकराव व संवैधानिक संकट के दायरे में आ जाएगा. इसी तरह राजद सांसद जगदानंद सिंह कहते हैं कि नीतीश सरकार को विकास से मतलब नहीं है वह सिर्फ़ विकास का झूठा ढिढोरा पीटने में मास्टर है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि शौचालय से लेकर सचिवालय तक में केवल और केवल उनका नाम दिखलाई दे. यही वजह है कि उन्होंने विधायक फंड ख़त्म कर दिया और अब सांसद फंड पर नज़र लगाए हुए है. सिंह कहते हैं कि जब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा ख़त्म होने लगता है तो तानाशाह का जन्म होता है. नीतीश कुमार का विधायकों व सांसदों पर से विश्वास उठता जा रहा है, जो एक तानाशाह के जन्म की परिस्थिति पैदा कर रही है. जगदा बाबू कहते हैं कि देश भर में प्रतिकिलोमीटर सड़क निर्माण का ख़र्च और बिहार में प्रतिकिलोमीटर सड़क निर्माण के ख़र्च का अंतर देख लीजिए, विकास की सच्चाई सामने आ जाएगी. उन्होंने कहा कि लूट का खेल चल रहा है और जनता को दिग्भ्रमित कर बरगलाया जा रहा है. लेकिन जनता जाग रही है और पाप का घड़ा जल्द ही फूटेगा. भाजपा सांसद भोला प्रसाद सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार में विचारधारा की आत्मा नहीं है वह परिस्थति विशेष में भिन्न भिन्न आकृति ग्रहण करते हैं. अपनी बात पर टिके रहने की आदत इनमें नहीं है. सांसद निधि को लेकर झमेला बेवजह खड़ा किया जा रहा है. आखिर इस पैसे से बिहार की ही सड़कें तो बनेंगी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शनि देव हैं और सुशील मोदी सोम देव. इन दोनों देवों को परमात्मा सही ज्ञान दें यही कामना है. सांसद उपेंद्र कुशवाह का आरोप है कि सांसद फंड का बवाल राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है. सांसद अगर अपने क्षेत्र में काम करवाएंगे तो विधायकों का गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ेगा क्योंकि उनका फंड ख़त्म हो चुका है. नीतीश कुमार बस इस गुस्से से बचना चाह रहे हैं. काम का बोझ व सर्विस टैक्स सब बहाना है.

कुशवाहा का आरोप है कि केवल अपना नाम चमकाने के लिए सांसद निधि के उपयोग पर बहाने बनाए जा रहे हैं. इसी तरह राजद सांसद रामकृपाल यादव कहते हैं कि पैसा-पैसा की रट लगाने वाली यह सरकार सांसदों का 280 करोड़ क्यों नहीं लेना चाहती है. एक तरफ वह कहती है कि केंद्रीय एजेंसियां अच्छा काम नहीं कर रही है और दूसरी तरफ यह कहती है कि सांसद निधि का काम केंद्रीय एंजेंसियों से करवा लिया जाए. यह दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है. साफ़ है कि सरकार की नीयत में ही खोट है जिसका खामियाजा बिहार की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

नेता जी कहिन

बिहार के विकास से समझौता करने का तो सवाल ही नहीं है. यही हमारा संकल्प भी है और सपना भी. राज्य की एजेंसियां काम से लदीं हैं, इसलिए सांसद निधि का काम केंद्रीय एजेंसियां ही करें तो बेहतर. *- नीतीश कुमार*

विकास हमारी पहली प्राथमिकता है पर राज्य की ज़रूरतों का भी ख्याल केंद्र को रखना चाहिए. हम चाहते हैं कि बातचीत हो और विकास के पक्ष में रास्ता निकले. *- भीम सिंह, मंत्री,ग्रामीण कार्य विभाग*

बिहार सरकार सांसदों का 280 करोड़ क्यों नहीं लेना चाहती है. वह कहती है कि केंद्रीय एजेंसियां अच्छा काम नहीं करती, दूसरी तरफ कहती है कि सांसद निधि का काम केंद्रीय एंजेंसियों से करवा लिया जाए. यह दोहरा मापदंड है. *- रामकृपाल यादव, सांसद*

नीतीश कुमार चाहते हैं कि शौचालय से लेकर सचिवालय तक केवल और केवल उनका नाम दिखाई दे. यही वजह है कि उन्होंने विधायक फंड ख़त्म कर दिया और अब सांसद फंड पर नज़र लगाए हुए हैं. *- जगदानंद सिंह , सांसद*

सांसद अगर अपने क्षेत्र में काम करवाएंगे तो विधायकों का गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ेगा क्योंकि उनका फंड ख़त्म हो चुका है. नीतीश कुमार बस इस गुस्से से बचना चाह रहे हैं. काम का बोझ व सर्विस टैक्स सब बहाना है. *- उपेंद्र कुशवाहा, सांसद*

नीतीश कुमार शनि देव हैं और सुशील मोदी सोम देव. इन दोनों देवों को परमात्मा ज्ञान दे, यही कामना है. सांसद निधि का पैसा बिहार में ही ख़र्च होगा, कोई दूसरे लोक में नहीं. *-भोला प्रसाद सिंह, सांसद*

नीतीश कुमार कहते हैं कि राज्य सरकार को इन योजनाओं का कार्यान्वयन करना है तो अलग से धनराशि दी जाए. जबकि सच्चाई यह है कि सांसद कोष में छह फ़ीसदी की राशि कार्यान्वयन के लिए शामिल रहती है. *- पी के सिन्हा, पूर्व विधान पार्षद*

मीटर रीडिंग का कार्य इपभोक्ताओं की मांग को अनसुना कर प्रति माह न करके 6 माह से लेकर 2 वर्ष की लम्बी अवधि पर किया जाता है.

एक नज़र

पटना प्रक्षेत्र में दिव्या प्रथम

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बारहवीं की परीक्षा में ज्ञान भारती आवासीय परिसर बोधगया की छात्रा दिव्या, क्रमांक 7607559 नें 96.8 प्रतिशत अंक लाकर पटना प्रक्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया. दिव्या को विद्यालय के चेयरमैन गोपाल शरण सिंह , निदेशक रोमित कुमार, प्रधानाचार्य विनोद कुमार भारद्वाज, उप प्राचार्य राजीव कुमार एवं समस्त विद्यालय परिवार ने बधाई दी है और उसके मंगलमय भविष्य की कामना की है. दिव्या की उपलब्धि पर शहर के विभिन्न संगठनों की ओर से लगातार सम्मान किया जा रहा है.

काजल सिन्हा को अवार्ड मिला

सुधा दूध के बेहतर वितरण तथा लक्ष्य से अधिक उपलब्धि के लिए गया शहर के सुधा दूध के वितरक काजल सिन्हा को काम्फेड की ओर से सम्मानित किया गया है. गत दिन पटना के एस के मेमोरियल हाल में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें एवार्ड देकर सम्मानित किया. मगध डेयरी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस उपलब्धि पर काजल सिन्हा को बधाई दी है. *- सुनील सौरभ*

पिंटू सिंह तीसरी बार जीते

इस बार के चुनाव में जहां एक तरफ सत्ता विरोधी लहर चल रही थी एवं इस बयार में कई निवर्तमान मुखिया ने अपनी कुर्सी गंवा दी. वहीं वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के पेहियार पंचायत के मुखिया शिवकुमार सिंह उर्फ मन्टु सिंह ने लगातार तीसरी बार बाजी मार ली है. इस सम्बन्ध में मुखिया जी ने कहा कि वह पंचायत को एक आदर्श पंचायत का रूप देना चाह रहे हैं, जहां हर किसी को पक्का मकान पेयजल, रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध होगी एवं जानवरों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध कराने के लिए भी वह सरकार से पत्राचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत अपराध मुक्त पंचायत बनने को अग्रसर है. दूसरी तरफ गांव के कई लोगों ने बताया कि मुखिया जी की आयु लगभग 40 वर्ष हो चुकी है अत: मुखिया जी को अब शादी कर लेनी चाहिए. *- चौथी दुनिया ब्यूरो*

मोतिहारी नगर परिषद

अवैध उगाही ज़ोरो पर

एन. एच पर सरपट दौड़ लगाने वाले मालवाहक वाहनों का ब्रेक मोतिहारी के छतौनी चौक व कुंवारी देवी चौक के पास लगना निश्चित है. भले ही इन वाहनों का गंतव्य स्थल दूसरा ज़िला अथवा नेपाल हो, लेकिन मोतिहारी से गुजरते हुए इन दो स्थलों में कहीं एक जगह इनसे पार्किंग टैक्स वसूला जाता है. जबकि नियमानुसार नगर परिषद् क्षेत्र में लोड-अनलोड होने वाले वाहनों से ही पर्किंग टैक्स लिया जाना है. नवनिर्वाचित उपसभापति मोहिबुल हक की मानें तो ठेकेदार द्वारा दो स्तरों पर गड़बड़ी की जा रही है. पहला यह कि मोतिहारी में लोड-अनलोड नहीं लेने वाले गाड़ियों से यह टैक्स जबरन वसूला जा रहा है. दूसरा ट्रक के लिए निर्धारित शुल्क 40 रुपए की जगह 50 रुपए व ट्रैक्टर के लिए निर्धारित शुल्क 15 रुपए की जगह 25 रुपए वसूला जा रहा है. बकौल हक यह आश्चर्यजनक है कि लंबे अरसे से गड़बड़ी करने वाले ठेकेदार को ही फिर से ठेका क्यों दे दिया गया है? यही नहीं बल्कि मार्च में टेंडर हुआ और मई बीतने के बाद भी उक्त ठेकेदार के यहां नप का दो लाख से अधिक बकाया है. उन्होंने कहा कि जांच के लिए गठित कटी की बात कोई नहीं सुन रहा है. लिहाजा वे जांच कमेटी की सदस्यता छोड़ने की पेशकश बोर्ड की बैठक में कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि कार्यभार संभालते ही वे मामले की जांच कर टेंडर कैंसिल करने का प्रयास करेंगे. ट्रक ड्राइवर ओमप्रकाश बताते है कि वे सोन सैन्ड लेकर बेतिया जा रहे थे. जबरन एन एच पर गाड़ी रोककर 50 रुपए की रसीद थमा दी गई. विरोध किया तो मारपीट हुई. शिकायत करने जब छतौनी थाना गया तो भगा दिया गया. थाना में गाली देकर कहा गया कि पैसा जब गाड़ी मालिक व पार्टी देता है तो तुम्हे क्या दिक्कत है? यह घटना इक्के-दुक्के वाहनों के साथ नहीं बल्कि मोतिहारी एन एच से गुजरने वाले हरेक मालवाहक वाहनों के साथ होती है. हालांकि छतौनी व मुफसिल थानाध्यक्ष इस तरह की घटना से इंकार करते हैं. मुफसिल थानाध्यक्ष रवि कुमार ने कहा कि इस तरह की शिकायत मिलने के बाद पुलिस कप्तान के निर्देश पर एन एच पर कड़ी नज़र रखी जा रही है. भले ही पुलिस जो कहे लेकिन सच्चाई यही है एन एच के अलावा शहर में भी अवैध उगाही जारी है, जहां निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली हो रही है. शहर के तीनों थानों, नगर थाना, छतौनी थाना व मुफसिल थाना इस मामले में मूकदर्शक की भूमिका में हैं. यही कारण है कि 4 जून को संपन्न बोर्ड की बैठक में अवैध उगाही का मुद्दा पूरी तरह छाया रहा. पार्षदों के अलावा मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने भी इसपर चिंता व्यक्त की. नप सभापति प्रकाश अस्थाना को पार्षदों के कड़े तेवर के मद्देनजर यह आश्वासन देना पड़ा कि एक सप्ताह के अंदर निर्धारित स्थलों पर निर्धारित शुल्क का बोर्ड लगा दिया जाएगा. साथ ही बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि अवैध उगाही को रोकने के लिए डी एम व एसपी को पत्र लिखा जाएगा. इस बाबत एस पी गणेष कुमार ने पूछने पर बताया कि नगरपालिका की मंशा अगर अवैध उगाही को रोकना होता तो निर्धारित स्थलों पर बोर्ड लगवाने के लिए सात दिन की क्या आवश्यकता है? यह काम महज 24 घंटे में हो सकता है. दूसरी जो समस्या है वह यह कि वाहन मालिक या ट्रक ड्राइवर थाने में कम्पलेन नहीं करना चाहते. पुलिस स्वत: कार्रवाई करती है तों कोर्ट तक जाते-जाते यह मामला काफी हल्का हो जाता है. कुल मिलाकर यहीं कहा जा सकता है कि उगाही रोकने के लिए नगरपालिका, नागरिक व पुलिस को सम्मिलित प्रयास करना होगा.

मोहीबुल हक

अमिता कुणाल
feedback@chauthiduniya.com

भूमि निबंधन राजस्व में करोड़ों का घोटाला

राज्य की सुशासन सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लाखों उपाय बताए लेकिन बेलगाम हो चुके भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाना लगता है सरकार के वश की बात नहीं रही है, तभी तो भ्रष्टाचार के संबंध में नित्य नये-नये खुलासे सामने आ रहे हैं. वर्तमान में सीमांचल के पूर्णिया किशनगंज कटिहार, अररिया ज़िले में ज़मीन निबंधन शुल्क में बड़े पैमाने पर करोड़ों का सरकारी राजस्व गबन का मामला सामने आया है. यहां निबंधन कार्यालय द्वारा शहरी क्षेत्र की भूमि को ग्रामीण क्षेत्र की भूमि, सड़क किराने की भूमि को सड़क से 300 फीट दूर की भूमि, भवन निर्मित आवसीय भूमि को खाली, आवासीय भूमि को खेती योग्य भूमि दिखा धड़ल्ले से निबंधन कार्यालय द्वारा निबंधन कराया जा रहा है. सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार की भूमि के निबंधन से पहले निबंधक पदाधिकारी द्वारा स्थल जांच का प्रावधान है लेकिन सीमांचल के पूर्णिया किशनगंज ज़िले में निबंधक कार्यालय के कर्मी जांच के कोरम को पूरा करने के कार्य करते हैं. बताया जाता है कि पूर्णिया, किशनगंज में निबंधन शुल्क में बरती जाने वाली धांधली का खेल काफी लम्बे समय से खेला जा रहा है जिस खेल में अंचल अधिकारी कार्यालय के कर्मी भी शामिल हैं. इनके द्वारा शहरी क्षेत्र के मकान बने भूमि को खाली भूमि व शहरी आवासीय भूमि को खेती की भूमि बता निबंधन करा दिया जाता है. ऐसे अनेकों मामले नजर आ जायेंगे जिसे सड़क से हजार फीट दूर तक बता निबंधन कराया गया है. ऐसा ही एक मामला किशनगंज में प्रकाश में तब आया जब नगरपालिका किशनगंज के अन्तर्गत ठेकसरा मौजा थाना नं. 44, पुराना वार्ड नं. 17 नया वार्ड नं. 5 (4) खाता नं. 55 खेसरा नं. 283/501 नगरपालिका सर्वे खाता नं. 73 नगरपालिका सर्वे खेसरा नं0 281ए 282 की सड़क से 300 फीट दुर दिखाकर निबंधन कराया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंची. वहीं किशनगंज में अनेकों सरकारी भूमि का अवैध रूप से निबंधन करा लिया गया है. वहीं पूर्णिया के कसबा में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की आठ एकड़ 38 डिसमिल भूमि को ग्रामीण क्षेत्र की खेती योग्य भूमि दिखा एक हजार रुपये प्रति डिसमिल की दर से निबंधन करा दिया गया जबकि वास्तविक निबंधन शुल्क 27 हज़ार प्रति डिसमिल की दर से इसका निबंधन होना था. निबंधन शुल्क में गड़बड़ी के आलोक में पूर्णिया एवं किशनगंज के निबंधन पदाधिकारी का कहना है कि आवश्यक कर्मचारियों एवं संसाधन के अभाव में भूमि का निबंधन पूरी जांच कराने के उपरांत ही होता है ऐसे में किसी प्रकार की धांधली एवं राजस्व की क्षति का सवाल ही नहीं उठता है. वहीं किशनगंज एवं पूर्णिया के स्थानीय लोगों का कहना है कि निबंधन शुल्क में चलने वाली धांधली का खेल काफ़ी लम्बे समय से चल रहा है अगर विगत 15 से 20 साल के सारे निबंधन के केबाला और केबाला में उल्लेखित स्थल को खंगाला जाए तो चौकानेवाले परिणाम सामने आएंगे और करोड़ों रुपये सरकारी राजस्व के गबन का मामला स्वयं ही प्रकाश में आ जाएगा.

सीमांचल

यहां निबंधन कार्यालय द्वारा शहरी क्षेत्र की भूमि को ग्रामीण क्षेत्र की भूमि, सड़क किराने की भूमि को सड़क से 300 फीट दूर की भूमि, भवन निर्मित आवसीय भूमि को खाली, आवासीय भूमि को खेती योग्य भूमि दिखा धड़ल्ले से निबंधन कार्यालय द्वारा निबंधन कराया जा रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सोना सिंह बिहार के अन्ना बनेंगे

अन्ना हजारे के आंदोलन ने देश के नेताओं को एक बार फिर अनशन की ताकत का अहसास करा दिया. जिस पीढ़ी ने गांधीजी के अनशन को केवल किताबों में पढ़ा, उसने शायद पहली बार अन्ना के आंदोलन में अनशन की ताकत को महसूस किया. जदयू के युवा नेता संजीव रतन उर्फ सोना सिंह भी ऐसे ही नेताओं में हैं जिन्होंने अनशन की ताकत को जाना और जल्द ही इसे आजमाने भी जा रहे हैं. बिहार में विशेष राज्य के दर्जे के लिए चले अभियान में सोना सिंह ने नीतीश कुमार व वशिष्ठ सिंह के आशीर्वाद से अपनी पूरी ताकत झोंकी और हस्ताक्षर का आंकड़ा एक करोड़ से अधिक कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिले, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने एक अनूठी पहल की जिसका चमत्कारी परिणाम सामने आया. विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए चले हस्ताक्षर अभियान में अचानक तेजी आई और बिहार के लोग इससे जुड़ने लगे. सोना सिंह ने एक सीडी बनवाई जिससे ग्रेसी सिंह व सुदेश बेरी जैसे फिल्मी कलाकारों ने अभिनय कर लोगों को बताया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना कितना ज़रूरी है. भोजपुरी के सुपर स्टार रविकिशन ने भी अपना आग्रह इस कैसेट में किया है. सीडी में नीतीश कुमार व जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ सिंह ने भी अपना संदेश बिहार के लोगों के नाम दिया है तथा यह बताया है कि इस राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो बहुत हद तक इस राज्य की समस्याएं दूर हो जाएंगी. सोना सिंह बताते हैं कि मैं तमाम लोगों से अपील की है कि वह इस दल के बंधन को तोड़कर बिहार के हित में इस अभियान से जुड़ें. सोना सिंह ने कहा कि जल्द ही महामहिम राष्ट्रपति को एक करोड़ हस्ताक्षर सौंप दिए जाएंगे और उनसे अपील होगी कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं.

उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि महामहिम के दरबार से हमलोगों को न्याय मिलेगा पर अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वह अन्ना के रास्ते पर चलते हुए लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाएंगे. सोना सिंह ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन करेंगे जिसमें बिहार को प्यार करने वाले सारे लोग शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता इनका आंदोलन जारी रहेगा. नीतीश कुमार ने जो सपना बिहार के लिए देखा है उसे पूरा कराने के लिए वह दिन रात लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साढ़े पांच साल में बिहार को जो कायाकल्प हुआ उससे वह काफी प्रभावित हैं और चाहते हैं कि विकास का सिलसिला जारी रहे.

मोनिबा फातमा
feedback@chauthiduniya.com

छपरा

बिजली उपभोक्ता परेशान हैं

हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की शिकायत यह है कि फीडर 2 से जुड़े क्षेत्रों में बिजली का समय व निर्बाध गति से मिलना एक आवश्चर्यजनक घटना है. इनका कहना है कि यहां बिजली सोने के बाद प्राय 10-11 बजे रात में आती है और जगने से पहले काट दी जाती है. सच्चाई यह है कि दिन-रात मिलकर औसतन 4-5 घंटे मुश्किल से बिजली की आपूर्ति संभव हो पाती है.

विजयेन्द्र कुमार

संपूर्ण सारण क्षेत्र में बिजली की आंखमिचौली और विभागीय अधिकारियों की कारगुजारी से आम उपभोक्ता इलकान है. छपरा शहर के पश्चिमी क्षेत्र के उपभोक्ता बिजली के अभाव को लेकर नहीं बल्कि बिजली की आपूर्ति व्यवस्था में सौतेला व्यवहार को लेकर परेशान हैं. यहां शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है. फीडर 1 और फीडर 2 के नाम पर विद्युत आपूर्ति के मामले में फीडर 2 से जुड़े उपभोक्ताओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा है. जिसको लेकर उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बीच वर्षों पूर्व से आक्रोश है. फीडर 2 से जुड़े उपभोक्ताओं में शहर के प्रभुनाथ नगर, भगवान बाजार, काशी बाजार, रतनपुरा व गुदरी बाजार से लेकर रिविलगंज नगर पंचायत के सभी इलाके आते हैं. हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की शिकायत यह है कि फीडर 2 से जुड़े क्षेत्रों में बिजली का समय व निर्बाध गति से मिलना एक आवश्चर्यजनक घटना है. इनका कहना है कि यहां बिजली सोने के बाद प्राय 10-11 बजे रात में आती है और जगने से पहले काट दी जाती है. सच्चाई यह है कि दिन-रात मिलकर औसतन 4-5 घंटे मुश्किल से बिजली की आपूर्ति संभव हो पाती है. बिजली की अनियमित आपूर्ति को लेकर बिल जमा करने में उपभोक्ता में हमेशा उदासीनता बनी रहती है. जबकि विभाग का मानसिकता यह है कि उपभोक्ताओं को हर हालत में 40 यूनिट ख़र्च करना है और 40 यूनिट का शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना है. ग़ौरतलब है कि मीटर रीडिंग का कार्य उपभोक्ताओं की मांग को अनसुना कर प्रति माह न करके 6 माह से लेकर 2 वर्ष की लम्बी अवधि पर किया जाता है. विगत कई वर्षों से उपभोक्ता बिजली विभाग के अधिकारियों के मनमाने रवैये से तबाह होकर कभी-कभार अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सक्षम उग्र प्रदर्शन करने को उतारू होते रहे है. छपरा शहर के पश्चिमी इलाके के फीडर 2 से जुड़े उपभोक्ताओं का मानना है कि इनके साथ विभागीय अधिकारियों का रवैया हमेशा दोयम दर्जे के नागरिक के समान रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Estd. 2000
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
- ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of Patna University & Magadh University get Practical Training.

FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday
Excellent Placement with Handsome Salary
Website : www.psfsm.com
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-6455019, Mob. : 9334107607, 9835042835, 9234729075

तालाबों को भरकर भवन बनाए जा रहे हैं

देवघर

देवघर में चारों ओर गंभीर पेयजल संकट से जनता त्राहिमाम की स्थिति में जीने को मजबूर है, अधिकांश प्राकृतिक जल स्त्रोत सूख रहे हैं, इन जलस्त्रोतों को आज बचाने की अति आवश्यकता है. जबकि यहां भू माफियाओं के साथ साथ जिला प्रशासन भी इन जल स्त्रोतों के अस्तित्व को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. बताना आवश्यक है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तालाबों को भर कर भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. परन्तु जिला प्रशासन इन आदेशों की अनदेखी कर देवघर के एक संतृप्त तालाब को भर कर जिला नियोजनालय एवं जिला खनन कार्यालय का भव्य भवन निर्माण करा रहा है. मामला जब न्यायालय पहुंचा तब तालाब के शेष भाग पर निर्माण कार्य रोक दिया गया. लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे तालाब भरने का काम जारी है. उक्त कार्यालय का भव्य भवन निर्माण कार्य राज्य के चर्चित एवं आय से अधिक सम्पत्ति मामले सहित कई घोटाले में आरोपित अभियंता पारस सिंह की देखरेख में ही हुआ है. इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से हाल ही में जिला मत्स्य विभाग के तालाब को भर कर सोलर प्लांट लगाने के लिए एक निजी कंपनी को जमीन दी गई है. जबकि उक्त सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकारी व बंजर ज़मीन आसानी से उपलब्ध हो सकती थी. हालात यह है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में शहर के दर्जन भर तालाबों को भू माफियाओं के द्वारा भर कर आवासीय कालोनी बनाया जा चुका है. प्रसिद्ध छत्तीसी तालाब भी अतिक्रमण का शिकार हो रहा है. यह सब कारनामा जिला प्रशासन के कुछ पदाधिकारियों की सहमति से ही संभव हो सका है. शेष बचे तालाबों पर भी इनकी पैनी नजर बनी हुई है. भू माफियाओं की दबंगई एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के फरमानों से आम जनता मूक दर्शक बनी हुई है. लेकिन आने वाले समय में विलुप्त हो रहे जल स्त्रोत के कारण भीषण जल संकट का सामना करना ही पड़ेगा और इस समय शायद कोई उपाय भी नहीं होगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुबोध प्रसाद ने शहर के कई तालाबों का अतिक्रमण करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ जांच एवं दंडात्मक कार्रवाई करने की दिशा में पहल की है. आश्चर्य है कि जिला प्रशासन की आंखों के सामने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं और पदाधिकारी मामले की गंभीरता से अनभिज्ञ हैं या जानबूझ कर नजर अंदाज कर रहे हैं या सबकुछ इनकी स्वीकृति से हो रहा है! यदि ऐसा है तो आम नागरिक क्या कर सकता है? यदि यही रवैया जिला प्रशासन का रहा तो शहर में एक भी तालाब नहीं बच पाएगा और लगातार बढ़ रहे जल संकट का समाधान खोजने से भी नहीं मिल पाएगा.

भूमाफ़ियाओं की दबंगई एवं ज़िला प्रशासन के पदाधिकारियों के फ़रमानों से आम जनता मूक दर्शक बनी हुई है. लेकिन आने वाले समय में विलुप्त हो रहे जल स्रोत के कारण भीषण जल संकट का सामना करना ही पड़ेगा और उस समय शायद कोई उपाय भी नहीं होगा.

रणजीत झा
feedback@chauthiduniya.com

करियर दुनिया

नौकरी का पिटारा खुल रहा है सरकारी

बिहार कर्मचारी चयन अयोग के द्वारा पहली बार स्नातक स्तरीय प्रारम्भिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है. सचिवालय सहायक, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, कनीय सांख्यिकी सहायक, सांख्यिकी संगणक तथा महिला समाज आयोजिका जैसे पदों पर इस परीक्षा के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जानी हैं. प्रारंभ में आयोग द्वारा कुल 1569 रिक्तियां घोषित थीं लेकिन बाद में इसमें लगभग 700 रिक्तियां और जोड़ दी गईं. इस तरह परीक्षा के माध्यम से 2200 से भी अधिक नियुक्तियां की जानी हैं. निश्चित ही यह बिहार के युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है. हालांकि आयोग द्वारा अभी तक इसके लिए परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गयी है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक़ अगस्त के अंतिम सप्ताह तक इनके लिए परीक्षा आयोजित किये जाने की उम्मीद है. ऐसे में अभ्यर्थियों के पास मात्र दो से ढाई माह शेष रह गए हैं. अगर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो अभ्यर्थियों को अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

क्या है नियुक्ति की प्रक्रिया

मेधासूची- लगभग पांच गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा. ये चयनित अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलत होंगे तथा मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर पदवार एवं कोटिवार मेधासूची का प्रारूप तैयार किया जायेगा. मेधासूची प्रारूप तैयार करने के पश्चात आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच एवं स्वास्थ्य जांच कराई जायेगी. तत्पश्चात अंतिम अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जाएगी.

परीक्षा का प्रारूप -

परीक्षाएं दो चारणों में ली जाएगी.

क) प्रारंभिक परीक्षा

ख) मुख्य परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा -प्रारंभिक परीक्षा में तीन पत्र होंगे.

क) सामान्य अध्ययन

ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित

ग) मानसिक क्षमता जांच

तीन पत्रों में प्रश्नों की संख्या 50-50 होगी. सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे. सही उत्तर के लिए चार अंक निर्धारित हैं, जबकि प्रत्येक ग़लत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जायेगी. परीक्षा की अवधि दो घंटा 15 मिनट की होगी. सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा.

प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जायेगी. यानी परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं. प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी.

ब) मुख्य परीक्षा- मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे

क) प्रश्नपत्र- 1) विषय हिन्दी

इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे. हिन्दी में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है लेकिन मेधा सूची के अंकों में इसे नहीं जोड़ा जायेगा. जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा.

प्रशन-पत्र-1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी होगा. इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी. प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जायेगी.

प्रशन पत्र-2 सामान्य ज्ञान से प्रश्न होंगे. इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे.

प्रश्न पत्र - 2 सामान्य ज्ञान (मुख्य) में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी.

सामान्य अध्ययन	-	प्रश्नों की संख्या 50 होगी
सामान्य विज्ञान एवं गणित	-	,,
मानसिक क्षमता जांच	-	,,

सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी या हिन्दी होगा. प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जायेगी. परीक्षा की अवधि दो घंटा 15 मिनट होगी.

रणनीति - परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे पहले सिलेबस को समझना ज़रूरी है. यह एक महत्वपूर्ण अवसर है इसलिए इसमें सफल होने के लिए सभी अभ्यर्थी एड़ी चोटी एक कर देंगे लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे. कठिन प्रतिस्पर्द्धा की वजह से किसी भी प्रश्न पत्र को कमतर नहीं आंकना चाहिए. प्रश्नों के स्तर को समझने के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आयोजित प्रश्नों को देखना ज़रूरी है. इससे टू द प्वाइंट तैयारी करने में सहायता मिलेगी. निर्धारित समय सीमा में सभी प्रश्नों का उत्तर देना आसान नहीं है. इसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है. समसामायिक घटनाओं की जानकारी को अपडेट रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र के अलावा प्रतियोगिता पत्रिकाओं की नियमित पढ़ाई ज़रूरी है. सामान्य विज्ञान में सामान्यत: मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. इसके लिए एनसीईआरटी की पुस्तक काफी सहायक है. गणित विषय से 25 प्रश्न पूछे जायेंगे. ये सामान्यत: पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्तर सबंध मूलभूत अंक गणितिय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात व समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ और हानि से प्रश्न पूछे जायेंगे. मानसिक क्षमता जांच में शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. इसमें मुख्यत: सदृश्य समानता एवं भिन्नता, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या से सबंधित प्रश्न होंगे.

कॉलेजों में शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया

इंटरमीडिएट का परिणाम आने के बाद राजधानी के सभी कॉलेजों में दाखिले के लिए मारा-मारी शुरू हो गई है. पटना तथा मगध विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में नामांकन के लिए फॉर्म मिलना शुरू हो गया है. पटना विश्वविद्यालय में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 जून निर्धारित है, जबकि एक जुलाई से नामांकन शुरू हो जायेगा. वहीं मगध वि.वि. के कॉलेजों में 30 जून तक फॉर्म जमा करने की तिथि निर्धारित है.

कला संकाय में दाखिले के लिए पटना कॉलेज छात्रों की पहली पसंद है, वहीं विज्ञान की पढ़ाई के लिए साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज और ए एन कॉलेज प्रसिद्ध हैं. लड़कियों की पसंद पटना वीमेंस कॉलेज, जेडी वीमेंस कॉलेज, मगध महिला, अरविन्द महिला कॉलेज और गंगा देवी कॉलेज है. कॉमर्स की पढ़ाई के लिए सबसे पहला ऑप्शन वाणिज्य महाविद्यालय है. इसके बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अरविंद महिला सहित अन्य कॉलेजों के नाम आते हैं.

कॉलेजों की सीट	-	
पटना कॉलेज	-	500 बीए
साइंस कॉलेज	-	300 बीएससी
वाणिज्य महाविद्यालय	-	350
बीमेंस कॉलेज	-	64 बीएससी, 280 बीए
मगध महिला कॉलेज	-	128 बीएससी, 300-बीए
बीएन कॉलेज	-	175 बीएससी, 400 बीए

अवसर

एसआई/एएसआई/आईए (स्टाफ सलेक्शन कमीशन) कर्मचारी चयन आयोग (एसएसबी) के द्वारा सेन्ट्रल पुलिस ऑर्गनाइजेशन में सबइंस्पेक्टर सीआईएसएफ में असिस्टेंट सबइंस्पेक्टर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में इंटेलीजेंस अफसर के लिए 1882 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित है

अंतिम तिथि 24 जून, परीक्षा की तिथि - 28 अगस्त, शैक्षणिक योग्यता - स्नातक या समकक्ष

अनुमेहा झा
feedback@chauthiduniya.com

सोना सिंह ने नीतीश कुमार व वशिष्ठ सिंह के आशीर्वाद से अपनी पूरी ताकत झोंकी और हस्ताक्षर का आंकड़ा एक करोड़ से अधिक कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई.

एक नज़र

समस्तीपुर के छात्र-छात्राओं ने रिकॉर्ड बनाया

सीबीएसई 10वीं परीक्षा में समस्तीपुर जिला के छात्र-छात्राओं ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए पटना रीजन में अपनी पहचान बनाई है. इस जिले के लगभग दो सौ छात्र-छात्राओं ने ग्रेड प्वाइंट 10 लाकर अपने-अपने विद्यालयों एवं जिले का मान बढ़ाया है. जवाहर नवोदय विद्यालय, बिरौली के 32 छात्रों ने ग्रेड प्वाईंट 10 लाकर पटना रीजन में अव्वल स्थान प्राप्त किया. इसी प्रकार संत जोसेफ स्कूल दल सिंह सराय के 39 छात्र-छात्राओं ने ग्रेड प्वाइंट 10 लाकर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता हासिल की. विद्यालय के निदेशक अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि उनके विद्यालय में ग्रेड टू से सफल छात्रों की संख्या 350 है. हसनपुर प्रखंड अंतर्गत प्रोग्रेसिव सेन्ट्रल हाई स्कूल के शत प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने सफलता पाई है. विद्यालय के उत्कृष्ट प्रदर्शन से उत्साहित निदेशक रामकिशोर राय ने बताया कि ए-वन में 31, 9 से 9.9 तक ग्रेड प्वाइंट लाने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या 177 है तथा शेष 205 छात्र-छात्राओं ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की है.

बच्चों का भविष्य सुधार रहा है VGI

VGI Venkateshwara GROUP OF INSTITUTIONS

बिहार के बच्चों का कैरियर बनाने में वैंकटेश्वर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है. यहां के निदेशक सुधीर ने बताया अच्छे माहौल में छात्र यहां काफी बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं. जानी-मानी विजिटिंग फैकल्टी हमेशा आती है. लाइब्रेरी की भी सुविधा होने से छात्रों को काफी मदद मिलती है. बिहार के छात्र यहां अपने घर जैसा अनुभव करते हैं. पिछले वर्ष कुल 60 से अधिक बिहार के बच्चों का प्लेसमेन्ट हो चुका है. आम बच्चों के लिए वीजीआई ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एजूकेशन लोन के लिए टाईअप किया है. बिहार एवं झारखण्ड के इच्छुक बच्चे एडमिशन के लिए बिहार कार्यालय का नम्बर 09386941721, 09334252869 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही मुख्य उद्देश्य

समस्तीपुर के शिक्षाविद् ए. कुमार के जन्मदिन के मौके पर इस वर्ष के 10+2 की परीक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले रीयल मेरिट सेन्टर एवं मॉर्डन स्टडी सेन्टर, काशीपुर के छात्र-छात्राओं को बैग, पुस्तक एवं प्रैक्टिस बुक देकर पुरस्कृत किया गया. उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए शिक्षाविद् ए. कुमार ने कहा कि बेहतर शैक्षणिक माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण इनका मुख्य उद्देश्य है जिसका परिणाम है कि काफी कम समय में ही हमारी संस्था ज़िले में लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंची है. इसके लिए उन्होंने अभिभावकों के प्रति आभार प्रकट किया. मौके पर एस. पी. सिंह, शत्रुघ्न महतो, रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सदस्य संतोष कुमार आदि ने भी छात्र-छात्राओं की हौसलाफजाई की. *- चौथी दुनिया ब्यूरो*

सुशासन की खोज में महादलित महिला

बिहार में सुशासन की सरकार है, यह सुन-सुनकर महादलित महिला शांति कुमारी के कान पक गये हैं. पिछले छह वर्षों से यह महिला न्याय के लिये दर-दर भटक रही है. 2005 में इसकी नियुक्ति शिक्षा मित्र के पद पर शेरघाटी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय, बिटी बिगहा में की गई थी. वह ग्यारह माह तक दक्षता पूर्व अध्यापन का कार्य करती रहीं लेकिन संतोषप्रद सेवा देने के बावजूद न तो नियोजन का विस्तार किया गया न ही सेवा काल के मानदेय का भुगतान किया जा सका. यह महादलित महिला प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक फरियाद कर चुकी है, लेकिन इसे अबतक न्याय नहीं मिल पाया है.

विकास योजनाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं

समस्तीपुर में चल रही विकास योजनाओं में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. योजनाओं का लाभ यदि लाभुक को नहीं मिलने की बात प्रकाश में आई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित है. उक्त बातें जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने ज़िला समन्यवय समिति की मासिक बैठक में कहीं. सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों में सभी अर्हताओं को पूरा करने वालों को यदि पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है तो संबंधित पंचायत सेवक और मुखिया पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कल्याण छात्रवृत्ति वितरण का प्रतिवेदन और आवंटन कर मांग तथा अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के तहत विभिन्न प्रखंडों में जांच प्रतिवेदन शीघ्र देने का निर्देश दिया. *- विकास कुमार*

जेल से चुनाव लड़कर मुखिया बने अशोक यादव

संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समस्तीपुर ज़िले के बिथान प्रखंड से नरपा पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया अशोक कुमार यादव ने जेल से चुनाव लड़कर मुखिया का ताज अपने नाम किया और पुलिस हिरासत में प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर बीडीओ राजीव रंजन द्वारा निर्गत निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया. प्रमाण-पत्र लेने के बाद पुलिस उन्हें फिर से रोसड़ा उपकारा वापस ले गयी. बता दें कि जेल में रहते हुए अशोक ने 500 से अधिक मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को पटखनी दी. इनकी पत्नी विभा देवी बिथान की निवर्तमान प्रखंड प्रमुख हैं जो इस बार पंचायत चुनाव से खुद को अलग रखा. *- कुतुबुद्दीन*

महिला महाविद्यालय की उपेक्षा

महनार अनुमंडल का इकलौता महिला महाविद्यालयसंस्थान जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का रोना रो रहा है. इसके प्राचार्य डॉ. प्रेमनाथ सिंह ने बताया कि एक जनप्रतिनिधि कम्प्यूटर देने की घोषणा कर वादे से मुकर गए. उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय को स्थानीय सहयोग से चलाया जा रहा है, जिससे हर साल बड़ी संख्या में छात्राएं लाभान्वित हो रही हैं. उन्होंने कहा कि अगर महनार के व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, नौकरशाह इत्यादी इस संस्थान के लिए थोड़ी सा समय निकालें तो यह महाविद्यालय एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान के रूप में पूरे बिहार में छा जाएगा. *- अंजुम परवेज*